3 राजधानी
मस्ती की पाठशाला लगाएगा एलडीए

6 अभिमत
तेजी से प्रगति करती अर्थव्यवस्था

10 बजट विशेष
रियल एस्टेट ने सराहना की

11 विदेश
मोदी को बाइडेन ने किया आमंत्रित

RNI NO.UPHIN/2010/36547
वर्ष 13 अंक 104
लखनऊ, बृहस्पतिवार, 2 फरवरी, 2023
पृष्ठ 12 मूल्य ₹ 3
लखनऊ
नगर संस्करण

लखनऊ, नई दिल्ली, रायपुर और फरीदाबाद से प्रकाशित
पायनियर
www.dailypioneer.com

सचिन ने विश्वकप विजेता टीम को सम्मानित किया
स्पोर्ट्स-12

आयकर मोर्चे पर राहत, बुजुर्गों व महिलाओं को तोहफा

आम चुनाव से पहले सरकार के अंतिम पूर्ण बजट में समाज के हर वर्ग को साधने का प्रयास

सालाना आय	नया टैक्स
0-3 लाख	कुछ नहीं
3-6 लाख	5%
6-9 लाख	10%
9-12 लाख	5%
12-15 लाख	20%
15 लाख से अधिक	30%

- सालाना स्लैब में बड़ा बदलाव
- सात लाख तक वार्षिक आय पर नहीं लगेगा कोई कर

बजट 2023-24

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

- एक अप्रैल से व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर सात लाख किया गया, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत जमा सीमा 30 लाख हुई, मासिक आय योजना में जमा सीमा नौ लाख की गई
- महिला सम्मान बचत पत्र का ऐलान, इसमें दो वर्ष के लिए दो लाख रुपए तक की बचत पर 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा

अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को पेश नरेंद्र मोदी सरकार के अंतिम पूर्ण बजट में सभी तबकों को साधने का प्रयास किया। उन्होंने जहां एक तरफ मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को आयकर मोर्चे पर राहत देने की घोषणा की, वहीं लघु बचत योजनाओं के तहत निवेश सीमा बढ़ाकर बुजुर्गों और नई बचत योजना के जरिए महिलाओं को भी सौगात दी है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे पर खर्च में 33 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि करने का भी प्रस्ताव किया है। नई कर व्यवस्था के तहत एक अप्रैल से व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर सात लाख रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की आय सात लाख रुपए है, उसे कोई कर नहीं देना होगा। अबतक यह सीमा पांच लाख रुपए है। साथ ही कर स्लैब को सात से घटाकर पांच किया गया है। साथ ही अधिभार की दर 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने के बाद कर की अधिकतम दर 42.7 प्रतिशत से घटकर लगभग 39 प्रतिशत रह जाएगी।

वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों को भी राहत दी। इसके तहत वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत जमा सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं मासिक आय योजना के तहत जमा सीमा बढ़ाकर नौ लाख रुपए की गई है। महिलाओं के लिए अलग से नई बचत योजना...महिला सम्मान बचत पत्र...की घोषणा की गई। इसमें दो वर्ष के लिए दो लाख रुपए तक की बचत पर 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। सीतारमण ने अपना पांचवां पूर्ण बजट ऐसे समय पेश किया जब वैश्विक चुनौतियों के कारण अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ रही है और सामाजिक क्षेत्रों पर खर्च बढ़ाने के साथ स्थानीय स्तर पर विनिर्माण को प्रोत्साहन बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने मोबाइल फोन कल-पुर्जों तथा हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लीथियम बैटरी और अन्य ऐसे सामान के लिए सीमा शुल्क में कटौती की भी घोषणा की। यह अगले साल अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है। अगले साल फरवरी में अंतरिम बजट यानी लेखानुदान पेश किया जाएगा। बजट में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय लगातार तीसरी बार उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया गया है। इसे 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया है जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.3 प्रतिशत बैठता है।

मुख्य बिन्दु

- लगभग नौ वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है।
- बजट की सात प्राथमिकताएं सप्तऋषि। इनमें शामिल हैं: समावेशी विकास, अंतिम छोर-अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र।
- 5जी सेवाओं पर आधारित एप्लिकेशन विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।
- सरकार अगले तीन वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को अगले तीन वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल सम्पन्न बनाने के लिए शुरू की जाएगी।
- विभिन्न राज्यों से कुशल युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
- एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीनीकृत किया गया है। यह पहली अप्रैल 2023 से कार्प्स में 9,000 करोड़ रुपए जोड़कर क्रियान्वित होगी।
- वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में अधिकतम जमा की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़कर 30 लाख रुपए हो जाएगी।
- लक्षित राजकोषीय घाटा 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से नीचे रहने का अनुमान है।
- बजट अनुमानों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4 प्रतिशत है।

क्या होगा महंगा

- सिगरेट
- किचन की चिमनी
- आयातित साइकिल और खिलौने
- पूर्ण रूप से आयातीत कारें और इलेक्ट्रिक वाहन
- नकली आभूषण
- कम्पाउंडेड रबड़
- अप्रसंस्कृत चांदी (सिल्वर डोर)
- नेफ्था

क्या होगा सस्ता

- मोबाइल फोन
- घरेलू स्तर पर विनिर्मित टीवी सेट
- झींगे का आहार
- जलीय जीवों के आहार के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाला मछली का तेल
- प्रयोगशाला में हीरों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री
- पूंजीगत माल
- इलेक्ट्रिक वाहन

देशभर में खुलेंगे 157 नर्सिंग कॉलेज

नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2023-24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में 10 हजार करोड़ की बढ़ोतरी करते हुए 89,155 करोड़ रुपये आवंटित किया है। जो 2022-23 में आवंटित की गई 79,145 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में लगभग 13 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि देशभर में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।

एकलव्य स्कूलों में 38,800 शिक्षकों की होगी भर्ती

नई दिल्ली। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और अन्य कर्मियों की भर्ती की जाएगी। शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र और इंजीनियरिंग संस्थानों में 5-जी सेवाओं का उपयोग करते हुए अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।

गरीब-मध्य वर्ग के सपने पूरे करेगा बजट : प्रधानमंत्री

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

- सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मोदी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि अमृत काल के पहले बजट ने विकसित भारत के संकल्प और गरीबों एवं मध्यम वर्ग सहित आकांक्षी समाज के सपनों को पूरा करने के लिए एक मजबूत आधार स्थापित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बधाई देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आम बजट पेश करते हुए व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा बढ़ा दी, छोटी बचत पर रियायतें दीं और पिछले एक दशक में पूंजीगत खर्च में सबसे बड़ी वृद्धि की घोषणा की है। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने पिछले वर्षों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिससे जीवन की सुगमता सुनिश्चित हुई है। प्रधानमंत्री ने 2047 के सपनों को साकार करने में मध्यम वर्ग की क्षमता को रेखांकित किया और कर की दरों में कमी के साथ-साथ प्रक्रियाओं के सरलीकरण, पारदर्शिता और गति पर भी प्रकाश डाला।

नए भारत की समृद्धि का संकल्प व अंत्योदय का विजन: योगी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम बजट 2023-24 को लोककल्याणकारी बताते हुए इसकी काफी सराहना की। सीएम ने ट्वीट कर हर वर्ग की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने वाले केंद्रीय बजट का स्वागत किया। साथ ही सर्वसमाज के हितों का ध्यान रखने के लिए प्रधानमंत्री व केंद्रीय वित्त मंत्री का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान व महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग की आशाओं और राष्ट्र के समग्र उत्थान की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला है। यह बजट नि:संदेह भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। आम बजट 2023-24 में नए भारत की समृद्धि का संकल्प है अंत्योदय का विजन है।

रेल के सफर को और आरामदायक बनाएंगे

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

- रेलवे के लिए अब तक का सर्वाधिक पूंजीगत परिव्यय, 2.40 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि 2023-24 के आम बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत परिव्यय उपलब्ध कराया गया है जो रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक पूंजीगत परिव्यय है। लोकसभा में बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि रेलवे को मौजूदा बजट प्रस्ताव में उपलब्ध कराया गया परिव्यय, 2013-14 में कुल पूंजीगत परिव्यय का लगभग 9 गुना है।

सीतारमण ने कहा कि कोयला, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए अंतिम और प्रथम-मील कनेक्टिविटी के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिसे 75,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा। इसमें 15 हजार करोड़ रुपये निजी क्षेत्र का होगा। उन्होंने कहा कि रेल में सफर करने वाले यात्रियों की बढ़ती उम्मीदों के साथ रेलवे राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, हमसफर और तेजस जैसी प्रमुख ट्रेनों के 1,000 से अधिक कोच के नवीनीकरण की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि इन कोच के आंतरिक हिस्सों को अत्याधुनिक बनाया जाएगा और यात्रियों के आराम के हिसाब से इसमें सुधार किया जाएगा।

रक्षा क्षेत्र के लिए 5.94 लाख करोड़ आवंटित

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित राशि बढ़ाकर 5.94 लाख करोड़ रुपये कर दी गई है जो पिछले साल 5.25 लाख करोड़ रुपये थी। जो पिछले बजट से 71 हजार करोड़ रुपये अधिक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में आम बजट पेश किया जिसमें पूंजीगत व्यय के लिए कुल 1.62 लाख करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं। इनमें नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य साजोसामान की खरीद शामिल है। वित्त वर्ष 2022-23 में, पूंजी परिव्यय के लिए बजटीय आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपये था, लेकिन संशोधित अनुमान के अनुसार व्यय 1.50 लाख करोड़ रुपये था। अगले वित्त वर्ष के बजट दस्तावेजों के अनुसार, राजस्व व्यय के लिए 2,70,120 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जिनमें वेतन भुगतान और प्रतिष्ठानों के रखरखाव पर होने वाले खर्च शामिल हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में राजस्व व्यय के लिए बजटीय आवंटन 2,39,000 करोड़ रुपये था।

पीएम आवास योजना के लिए 66% अधिक धन

नई दिल्ली। सभी को अपनी छत देने के सरकार के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में ऐलान किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन को 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा शहरों को शहरी नियोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्त मंत्री की ओर से यह घोषणा भी की गई कि केंद्र सरकार शहरी आधारभूत अवसंरचना विकास कोष की तर्ज पर शहरी आधारभूत अवसंरचना विकास कोष की स्थापना करेगी तथा इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। केंद्र सरकार ने शहरी आधारभूत अवसंरचना विकास कोष पर हर साल 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सीतारमण ने कहा कि सभी शहरों और नगरों में सीवरों और सेप्टिक टैंकों को मैन होल से पूरी तरह मशीन होल मॉडल पर परिवर्तित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस कोष का उपयोग सरकारी एजेंसियों द्वारा दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में अवसंरचना तैयार करने में किया जाएगा।

कृषि ऋण के लिए 20 लाख करोड़ की घोषणा

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को पेश बजट में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को 11 प्रतिशत बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की। कृषक समुदाय को रियायती दरों पर अधिक कृषि कर्ज देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 का बजट पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की नई उप-योजना 6,000 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश के साथ शुरू की जाएगी, ताकि मछुआरों, मछली विक्रेताओं और सूक्ष्म और लघु उद्यमों की गतिविधियों को और प्रभावी बनाने, मूल्य श्रृंखला क्षमता में सुधार के साथ मत्स्यपालन के लिए बाजार का विस्तार किया जा सके। उन्होंने कहा कि समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झींगा मछली के चारे के घरेलू विनिर्माण के लिए प्रमुख लागतों पर सीमा शुल्क भी कम किया जाएगा।

बाजार

सेंसेक्स	59,708	↑	158	
निफ्टी	17,616	↓	45	
सोना	57,830	↑	640	/10g
चांदी	70,059	↑	1230	/kg

क्विक न्यूज

अडाणी एंटरप्राइजेज ने एफपीओ वापस लिया

नई दिल्ली। अडाणी एंटरप्राइजेज ने बुधवार को अपने 20 हजार करोड़ रुपए के अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ) को वापस लेने और निवेशकों का पैसा लौटाने की घोषणा की। हालांकि, कंपनी के एफपीओ को मंगलवार को पूर्ण अभिदान मिल गया था। समझा जाता है कि अडाणी एंटरप्राइजेज ने यह कदम अमेरिका की शॉर्टसेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उठाया है। बीएसई के आंकड़ों के अनुसार, अडाणी एंटरप्राइजेज के एफपीओ के तहत 4.55 करोड़ शेयरों की पेशकश की गई थी, जबकि इसपर 4.62 करोड़ शेयरों के लिए आवेदन मिले थे। गैर संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित 96.16 लाख शेयरों पर करीब तीन गुना बोलियां मिली थीं। वहीं पात्र संस्थागत खरीदारों के खंड के 1.28 करोड़ शेयरों पर पूर्ण अभिदान मिला था।

भाजपा ने सराहा, विपक्ष बोला-जनता की उम्मीदों पर आघात

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने केंद्रीय बजट को जनता की उम्मीदों के साथ विश्वासघात करार दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने दावा किया वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए गए केंद्रीय बजट ने देश के ज्यादातर लोगों को निराश किया है। यह जनता की उम्मीदों पर आघात है। उन्होंने एक बयान में कहा कि बजट और वित्त मंत्री का बजट भाषण यह प्रदर्शित करता है कि जनता, उसके जीवन, आजीविका तथा अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई से सरकार कितनी अनजान है। चिदंबरम ने दावा किया कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बेरोजगारी, गरीबी और असमानता जैसे शब्दों का कहीं उल्लेख नहीं किया। शुक्र है कि उन्होंने गरीब शब्द का उल्लेख दो बार किया। मुझे यकीन है कि भारत के लोग इसका संज्ञान लेंगे कि सरकार को किन लोगों की चिंता है और किन लोगों की नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार की ओर से अनुमानित जीडीपी (वास्तविक मूल्यों पर आधारित) 232,14,703 करोड़ रुपए बताई गई थी और 11.1 प्रतिशत की विकास दर का अनुमान लगाया गया था। वहीं, वर्ष 2022-23 के लिए 258,00,000 करोड़ रुपए की जीडीपी का अनुमान लगाया गया था। मौजूदा बजट में सरकार ने 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान 273,07,751 करोड़ रुपए का लगाया है। इस तरह, वास्तविक मूल्यों पर आधारित जीडीपी दोगुनी होनी चाहिए थी, जबकि वित्त मंत्री (निर्मला सीतारमण) द्वारा और आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि जीडीपी की वृद्धि दर सात प्रतिशत रही। सरकार को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। चिदंबरम ने इसे संवेदनहीन बजट बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि बजट भारतीय जनता पार्टी पर जनता के लगातार गिरते विश्वास का सबूत है तथा इसे सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बजट में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के संदर्भ में कोई समाधान ढूंढने का प्रयास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मनरेगा का बजट 38,468 करोड़ रुपए कम कर दिया, तो गरीबों का क्या होगा? कुल-मिलाकर मोदी सरकार ने जनता का जीवन दुश्वार किया है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट को मित्रकाल बजट करार देते हुए कहा कि इससे साबित होता है कि सरकार के पास भारत के भविष्य के निर्माण की कोई रूपरेखा नहीं है।

- राहुल गांधी ने करार दिया मित्रकाल बजट, चिदम्बरम ने सरकार को बताया जमीनी हकीकत से अनजान
- खड़गे, ममता, अखिलेश, मायावती, बीआरएस के केशव राव ने कहा- बेरोजगारी, महंगाई से निपटने के लिए कुछ नहीं

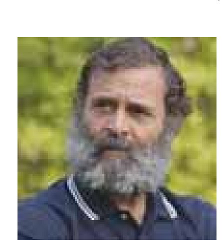

अमृत काल की मजबूत आधारशिला : शाह

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

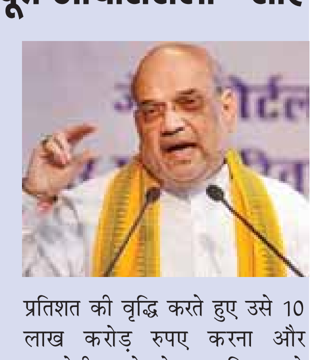

केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए इसे दूरदृष्टिपूर्ण और अमृत काल की मजबूत आधारशिला बताया है। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह बजट सर्वसमावेशी और दूरदर्शी है और यह आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति देगा। वित्ता मंत्री द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद शाह ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया बजट-2023 अमृतकाल की मजबूत आधारशिला रखने वाला है। पूंजीगत व्यय में 33 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए उसे 10 लाख करोड़ रुपए करना और राजकोषीय घाटे को 5.9 प्रतिशत रखे जाने के लक्ष्य की सराहना करते हुए शाह ने कहा कि यह केंद्र सरकार की सशक्त बुनियादी ढांचे और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले नए भारत बनाने की दूरदर्शिता को दर्शाता है।

विज्ञापन जारी करने के नौ साल बाद हुई प्रधानाचार्यों की नियुक्तियां रद

लखनऊ (विधि संवाददाता)। वर्ष 2013 की विज्ञापन संख्या 3 के क्रम में प्रदेश भर के इंटर कॉलेज और हाई स्कूलों में की गई नियुक्तियों को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रद् कर दिया है। पीठ ने कहा है कि नौ वर्ष पहले जारी किए गए विज्ञापन के क्रम में अब नियुक्तियां करना संविधान में प्रदत्त लोक नियोजन में समान अवसर और विधि के समक्ष समता के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। पीठ ने नियुक्तियों को रद् करने के साथ ही नये सिरे से नियमानुसार नियुक्तियों की प्रकिया जल्द पूरी करने का आदेश भी दिया है। जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह आदेश कमेटी ऑफ मैनेजमेंट इंटर कॉलेज, नतौली की याचिका समेत 29 याचिकाओं पर दिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील पाठक ने बहस की। उनका कहना था कि वर्ष 2013 में विज्ञापन संख्या 3 जारी करते हुए प्रधानाचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी।

देश के सर्वांगीण विकास को शक्तिशाली करने वाला है बजट

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने आज संसद में प्रस्तुत आम बजट 2023.24 पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आजादी के अमृत काल का यह पहला बजट देश के सर्वांगीण विकास को शक्तिशाली करने वाला बजट है। इस बजट में ध्यान रखा गया है कि गरीब, मध्यम वग, किसान आगे बढ़ने का हौंसला रखने वाला समाज अपने सपनो को पूरा कर सके। देश का मेहनतकश जो भारत के निर्माण की नीव है, ये बजट उनके हौंसलों को साकार करने वाला है। उन्होंने कहा बजट में महिलाओंए श्रमिकों, नौकरीपेशा लोगो, शिक्षा सुविधाओं में बढ़ोत्तरी जैसे कई आवश्यक क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है जो विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखेगा। यह एक दूरगामी और सबको समाहित करने वाला बजट है। बजट का स्वागत करते हुए राज्यपाल ने देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है।

गरीब कल्याण को समर्पितः पाठक

लखनऊ। केंद्र की भाजपा सरकार ने शानदार बजट प्रस्तुत किया है। अमृतकाल का यह पहला बजट गरीब कल्याण को समर्पित है। विकसित भारत के संकल्प को यह बजट पूरा करेगा। बजट में हर वर्ग को लाभ प्रदान किया गया है। नौकरी पेशे से लेकर बिजनेस क्लास को फायदा मिलेगा। किसानों को भी आशातीत फायदा मिलेगा। छूट भी प्रदान की गई है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार बेहतर काम कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी वर्ग व समूहों का खयाल रखते हुए आम आदमी का बजट प्रस्तुत किया है। अमृतकाल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जन भागीदारी सबका साथ सबका विकास पर जोर किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में महिलाओंए बुजुर्ग छात्रों और किसानों को विशेष छूट प्रदान की गई है। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि टैक्स स्लैब में तब्दीली की गई है। सात लाख तक की इनकम को कर मुक्त घोषित किया गया है। टैक्स स्लैब में परिवर्तन की लंबे समय से देश व प्रदेश की जनता राह देख रही थी। इससे आम आदमी को सीधे फायदा होगा।

आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करने वालाः खन्ना

लखनऊ। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बजट को सर्वहितकारी एवं सर्वसमावेशी बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करने वाला बजट है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रस्तुत इस बजट ने हिंदुस्तान की जनता का दिल जीता है। बजट में किसानों, नौजवानों, महिलाओं, गरीब, नौकरीपेशा, व्यापारी सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि बजट के माध्यम से मध्यम वर्ग एवं वेतन भोगी वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी गई है। इससे लोगों की क्रयशक्ति बढ़ेगी और मांग सृजित होगी जिससे उद्योगों को गति मिलेगी और रोजगार सृजन बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट है। श्री खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश को केंद्रीय करों में राज्यांश के रूप में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 146498.76 करोड रुपए मिलने का अनुमान था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित आंकड़ों के अनुसार अनुमानतः 169745.30 करोड़ रुपए मिलेगा जो मूल अनुमान से 23246.54 करोड़ रुपए अधिक है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 में 183237.59 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार से मिलने का अनुमान है जो वर्तमान वित्तीय वर्ष के अनुमान से 37000 करोड़ रुपए अधिक है। स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में राज्यों को पूंजीगत कार्य में सहायता के लिए 50 वर्षीय ब्याज रहित ऋण दिए जाने की घोषणा की गई थी तथा इसके लिए एक लाख करोड़ रूपए का प्राविधान केंद्रीय बजट में किया गया था। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश को 14351 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे जिसके सापेक्ष अब तक 7654.57 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं।

विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखेगा

लखनऊ। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केन्द्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि गाँव, गरीब, किसान, नौजवान, महिला सशक्तीकरण को समर्पित एवं आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने वाला भारत को विश्व में नंबर एक अर्थ व्यवस्था बनाने को अग्रसर करने वाला बजट है। मौर्य ने कहा है कि डिजिटल इंडिया वाला मेक इन इंडिया को आकर्षित करने वाले बजट में ग़रीबों के साथ मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना और रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी व जलमार्ग के साथ पर्यटन उद्योग व कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने वाला बजट है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 66फीसदी बढ़ोतरी की गयी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सामाजिक न्याय, समानता और समान अवसर की अवधारणा को चरितार्थ करने वाला बजट है। गरीबों को मजबूत व शक्तिशाली बनाने वाला बजट है।कहा कि बजट विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखेगा। बजट में वैकल्पिक उर्वरकों को प्रोत्साहन देने के लिए पी एम प्रणाम योजना की शुरुआत की गयी है। बजट की बात प्राथमिकताएं हैं जो सप्तऋषि की तरह अमृतकाल के दौरान हम सबका मार्गदर्शन करेंगी।

इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सस्टेनेबल ग्रोथ का मार्ग प्रशस्त करेगाः नन्दी

लखनऊ। प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने कहा कि आम बजट 2023 सर्वस्पर्शी, सर्व-समावेशी एवं जन-जन के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट है। यह बजट देश के 130 करोड़ लोगों का बजट है। उनकी सहूलियत, रोजमर्रा की जरूरतों और सुरक्षित भविष्य का मजबूत खाका इस बजट में मौजूद है। खासकर कि मध्यम वर्ग और टैक्स पेयर्स का विशेष ध्यान रखा गया है। यह बजट देश के औद्योगिक विकास, सुरक्षित निवेश और इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सस्टेनेबल ग्रोथ का मार्ग प्रशस्त करेगा, युवाओं के लिए रोजगार सृजन, किसानों की चिंता, महिलाओं के सशक्तिकरण की स्पष्ट झलक इस बजट में समाहित है।

किसानों, महिलाओं, देश की गरीब जनता के लिए कल्याणकारीः जयवीर सिंह

लखनऊ। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि बजट को किसानों, महिलाओं, देश की गरीब जनता के लिए कल्याणकारी बताते हुए कहा है कि यह बजट उभरते भारत की नई तस्वीर है। बजट में महिलाओं, श्रमिकों, नौकरीपेशा के साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, अवस्थापना सुविधाओं पर विशेष जोर दिया गया है। इसके साथ ही रेल बजट में वित्तीय वर्ष 2013-14 की तुलना में 9 गुना बढ़ोत्तरी की गयी है। इससे असेवित क्षेत्रों तक रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है कि इस बजट में सभी सेक्टरों को काफी तरजीह दी गई है। जयवीर सिंह ने कहा है कि इस बजट के प्राविधानों से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण एवं शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ ही कृषि एवं औद्योगिक सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है।

देश की अर्थव्यवस्था और गतिशील व विकासोन्मुखी होगीः धर्मपाल सिंह

लखनऊ। पशुधन एवं दुग्ध विकास, राजनैतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज तथा नागरिक सुरक्षा विभाग के मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि बजट को सर्वस्पर्शी एवं जन कल्याणकारी बताते हुए कहा कि इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था और अधिक गतिशील व विकासोन्मुखी होगी। बजट में किसानों, महिलाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, औद्योगिक तथा अवस्थापना विकास पर विशेष बल दिया गया है। जिससे रोजगारसृजन के साथ ही ग्रामीण एवं शहरी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और देश को आत्मनिर्भर बनाने का स्वप्न साकार होगा। पशुधन मंत्री ने डेयरी सेक्टर पर विशेष ध्यान दिये जाने पर देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हार्दिक बधाई दी।

ओडीओपी योजना का होगा पूरे देश में विस्तारः राकेश सचान

लखनऊ। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, रेशम, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग तथा खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने कहा कि महिला, गांव, गरीब और किसानों को प्राथमिकता दी गई है। इस बजट में खासतौर से श्रमिकों एवं मध्यम वर्ग का ख्याल रखा गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की बजट में किये गये प्राविधान से प्रदेश की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। प्रदेश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर होगा। सचान ने एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना को पूरे देश में विस्तार देने के लिए प्रधानमंत्री व वित्तमंत्री को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी इस योजना को पूरे देश में लागू करने से व्यापक स्तर पर रोजगार का सृजन होगा और देश व प्रदेश की जीडीपी बढ़ाने में मदद मिलेगी। ओडीओपी योजना के तहत यूनिटी मॉल खोलने, एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना तथा पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना से हस्तशिल्पियों, पारंपरिक कारीगरों एवं उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

पुरानी पेंशन बहाली की उम्मीद थी जिस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया

लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया बजट बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी एवं आर्थिक मंदी के दौर में आम जनमानस के लिए निराशाजनक है। इस बजट से देश के लोगों को बहुत उम्मीद थी, रोजगार के ठोस अवसर परिलक्षित नहीं हो रहे, सरकारी सेवकों को इस बजट में पुरानी पेंशन बहाली की केंद्र सरकार से उम्मीद थी जिस पर सरकार का किसी भी प्रकार का कोई ध्यान ना देना अत्यंत निराशाजनक एवं दुर्भाग्यपूर्ण प्रतीत हो रहा है। डायरेक्ट टैक्स में किए गए संशोधन, कुछ हद तक संतोषजनक है किंतु सरकार इसमें और बेहतर कर सकती थी। अंततः यही कहा जा सकता है कि चाहे सरकारी कर्मचारियों का मामला हो अथवा आम जनमानस का किसी भी दृष्टिकोण से उत्साह जनक नहीं कहा जा सकता है।

केन्द्रीय बजट में सशक्त-समृद्ध नए भारत के निर्माण का संकल्प स्पष्ट दिखाई देता है

लखनऊ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने आजादी के अमृतकाल के आम बजट 2023-24 को सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, गरीबों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग के हितों को पूरा करने वाला बजट बताया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने आजादी के अमृतकाल में प्रस्तुत नवभारत के संकल्प को समर्पित, लोकहित एवं जनकल्याणकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का आभार एवं अभिनंदन व्यक्त किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केन्द्रीय बजट 2023-24 में सशक्त-समृद्ध नए भारत के निर्माण का संकल्प स्पष्ट दिखाई देता है। केन्द्रीय बजट की सात प्राथमिकताएं है जो सप्तऋषि की तरह अमृतकाल में भी नए भारत की समृद्धि एवं देश को आर्थिक मोर्चे पर महाशक्ति बनाने में हमारा मागदर्शन करेगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने बजट को सशक्त व समृद्ध भारत की तस्वीर बताते हुए कहा कि इसमें 130 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं और हितों को ध्यान में रखा गया है। मोदी सरकार द्वारा लाया गया बजट 2023 में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के स्वप्न को पूरा करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

कुछ नया नहीं, पार्टी से ज्यादा देश के लिए होता तो बेहतरः मायावती

लखनऊ। देश के आम बजट को लेकर बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर कहा कि इस वर्ष का बजट भी कोई ज्यादा अलग नहीं। पिछले साल की कमियां कोई सरकार नहीं बताती और नए वादों की फि र से झड़ी लगा देती है जबकि जमीनी हकीकत में 100 करोड़ से अधिक जनता का जीवन वैसे ही दाव पर लगा रहता है जैसे पहले था। लोग उम्मीदों के सहारे जीते हैं लेकिन झूठी उम्मीदें क्यों? बसपा अध्यक्ष ने कहा कि देश में पहले की तरह पिछले 9 वर्षों में भी केन्द्र सरकार के बजट आते-जाते रहे, जिसमें घोषणाओं, वादों, दावों व उम्मीदों की बरसात की जाती रही किन्तु वे सब बेमानी हो गए जब भारत का मिडिल क्लास महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी आदि की मार के कारण लोवर मिडिल क्लास बन गया। जो अति अति-दुखद है। मायावती ने कहा कि सरकार की संकीर्ण नीतियों व गलत सोच का सर्वाधिक दुष्प्रभाव उन करोड़ों गरीबों किसानों व अन्य मेहनतकश लोगों के जीवन पर पड़ता है जो ग्रामीण भारत से जुड़े हैं और असली भारत कहलाते हैं। सरकार उनके आत्म-सम्मान व आत्मनिर्भरता पर ध्यान दे ताकि आमजन की जेब भरे व देश विकसित हो। मायावती ने कहा कि केन्द्र जब भी योजना लाभार्थियों के आँकड़ों की बात करे तो उसे जरूर याद रखना चाहिए कि भारत लगभग 130 करोड़ गरीबों, मजदूरों, वंचितों, किसानों आदि का विशाल देश है जो अपने अमृतकाल को तरस रहे हैं। उनके लिए बातें ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि बजट पार्टी से ज्यादा देश के लिए होता तो बेहतर।

आम जनता के लिए श्रेष्ठ बजटः अनिल राजभर

लखनऊ। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि यह आम जनता के लिए श्रेष्ठ बजट है। इसमें सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया है और आदिवासियों, गरीबों, महिलाओं, किसानों, युवाओं सभी की चिंता की गई है। श्रम मंत्री ने सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पर देश के स्थाई विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नागरिकों की सुविधाओं को और बेहतर किए जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बहुत.बहुत आभार व्यक्त किया है।

आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाएगा

अपना दल एस के प्रस्ताव को बजट में किया गया शामिल

लखनऊ। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि वर्ष 2023-24 का आम बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। उन्होंने कहा कि देश के हर व्यक्ति को भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुफ्त राशन योजना को अगले एक वर्ष तक बढ़ाने की सराहनीय पहल की गई है। अब यह योजना जनवरी 2024 तक जारी रहेगी। अपना दल एस गरीबों, वंचितों व पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए निरंतर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की मांग करता रहा है। पार्टी का यह भी कहती रही है कि आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वंचित व पिछड़ा समाज के लोग वर्षों तक जेल में पड़े रहते हैं, उनकी जमानत नहीं हो पाती है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना दल एस के इस महत्वपूर्ण मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए गरीबों की जमानत का पैसा खुद सरकार द्वारा वहन करने की घोषणा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने किसानों को एक साल तक लोन में छूट देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू करने की घोषणा की है, इसके तहत पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। अपना दल एस के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा है कि यह बजट ऐतिहासिक, संपूर्ण समावेशी, हर एक भारतीय के जीवन में सकारात्मक बदलाव का बजट है। देश में एयर सर्विस को बढ़ावा देने के लिए 50 नए एयरपोर्ट और हेलिपैड भी बनाए जाएंगे।

यह चुनावी बजट, इसमें कोई जनकल्याण की योजना नहीं

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केन्द्र सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह चुनावी बजट है, इसमें कोई जनकल्याण की योजना नहीं। ये सिर्फइम्पोर्ट को बढ़ावा देकर पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने का बजट है। अखिलेश ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सरकार ने कोई घोषणा नहीं की, स्किल डेवलपमेंट कैसे होगाघ् जब उत्पादन ही नहीं बढ़ेगा तो रोजगार कहां से देंगे, स्मार्ट सिटी का कोई जिक्र नहीं है। उत्तर प्रदेश में नए एक्सप्रेस वे के लिए कोई बजट नहीं दिया। नए पॉवर प्लांट लगाने की कोई घोषणा नहीं हुई। अखिलेश ने कहा कि ओडीओपी की बात सरकार ने फिर इस बजट में की लेकिन पहले ही ये योजना कितना जमीन पर उतरी इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। किसानों के लिए कोई नई मंडी बनाने, एमएसपी आदि के लिए घोषणा नहीं की गयी। पूरे बजट में वित्त मंत्री ने जीएसटी पर कोई चर्चा नहीं कीए जिससे व्यापारी वर्ग सबसे अधिक परेशान है। मेडिकल क्षेत्र में विकास की बात कर रहे हैं लेकिन मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था ही बर्बाद है। यूपी में गोरखपुर जैसे जिलों में बने एम्स बंद पड़े हैं। अखिलेश ने कहा कि सरकार नई एम्बुलेंस की बात कर रही लेकिन अस्पतालों में डॉक्टर, इलाज ही नहीं तो एम्बुलेंस का क्या करेंगे। ऊपर से इन लोगों ने समाजवादी एम्बुलेंस सेवा को भी बर्बाद किया। अखिलेश ने कहा कि यदि अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय इतनी ही बेहतर हुई तो किसानों की आत्महत्या क्यूं बढ़ रही है।

आम जनता की सारी उम्मीदें हुईं धूल धुसरितः खाबरी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कहा कि यह बजट पूरी तरह मध्यम वर्ग, श्रमिक, किसान, युवा, महिला तथा छात्र विरोधी है। भाजपा के पूर्व के जुमलों पर एक बार फिर बजट के माध्यम से पर्दा डालने का मात्र प्रयास है। बजट पूरी तरह आम जनता के हितों पर कुठाराघात और छलावा है।

उन्होंने कहा कि यह चुनावी बजट है, किसानों के लिए कुछ नहीं है। किसानों की एमएसपी की बात नहीं की है। रेलवे को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। आधे से ज्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया है। ये बहुत ही निराशाजनक बजट है। टैक्स स्लैब में बदलाव अच्छा है लेकिन सरकार बताए कि गरीब, किसान, बेरोजगारों को क्या दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हर गरीब को आवास, किसानों की आमदनी दुगनी, बुलेट ट्रेन, युवाओं को सालाना दो करोड़ रोजगार, महिला सुरक्षा जैसे बड़े-बड़े वादों पर वित्त मंत्री ने कुछ नहीं कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। बजट एक तरफ जहां कुछ बड़े पूंजीपतियों केंद्रित है वहीं दूसरी तरफ बजट पूरी तरह निराशावादी और देश के विकास को रसातल में ले जाने वाला है। इस बजट से आम जनता की जो उम्मीदे थीं वह धूल धूसरित हो गई हैं। महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा, किसानों की समस्याएं जस की तस हैं बजट में कुछ भी उनके लिए नहीं रखा गया है। कुल मिलाकर यह बजट युवा, महिलाएं, बेरोजगार, किसानां एवं मध्यम व निर्धन वर्ग को महज एक दिवास्वप्न दिखाने जैसा है। बजट पूरी तरह खोखला और आम जनता के साथ धोखा है। प्रधानमंत्री एक तरफ पैर में हवाई चप्पल पहनने वाले गरीब को हवाई जहाज की यात्रा का सपना दिखाने की बात करते हैं वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 24 प्रतिशत रोडवेज का किराया बढ़ाकर गरीब आदमी की कमर तोड़ने का काम कर रही है।

एमएसएमई के भगुतान के लिए प्रावधान किए जाने की आवश्यकताः आईआईए

लखनऊ। केंद्रीय बजट को लेकर आईआईए के केंद्रीय कार्यालय लखनऊ में बजट परिचर्चा के दौरान एमएसएमई के लिए उठाए गए कदम की सराहना की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष आईआई अशोक अग्रवाल ने कहा कि आईआईए द्वारा अपने बजट प्रस्ताव में जो मांगे वित्त मंत्री से रखी थी उनका आंशिक समाधान इस बजट में देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि आईआईए इन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए कुछ और बड़े कदमों की अपेक्षा रखता है। जिसमें खासतौर पर केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभागों में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों जो लंबित भुगतान बहुत समय तक पड़े रहते है उसके लिए पर्याप्त बजट प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आईआईए ने बजट पूर्व प्रस्ताव में वित्त मंत्री को एमएसएमई सेक्टर को ऋ ण की अनुपलब्धता तथा ऊँची ब्याज दरो की समस्या के समाधान के लिए आग्रह किया था। अतः एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम में 9000 करोड़ रूपए का प्रावधान करने का आईआईए स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि कोलैटरल फ्री गारंटीड क्रेडिट की कास्ट में 1 प्रतिशत की कमी भी स्वागत योग्य है। टैक्सेशन स्कीम की सीमा को 2 करोड़ रूपए से 3 करोड़ तक बढ़ाने से लाखों सूक्ष्म स्तर के उद्योगों को रहत मिलेगी। नीरज सिंघल वरिष्ठ उपाध्यक्ष आईआईए ने कहा कि बजट में जिन 7 प्राथमिकताओं के बारे में बताया गया है उससे एमएसएमई के लिए अनेक व्यावसायिक अवसर उत्पन्न होंगे। कुछ नए व्यावसायिक अवसर ग्रीन ग्रोथ, टूरिज्म, एजुकेशन एवं स्किलिंग, लैब ग्रेड डायमंड्स इत्यादि में सर्जित होंगे। दिनेश गोयल महासचिव आईआईए ने बताया कि व्यक्तिगत इनकम टैक्स में 7 लाख रूपए तक की रिबेट देने और नयी टैक्स प्रणाली में 15 लाख रूपए तक की आय पर 20 प्रतिशत इनकम टैक्स लागु करने से मध्यम वर्ग को अवश्य राहत मिलेगी जिससे एमएएमई के एवं अन्य उत्पादों की खपत बढ़ेगी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आईआईए आलोक अग्रवाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक्स एवं आईटी में बजट प्रावधान में जो लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है उससे ऑनलाइन प्रक्रिया को बल मिलेगा, फलस्वरूप पारदर्शिता बढ़ेगी।

यूपी के एमएसएमई व ओडीओपी सेक्टर को मिली बूस्टर डोज

अभिषेक रंजन। लखनऊ

उप्र की 90 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों को मिलेगी राहत

केंद्र सरकार ने अपने बजट में एमएसएमई और ओडीओपी सेक्टर को लेकर जो घोषणाएं की है, उसका सबसे अधिक लाभ यूपी को मिलेगा। इन सेक्टर से जहां एक तरफ सर्वाधिक रोजगार पनप रहे हैं तो वहीं समाज के हर वर्ग को काम भी मिल रहा है। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओडीओपी उत्पादों की बिक्री के लिए सभी राज्यों में यूनिटी मॉल खोलने की घोषणा कर प्रदेश के लाखों ओडीओपी कारीगरों, शिल्पियों और निर्यातकों को खुश कर दिया। यूनिटी मॉल राज्यों की राजधानियों के साथ ही अन्य बड़े शहरों में खुलेंगे। माना जा रहा है कि यूनिटी मालों के बन जाने पर देश के अंदर हर राज्य में ओडीओपी उत्पादों के लिए बड़ा बाजार तैयार होगा। ओडीओपी में मिट्टी के बर्तन से लेकर कांच के समान का निर्माण हो या फिर सहारनपुर में बनने वाले लकड़ी के खिलौने की बात हो इन छोटी स्टार्टअप इकाईयों के गांव देहात और शहरी नगरीय क्षेत्र के छोटे परिवार अपनी रोजी-रोटी चला रहे हैं। बजट में मोदी ने ओडीओपी को और प्रमोशन देते हुए हर राज्य में यूनिटी माल खोले जाने की घोषणा की है। इसके लिए ओडीओपी उत्पादों को एक बड़ा बाजार मिलेगा तो वहीं इस उद्योग के जरिए काम करने वाले हाथ भी वर्तमान में प्रदेश के कुल निर्यात में सबसे बड़ी हिस्सेदारी इन उत्पादों की ही है। इससे इतर अगर बात करें एमएसएमई सेक्टर की तो कोविड के दौरान पूरे देश में एमएसएमई सेक्टर में काफी गिरावट आई थी लेकिन अब केंद्र सरकार की इस डोज से एमएसएमई सेक्टर को काफी राहत मिलेगी। यूपी में 90 लाख से अधिक एमएसएमई इकाईयां हैं जिनसे करीब करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। तीन साल बाद अब प्रदेश में कोविड के बाद एमएसएमई सेक्टर पनपने लगा है। कोविड के समय एमएसएमई इकाईयों परफार्मेंस बैंक गारंटी पर जो संकट आया था वह अब दूर हो जाएगा। सरकार ऐसी एमएसएमई इकाईयों परफार्मेंस बैंक गारंटी वापस कर देगी जो कि बड़ी राहत इस सेक्टर के लिए साबित होगी। दरअसल कोविड के दौरान जो एमएसएमई इकाईयां सरकार को विभिन्न उत्पाद उलब्ध करा रही थी लेकिन लाकडाउन की वजह से उत्पादन बंद होने के कारण टेंडर की निर्धारित शर्तो के अनुरूप एमएसएमई इकाईयों की परफार्मेंस बैंक गारंटी सरकार ने रख ली थी। इस दौरान सबसे अधिक नुकसान निर्माण करने वाली इकाईयों को हुआ था। मगर अब सरकार की इस घोषणा के बाद कंपनियों की फसी हुई बैंक गारंटी के वापस मिलने का रास्ता साफ हुआ है। वापस मिलने वाली बैंक गारंटी को कंपनियां कही और लगा पाएंगी।

एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनाने का अवसर

निदेशक एवं चैयरमैन लखनऊ इंडो अमेरिकन चेम्बर मुकेश सिंह ने कहा कि 6.3 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों जिनका सकल घरेलू उत्पाद का 30 प्रतिशत हिस्सा है और लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। बजट ने लचीलेपन की इस भावना का प्रदर्शन किया है। एमएसएमई क्षेत्र के कई उद्योगों में बिक्री पूर्व महामारी के स्तर के 90 प्रतिशत तक पहुंचने के साथ भारत के छोटे व्यवसाय एक बदलाव की पटकथा लिख रहे हैं। एमएसएमई को संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना के लिए 9000 करोड़ रुपये का कोष मिला है यह संशोधित योजना 22 अप्रैल से 9000 करोड़ रुपये के कोष में डालने के माध्यम से प्रभावी होगी। इस बाउंसबैक का बहुत सारा श्रेय सरकार को उसके सक्रिय हस्तक्षेपों के लिए जाता है जैसे कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का विस्तार करना, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट की मरम्मत करना और स्वयं को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को शुरू करना है। उन्होंने कहा कि हमारे एमएसएमई की बड़े पैमाने पर असंगठित प्रकृति, बढ़ती ब्याज दरें और बिगड़ते बाहरी वातावरण ने उनके दर्द बिंदुओं को निरंतर आधार पर संबोधित करना अनिवार्य बना दिया है। सबसे महत्वपूर्ण ऑनलाइन विक्रेताओं के लिए जीएसटी दरों को कम करके, सरकार न केवल उनके वित्त को मजबूत करेगी बल्कि उनकी डिजिटलीकरण यात्रा को भी आगे बढ़ाएगी।

देश आर्थिक महाशक्ति की ओर अग्रसरः कपिल

लखनऊ। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अमृत काल मे आने वाले पच्चीस वर्ष को ध्यान मे रखते हुए भविष्य के आत्मनिर्भर भारत की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने एवं मध्यम वर्ग सहित समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े गुजर बसर करने वाले अन्त्योदय की भावना को, गांव, गरीब, किसान व्यापारी सभी की आवश्यकताओं को ध्यान मे रखते हुए उनके विकास के सपनों को चरितार्थ करता हुआ यह वार्षिक बजट निश्चित रूप से देश के सर्वांगीण विकास के सन्दर्भ मे मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 को अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल संपन्न बनाने के लिए शुरुआत की जाएगी और इसके उद्योग जगत 4 से संबंधित नई पीढ़ी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे।

दसवें बजट में जनमानस के साथ विश्वासघातः अनिल दुबे

लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा है कि जैसे सरकार ने 9 वर्षों के बजट में देश के जनमानस के साथ विश्वासघात किया ठीक वैसे ही इस दसवें बजट में भी किया है। दुबे ने कहा कि इस बजट में भी घोषणाओं, वादों और आश्वासनों कि भरमार है। इस बजट में किसानों, नौजवानों व मध्यम वर्ग के लोगों की पूरी तरह से अनदेखी की गयी है और ये बजट बेरोजगारी व महंगाई को बढ़ाने वाला है।

सीएमवाईके प्रिंटेक के लिए तथा उसी की ओर से मुद्रक एवं प्रकाशक नरेन्द्र कुमार द्वारा टिन टिन प्रिंटेक प्रा.लि. सी-33 अमौसी इंडस्ट्रियल एरिया, नादरगंज लखनऊ से मुद्रित एवं चौथी मंजिल, सहारा शापिंग सेंटर, फैजाबाद रोड, लखनऊ से प्रकाशित।
स्थानीय सम्पादकः विजय प्रकाश सिंह। फोनः (0522) 4036600 फैक्सः 2346443/2345582

एसएससी जीडी परीक्षा में दो साल्वर व अभ्यर्थी गिरफ्तार

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

एसटीएफ ने एसएससी (जीडी) परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने वाले गिरोह का का खुलासा किया है। एसटीएफ ने लखनऊ कमिश्नरेट के कृष्णानगर थाना क्षेत्र के एक सेंटर पर छापा मारकर दो साल्वर और एक मूल अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से कूटरचित आधार कार्ड, दो एसएससी जीडी प्रवेश पत्र, एक रेवले टिक, निवास प्रमाण पत्र, अंक पत्र, दो कमीशन कापी एसएससी जीडी और 5200 रुपए बरामद हुए।

छानबीन के दौरान एसटीएफ को ज्ञात हुआ कि पहली जनवरी 2023 को एसएसी (जीडी) कांसटेबल की परीक्षा में आवर लिटिल एंजल होम आन लाइन एग्जाम सेंटर, थाना कृष्णा नगर, कमिश्नरेट लखनऊ में अभ्यर्थी सचिन कुमार एवं अभ्यर्थी प्रशांत कुमार के स्थान पर साल्वर बैठने वाले हैं। इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एसटीएफ की टीम ने इस सेंटर पर छापेमारी करके अभ्यर्थी सचिन के स्थान पर साल्वर अर्पित कुमार को एवं अभ्यर्थी प्रशांत के स्थान पर जतिन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। जिनसे पूछताछ के आधार पर बाहर बैठे अभ्यर्थी सचिन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार साल्वर जतिन कुमार व अर्पित यादव ने पूछताछ में बताया कि हम लोगों को दूसरों की स्थान पर परीक्षा देने के लिए एक लाख रुपए मिलते हैं। हम लोग एसएससी (जीडी), अग्निवीर, सीटेट, सुपर टेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं। हम लोगों को परीक्षा में बैठाने के लिए अलग-अलग लोग हैं, जो नाम बदलकर हम लोगों से बात करते हैं। वह जिस के स्थान पर पेपर देना होता है उस बच्चे के फोटो व उस बच्चे के आई कार्ड प्रवेश पत्र व आधार कार्ड बनाकर या एडिट करके हम लोगों को प्रशांत द्वारा दे दिया जाता है। प्रशांत मूलतः फिरोजाबाद का रहने वाला है तथा प्रशांत अलग-अलग ग्रुप के लोगों से जुड़ा हुआ है। अलग-अलग लोगों को अलग-अलग जगहों पर प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठाता है। अभ्यर्थी प्रशांत की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

ग्लोबल इन्वेस्टर समिटः मंडलायुक्त ने लिया विभागों की तैयारियों का फीडबैक

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों पर मंडलायुक्त द्वारा विभागों की तैयारियों को फीडबैक लिया गया। मण्डलायुक्त द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को विभाग के सभी कार्यो को ससमय पूरा कराने का निर्देश दिया गया। पार्किंग स्थल पर मोबाइल शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था करा ली जाये। यही नहीं मण्डलायुक्त द्वारा जी.20 व इन्वेस्टर समिट के तहत एयरपोर्ट से लेकर 5 कालीदास मार्ग तक के विभिन्न चैराहों पर किये जा रहे साज.सज्जा के कार्यो का निरीक्षण किया गया।

बुधवार को मण्डलायुक्त डॉ रोशन जैकब ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन वृन्दावन योजना इन्वेस्टर समिट के वैन्यू पर बैठक की गई। बैठक में नगर विकास, आवास विकास परिषद, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग, अग्निशमन, पर्यटन, लखनऊ नगर प्रशासन, लखनऊ विकास प्रधिकरण सहित सम्बन्धित विभागों द्वारा की जा रही तैयारियों का फीड बैक लिया और सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। मण्डलायुक्त ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि जो भी तैयारियां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत विभाग द्वारा करायी जा रही है, उन सभी कार्यो को ससमय पूर्ण करा लिया जाये। उन्होनें कहा कि पुलिस ड्यूटी, मजिस्ट्रेट ड्यूटी 3 तारीख से कार्यक्रम स्थल पर लगाया जाना सुनिश्चित किया जाये। नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि पार्किंग स्थल पर मोबाइल शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था ससमय करा ली जाये। बैठक के दौरान मण्डलायुक्त ने पीडब्लूडी व एनएचएआई के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुये कहा कि सड़कों के कार्य मे तेजी लाये। रैलिंग की मरमम्त, डिवाइडर पेटिंग, साइनेज के कार्य ससमय करा लिये जाये। साथ ही पोलार्ड, बैरियल भी सही करा लें। उन्होनें सम्बन्धित अधिकारी से कहा कि बिजली के खम्बों की पेंटिंग, लटकते तारों को कसना एवं ट्रांसफार्मर शिफटिंग की स्थिति क्या है। लेसा के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा बताया गया है कि सम्पूर्ण कार्य पूर्ण करा लिये गये है। उन्होंने फायर सेफ्टी के तहत सम्बन्धित अधिकारी को ड्रिल बनाकर कार्य पूर्ण करना करें। इसके बाद मण्डलायुक्त ने जी.20 व इन्वेस्टर समिट के तहत एयरपोर्ट से लेकर 5 कालीदास मार्ग तक के विभिन्न चैराहों पर किये जा रहे साज.सज्जा के कार्यो का निरीक्षण किया और सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। समता मूलक चौराहें के फुटपाथ की टाइल्स के टूटे होने पर उसको तत्काल सही कराने के निर्देश दिये। कुछ स्थानों पर रैलिंग न होने पर उसको सही कराने को कहा। स्मारक समिति द्वारा समतामूलक पर पत्थरों की साफ सफाइ, पालशिग के कार्य अच्छे से कराने के निर्देश दिए और साथ ही नगर निगम द्वारा प्रतिदिन उक्त स्थानों की साफ सफाई और धुलाई कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कराये जा रहे कार्यों को स्थायी रुप से गुणवत्तापूर्ण व ससमय कराये जाने के निर्देश दिये। एनएचएआई द्वारा कराये जा रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये।

एसटीएफ की सतर्कता को लेकर प्रदेश शासन का दावा

बीते छह वर्षों में घटित होने से पहले ही रोकी गईं 438 आपराधिक घटनाएं

- 38 ईनामी अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराने के साथ ही 700 किए गए गिरफ्तारः प्रमुख सचिव गृह

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश शासन ने दावा किया है कि यूपी पुलिस की एसटीएफ की सजगता व सतर्कता के फलस्वरूप योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान 438 से अधिक अपराधिक घटनाओं को घटित होने से पूर्व ही रोकते हुए आपराधिक योजनाओं को विफल किया गया।

प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने बताया कि यह उपलब्धि एसटीएफ को मार्च 2017 से लगभग छह वर्षों की अवधि में मिली है। जिसके फ्लस्वरूप जनप्रतिनिधि, प्रतिष्ठित व्यक्ति, आम नागरिक आदि के अपहरण, लूट, हत्या आदि जैसे अपराधों की घटनाओं को घटित होने से पहले ही रोकने मे कामयाबी प्राप्त की गई हैं। इस अवधि में एसटीएफ द्वारा कुल 2084 विशेष सराहनीय कार्य भी किए गए। इसके अलावा 3197 संगठित अपराधकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रसाद ने बताया कि उक्त अवधि में कुल 700 कुख्यात व ईनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान हुई मुठभेड़ में 38 ईनामी अपराधी भी मारे गए। एसटीएफ द्वारा पकड़े व मारे गए इन अपराधियों पर 10 हजार से 5 लाख रुपए तक की धनराशि का इनाम घोषित था। एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश ने बताया कि उक्त अवधि में परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक जैसी धांधली को रोकने एवं जड़ से समाप्त करने के लिए सफलतापूर्वक कार्य करते हुए कुल 149 गिरोहों के 726 सरगना, साल्वरों व छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्य प्रत्यक्ष रूप से युवाओं के भविष्य सृजन से सम्बंधित है और इससे युवा वर्ग में सरकार की साख बहुत बढ़ी है। साइबर अपराधों में लिप्त 319 साइबर अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। अमिताभ यश ने यह भी बताया कि उक्त अवधि में अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर 167 अपराधियों की गिरफ्तारी कर उनके कब्जे से 1785 अवैध शस्त्र व 7716 अवैध कारतूस बरामद किए गए। अवैध शराब तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए विभिन्न प्रदेशो से शराब की तस्करी करने वाले 455 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर उनसे 72320 पेटी शराब, 330416 लीटर रेक्टिफ इड स्प्रिट एवं 7560 लीटर तैयार देशी शराब बरामद की गई।

ट्रैवल कंपनी से सेवा लेकर भुगतान न करने पर दम्पति पर मुकदमा दर्ज

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

जानकीपुरम स्थित निजी कम्पनी के मालिक दम्पति ने एक ट्रैवेल्स कम्पनी से देश.विदेश के टूर पैकेज समेत होटल.टैक्सी की सुविधाएं ली। दम्पति ने पहले नकद भुगतान कर फंसाया और फिर धीरे धीरे कर पांच साल में 38-54 लाख का बिल बकाया कर दिया। बकाया मांगने पर दम्पति ने पहले सुविधाएं लेनी बंद की और फिर रुपये के नाम पर टालमटोल की। लगातार आनाकानी देख पीड़ित पेमेंट के लिए दम्पति के घर पहुंचा जहां उसे नेताओं से सेटिंग का रौब दिखा धमकी दी गयी। थाने पर सुनवायी न होने पर ट्रेवेल्स कम्पनी के मैनेजर ने पुलिस आयुक्त एसबी शिरडकर से मिलकर शिकायत की। निर्देश पर जानकीपुरम पुलिस ने दम्पति समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आईटी चौराहा के सृष्टि काम्प्लेक्स स्थित जेवी ट्रेवेल्स में अनूप यादव प्रबंधक के पद पर हैं। उन्होंने बताया कि सेक्टर आई जानकीपुरम स्थित भारतीय माइक्रो क्रेडिट कम्पनी के प्रबंध निदेशक विजय पाण्डेय व उनकी पत्नी डिप्टी मैनेजिंग डॉयरेक्टर माया पाण्डेय ने वर्ष 2014 में सम्पर्क किया था। दम्पति ने अपने व अपने कर्मचारियों के लिए देश विदेश की यात्रा के लिए एयर टिकट, रेलवे टिकट, होटल, टैक्सी बुकिंग व विदेश के टूर पैकेज खरीदते रहे। अनूप का कहना है कि शुरूआत में दम्पति ने हमेशा नकद भुगतान किया लेकिन धीरे.धीरे वर्ष 2015 से नकद व उधार करने लगे। इसी तरह से दम्ति पर वर्ष 2015 से वर्ष 2020 तक का 3854657 रुपये का बकाया हो गया। उसी साल अनूप यादव ने उनसे सम्पर्क कर भुगतान का अनुरोध किया। इसपर उन लोगों ने उनकी कम्पनी से ली जा रही सुविधाओं को बंद कर दिया। भुगतान के नाम पर वे लोग लगातार आश्वासन देते रहे। उनका कहना है कि 24 अक्टूबर को भुगतान की बात करने विजय पाण्डेय के आवास जानकीपुरम गया। बात करने पर विजय व उनके साथी अनमोल ने टालमटोल की। दबाव बनाने पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। यही नहीं नेताओं से जान.पहचान बता मारपीट पर उतारू हो गये। पीड़ित वहां से निकलकर जानकीपुरम थाने पहुंचा। शिकायत की लेकिन पुलिस ने दीवाली का त्यौहार बता बाद में आने को कहा। उसके बाद पीड़ित अनूप यादव कई बार थाने गया लेकिन सुनवायी नहीं हुई। पीड़ित ने पुलिस आयुक्त से शिकायत की। निर्देश पर जानकीपुरम पुलिस ने बीते मंगलवार को भारतीय माइको क्रेडिट कम्पनी के प्रबंध निदेशक विजय पाण्डेय डिप्टी मैनेजिंग डॉयरेक्टर उनकी पत्नी माया पाण्डेय व अनमोल हेरोल्ड के खिलाफ अमानत में खयानत गाली गलौज व जान से मारने की धमकी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

आईएएस प्रशिक्षु अधिकारियों ने किया लखनऊ मेट्रो का दौरा

लखनऊ। प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों द्वारा मेट्रो के डिपो में संचालन को देखा गया। डिपो में प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों द्वारा 5डी सिम्युलेटर के कॉकपिट में मेट्रो के रियल टाइम ड्राइविंग का अनुभव किया गया। बुधवार को लाल बहादुर शास्त्री अकादमी मसूरी से आईएएस प्रशिक्षु अधिकारियों ने लखनऊ मेट्रो के स्टेशनों, ट्रांसपोर्ट नगर डिपो और ओसीसी-संचालन नियंत्रण केंद्र का दौरा किया। 19 प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों के दौरे की शुरुआत लखनऊ मेट्रो के प्रबंधन और परिचालन तंत्र के अवलोकन के साथ हुई। इस यात्रा का नेतृत्व महाप्रबंधक संचालन स्वदेश कुमार ने किया। डिपो में प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों ने 5डी सिम्युलेटर के कॉकपिट में मेट्रो के रियल टाइम ड्राइविंग का अनुभव किया। 5डी सिम्युलेटर मेट्रो चलाने का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है। इस 5डी सिम्युलेटर पर मेट्रो ट्रेन चालकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। बाद में प्रशिक्षु अधिकारियों के पूरे दिन के दौरे का समापन ओसीसी के दौरे के साथ हुआ जहां उन्होंने मेट्रो के संचालन के वास्तविक समय प्रबंधन को समझा।

मकान का ताला तोड़कर चोरों ने उड़ाए जेवरात

लखनऊ। राजधानी में शातिर चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आये दिन यह शातिर चोर किसी न किसी मकान दुकान या वाहन पर हाथ साफ कर रहे हैं और चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर फुर्र हो रहे हैं। ताजा मामला चिनहट इलाके का है, जहां चोरों ने मकान में घुसकर सोने चांदी के जेवरात व अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। पुलिस ने वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जनपद गाजीपुर निवासी अभय नारायण बताया कि वादी की दीदी नक्षत्र गेस्ट हाउस में रहती हैं। एक दिन पहले दीदी व जीजा नौकरी के सिलसिले में हैदराबाद गये थे। वहां से बुधवार को लौटे तो देखा कि मकान का ताला तोड़कर अल्मारी में रखे सोने चांदी के जेवरात व डीएसएलआर कैमरा समेत कीमती सामान चोरी कर लिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आस पास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।

संदिग्ध अवस्था में गांव के बाहर पड़ा मिला शव

लखनऊ। राजधानी के गोसाईगंज इलाके में नशे के आदी का शव गांव के बाहर अचेत अवस्था में पड़ा मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी। जानकारी के अनुसार भटटी बरकतनगर गोसाईगंज निवासी कलान्त कुमार वर्मा ने पुलिस को सूचना देकर बताया कि उनका चचेरा भाई अनिल कुमार वर्मा जो नशे का आदी था और हमेशा घर से भाग जाया करता था। बुधवार को गांव वालों ने बताया कि अनिल का शव गांव के बाहर खेत में पड़ा हुआ है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक विवाहित था और उसके एक बेटा था। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दिया है।

शातिर चोर गिरफ्तार, जेवरात बरामद

लखनऊ। राजधानी की इंदिरानगर पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी किये हुए सोने चांदी के जेवरात बरामद किये हैं। जानकारी के अनुसार इंस्पेक्टर इंदिरानगर छत्रपाल सिंह ने बताया कि अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस गश्त पर थी तभी मुखबिर से सूचना मिली कि एक शातिर चोर किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भरोसा किया और मौके पर पहुंचकर दबोच लिया। पुलिस पूछताछ में उसने अपना नाम बख्शी का तालाब निवासी अभिषेक उर्फ अर्पित बताया। पुलिस ने उसके कब्जे से जेवरात बरामद किये हैं।

एकेटीयू में प्लेसमेंट का आयोजन

लखनऊ। डॉ एपीजे कलॉम प्राविधिक विश्वविद्यालय में बुधवार को विवि के कुलपति प्रो पी के मिश्रा जी के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट विभाग द्वारा छात्रों को रोजगार देने के लिए हाईक एजुकेशन कम्पनी को आमंत्रित किया गया। जिसमें विभिन्न संस्थाओं के लगभग दो सौ छात्रों ने साक्षत्कार दिया। तदोपरांत प्रथम चरण के साक्षत्कार में तीस छात्रों को कम्पनी के लिए चयनित किया गया तथा द्वितीय चरण के साक्षात्कार में चौदह छात्रों का चयन किया गया जिनका परीक्षाफल कल तक घोषित किया जाएगा। यह सभी छात्रों का चयन बी टेक ब्रांच से किया गया है। हाईक एजुकेशन कम्पनी से दो एच आर निकिता यादव एवं तेज नारायण पांडेय ने सभी छात्रों का साक्षात्कार अधिष्ठाता अरुणिमा वर्मा की उपस्थिति में लिया गया। चयनित छात्रों को करीब सात लाख का सालाना पैकेज मिलेगा।

एलोपैथी व होम्योपैथी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु में अंतर समता का उल्लंघनः हाईकोर्ट

- होम्योपैथी डॉक्टर की सेवानिवृत्ति सम्बंधी आदेश को किया रद्द

विधि संवाददाता। लखनऊ

प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के एलोपैथी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष लेकिन होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा कैडर के डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष ही रखने को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने विधि के समक्ष समता के सिद्धांत का उल्लंघन माना है। पीठ ने इस टिप्पणी के साथ ही एक होम्योपैथिक डॉक्टर की सेवानिवृत्ति सम्बंधी आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें 62 वर्ष की आयु तक सेवा में बनाए रखने का आदेश दिया है।

जस्टिस विवेक चौधरी की एकल पीठ ने यह आदेश डॉ सुरेन्द्र प्रताप यादव की सेवा संबंधी याचिका पर दिया है। याचिका में 31 दिसंबरए 2021 के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि वह होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा कैडर से है। उन्हें 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर सेवानिवृत्त किया जा रहा है। जबकि 31 मई 2017 को एक अधिसूचना जारी कर प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के एलोपैथी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष कर दी गई है। सुनवाई के दौरान इस याचिका का राज्य सरकार की ओर से विरोध किया गया। एकल पीठ ने दोनों पक्षों की बहस के बाद एक निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि प्रांतीय चिकित्सा सेवा के एलोपैथी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की उम्र को 62 वर्ष करना लेकिन होम्योपैथिक कैडर के डॉक्टर जो इलाज का एलोपैथी से अलग तरीका प्रयोग करते हैं, उन्हें यह लाभ नहीं देना संविधान में प्रदत्त समता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप, पांच लाख की ठगी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

आशियाना कोतवाली में युवती ने प्रेमी के खिलाफ यौन शोषण करने का मुकदमा दर्ज कराया है। शादी का झांसा देते हुए आरोपी ने युवती से संबंध बनाए। करीबी का फायदा उठाते हुए आरोपी ने युवती से पांच लाख रुपये भी ऐंठ लिए। आशियाना निवासी युवती की दोस्ती ट्रांसपोर्टनगर निवासी सरफराज खान से थी। पांच वर्ष से दोनों का मुलाकात हो रही थी। पीड़िता के मुताबिक सरफराज ने शादी करने का प्रस्ताव दिया था। जिसे उसने स्वीकार्य लिया। इसके बाद से ही आरोपी ने यौन शोषण शुरू कर दिया। विरोध करने पर जल्द से जल्द शादी करने की बात कहने लगा। पीड़िता के गर्भवती होने पर सरफराज ने धोखे से दवा देकर गर्भपात करा दिया। आर्थिक दिक्कत का हवाला देते हुए आरोपी ने पांच लाख रुपये वसूल लिए। करीब एक माह पूर्व पीड़िता को पता चला कि सरफराज ने उससे छुपा कर शादी कर ली है। उसने युवती का फोन उठाना भी बंद कर दिया। परेशान होकर युवती ने बुधवार को आशियाना थाने पहुंच कर शिकायत की। इंस्पेक्टर अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि युवती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। युवती का मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराया जाएगा। वहीं आरोपी सरफराज और उसके साथी इमरान से भी पूछताछ की जाएगी।

विनय पाठक के खिलाफ एकेटीयू ने बिठाई जांच पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी गठित

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक के उपर लगे अनियमितता की जांच के लिए विवि के कुलपति प्रो. पीके मिश्रा ने सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है। गठित समिति आरोपों की जांच कर अपनी रिपोर्ट देगी। मौजूदा समय में कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक पर परीक्षा संबंधित कामों में कमीशनबाजी व अनियमितता के आरोप में पहले से ही एसटीएफ की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसके बाद शासन ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया था। जहां पर इस मामले की जांच चल रही है। अब वहीं एकेटीयू प्रशासन ने 21 नवंबर 2022 के विश्वविद्यालय आयोग की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को प्रेषित एक शिकायती पत्र की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित कमेटी में सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश संजय, आरईसी सोनभद्र के निदेशक जीएस तोमर व सहायक कुलसचिव रंजीत सिंह प्रस्तुता अधिकारी के रूप में शामिल हैं।

कमेटी इन मामलों की करेगी जांचः एकेटीयू के कुलपति प्रो मिश्रा की ओर से बनाई गई कमेटी प्रोफेसर विनय पाठक पर लगे 14 गंभीर आरोपों की प्रमुखता से जांच करेगी। जिसमें प्रोफेसर विनय पाठक की शिकायत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं प्रधानमंत्री कार्यालय से मिले सभी सूचनाओं के साथ ही कार्य परिषद व वित्त समिति के किए गए सभी निर्णयों की जांच शामिल है। अलावा समिति विश्वविद्यालयों में हुए सभी भर्तियों की जांच, ई.कंसोर्सियम की जांच पीएनबी हाउसिंग में 700 करोड़ रुपए एवं 1000 करोड़ रुपए का गलत निवेश, परीक्षा के गोपनीय कार्यों में 100 करोड़ का गलत निवेश, डीडीक्यूआईपी में 300 करोड़ का फर्जी भुगतान, गोल्ड बॉन्ड में निवेश, प्लेगेरिज्म फर्जी पीएचडी व फर्जी पेपर, फर्जी विनियमितीकरण, आगरा व एकेटीयू की कार्यपरिषद में नामित प्रक्रिया की जांच, डॉक्टर विनीत कंसल व डॉ अनुराग त्रिपाठी की प्रोफेसर पद पर फर्जी नियुक्ति, फर्जी बायोडाटा तैयार करना तथा निर्माण कार्यों का फर्जी तरीके से भुगतान करना जैसे गंभीर अनियमितता की जांच कर कुलपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

प्रमोशन को लेकर सड़क पर एलडीए लगाएगा मस्ती की पाठशाला

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

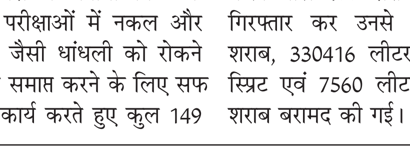

राजधानी में 4 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक 1090 चौराहा और मरीन ड्राइव पर मस्ती की पाठशाला लगेगी, जहां खेल-कूद के साथ ही योगा, जुम्बा एवं एरोबिक डांस, साइकिलिंग और नुक्कड़ नाटक सरीखे ढेरों आयोजन होंगे। शहरवासियों को यहां एक ही जगह पर इन अलग.अलग रोचक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। एलडीए के उपाध्यक्ष ने आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट व जी.20 शिखर सम्मेलन के प्रमोशन को लेकर इस राहगीरी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है।

एलडीए द्वारा गोमतीनगर के 1090 चौराहा और मरीन ड्राइव पर 4 से लेकर 8 फरवरी तक मस्ती की पाठशाला चलाई जाएगी। बुधवार को एलडीए उपाध्यक्ष डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि पूर्व में भी प्राधिकरण द्वारा इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। अब एलडीए द्वारा जी.20 शिखर सम्मेलन व ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के प्रमोशन के उद्देश्य से शहर में राहगीरी कार्यक्रम की शुरूआत दोबारा की जा रही है। इसके तहत 4 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक 1090 चौराहा और मरीन ड्राइव पर सड़क पर राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें नेट क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, साइकिलिंग, स्केटिंग, बोर्ड पेटिंग, योगा, जुम्बा एवं एरोबिक डांस, म्यूजिकल बैंड, मैजिक.शो और नुक्कड़ नाटक समेत कई तरह की मनोरंजक गतिविधियां होंगी। यह आयोजन हर आयु वर्ग के लोगों के लिए खास होगा और इसमें कुछ नया करने और सीखने के लिए अलग.अलग चीजें होंगी। उपाध्यक्ष ने बताया कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से आम जनता के लिए समर्पित होगा और इसमें किसी भी तरह का कोई प्रवेश शुल्क नहीं लगेगा। एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि यह कार्यक्रम लोगों में जागरुकता लाने का भी बड़ा माध्यम बनेगा। इसमें पेन्टिंग, स्लोगन राइटिंग व नुक्कड़ नाटक समेत अलग.अलग माध्यमों से लोगों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और जल संरक्षण आदि के सम्बंध में भी जागरूक करने का कार्य किया जाएगा।

जन्मजात बीमारी से बच्चे को दिलाई निजात

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

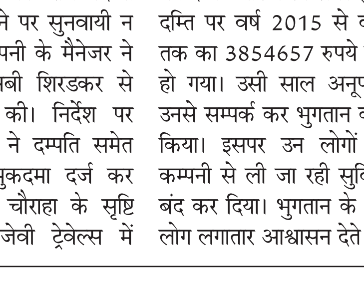

किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने एक सात साल के बच्चे को जन्जात बीमारी से निजात दिलाया है। सर्जरी के बाद स्वस्थ्य होने पर बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया है। बाराबंकी निवासी आशाराम अपने सात साल के बेटे अंश जो के जन्म से पेट दर्द और उल्टी से परेशान थे। उन्होंने कई निजी हॉस्पिटल में सलाह ली लेकिन मरीज की हालत में सुधार नहीं हुआ। अंत में वह पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के विभाग प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर जेडी रावत की ओपीडी में पहुॅचे। जांच के बाद पता चला कि मरीज़ को कोलेडोकल सिस्ट नामक बीमारी से ग्रसित है जो कि एक जन्मजात विकृति है, जिसमें पित्त कि नली विकृत हो जाती है और एक ट्यूब के बजाय थैली बन जाती है। आमतौर पर इस रोग का ऑपरेशन पेट में एक बड़ा चीरा लगाकर किया जाता है। लेकिन प्रोफेसर जे डीण् रावत एवं टीम ने लैप्रोस्कोपिक तकनीक से सर्जरी करने की योजना बनाई। बीते 25 जनवरी को लेप्रोस्कोपिक तकनीक से मरीज का सफल ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन का समय 5 घंटे था। लेप्रोस्कोप और उपकरणों को लगाने के लिए पेट में बड़ा चीरा लगाने के बजाय सिर्फ चार छोटे छेद किए गए। पोस्ट ऑपरेटिव अवधि में रोगी को ओपन सर्जरी की तुलना में कम दर्द और परेशानी होती है। रोगी को 6 दिनों के बाद संतोषजनक स्थिति में छुट्टी दे दी गयी। ऑपरेटिव टीम के अन्य सदस्य डॉ सुधीर सिंह, डॉ पीयूष कुमार और डॉ निरपेक्ष त्यागी थे। डॉ जीपी सिंह, डॉ सतीश वर्मा और उनके रेजिडेंट्स द्वारा इतनी लंबी सर्जरी के लिए एनेस्थीसिया टीम का अच्छा सहयोग रहा। नर्सिंग स्टाफ में सिस्टर वंदना, सिस्टर अंजू और संजय थे।

सतत विकास की रणनीति के तहत कृषि, युवा व पर्यावरण पर विशेष जोर

लखनऊ। मोदी 2.0 सरकार का यह आखिरी बजट भी पहले के बजटों के श्रृंखला में एक नयी कड़ी है जो अर्थव्यवस्था के तीव्र व समावेशी विकास के साथ तालमेल बिठाते हुए नये वृद्धि केन्द्रों को सृजित करता हुआ नजर आता है।

यूं तो वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आयकर में दी गयी व्यापक छूट आमलोगों में चर्चा का विषय बन चुका है किन्तु यह बजट मुख्य रूप से कृषि विकास, हरित उर्जा एवं हरित विकास रणनीति, लघु एवं मध्यम उद्योग के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहित करता हुआ नजर आता है। मोदी सरकार का 2023-24 का बजट सात प्रमुख आयाम सप्तर्षि पर आधारित है, जो अर्थव्यवस्था को नया आयाम प्रदान करने की क्षमता रखता है। इस दृष्टिकोण से जिस प्रकार से कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण किया जा रहा है तथा इसको आर्थिक विकास के एक नये स्श्रोत के रूप में सृजित किया जा रहा है, वह महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत कृषि के लिए 20 लाख करोड़ के ऋण का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही डिजिटल तकनीक के भरपूर इस्तेमाल से इसको नई गति प्रदान की जायेगी। मोटे आनाजों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने से भी कृषि समृद्ध होगी। इसी प्रकार कृषि विविधिकरण, प्राकृतिक खेती उत्पादन लागत में कमी महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार एवं आय में वृद्धि होगी। सूक्ष्म, लघु एवं मझोले व्यापार एवं उद्योग पर भी इस बजट में विशेष प्रयास नजर आता है। इसलिए 2 लाख करोड़ तक के ऋण की ऐसी व्यवस्था की गयी है, जिसके लिए किसी गारंटी की बावश्यकता न पड़े। कोरोना काल में इस तरह की जिन फर्मो ने निविदा की राशि जमा की थी तथा कार्य न करने से वो राशि जब्त हो गयी, अब उसको भी वापस कर दिया जायेगा, जिससे ऐसी फर्मों की पूंजी बढ़ सकेगी। इसी के साथ अन्य प्रयास भी इनको आगे बढ़ाने में मददगार होंगे। समावेशी विकास की रणनीति के अंतर्गत अवस्थापना सुविधाओं का तीव्र विकास किया जाना है। युवा वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए इनके कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को अगले 3 वर्ष तक फिर लागू किया गया है। इसी प्रकार चहुॅमुखी विकास के अंतर्गत नगरीय विकास तथा रेलवे विकास को नया आयाम दिया जा रहा है। इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह चाहे कृषि विकास हो या नगरीय विकास हो या फिर परिवहन या यातायात हो, सब में एक समान रणनीति यह है कि सभी जगह या तो पर्यावरण संरक्षण हो या पर्यावरण में सुधार हो सके। इस प्रकार मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट समावेशी होने के साथ-साथ पोषणीय एवं तीव्र गति से होने वाले विकास पर केन्द्रित है।

(लेखकः प्रो. मनोज अग्रवाल प्रसिद्ध अर्थशास्त्री होने के साथ ही लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के विभाग प्रमुख हैं)

पांच कालीदास मार्ग चौराहे पर मोर की आकृति का लगेगा स्कल्पचर

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

आगामी जी-20 शिखर सम्मेलन पर शहर में कराये जा रहे कार्यों के सम्बंध में एलडीए के उपाध्यक्ष द्वारा 1090 चौराहा, बंदरियाबाग चौराहा, लालबत्ती चौराहा समेत विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने सम्बंधित रूटों पर सौंदर्यीकरण व हॉर्टिकल्चर के कार्यों को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिये। उपाध्यक्ष ने हिदायत देते हुए कहा कि सभी अधिकारी व अभियंता अपने निर्धारित ड्यूटी प्वाइंट्स पर उपस्थित रहकर समस्त कार्यों को ससमय पूर्ण कराएं।

बुधवार को गोमतीनगर के 1090 चौराहा, बंदरियाबाग चौराहा, लालबत्ती चौराहा समेत विभिन्न स्थलों का उपाध्यक्ष डॉ इंद्रमणि त्रिपाठी द्वारा निरीक्षण किया। 1090 चौराहे के निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष ने निर्देश दिये कि पाल्म के पेड़ों पर ट्राई कलर लाइटिंग के साथ प्लेटफार्म पर मल्टीकलर गमलों से सजावट का कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि हाई मास्ट लाइट को सही कराने के साथ ही खम्भों की सफाई आदि के कार्य भी तत्काल प्रभाव से पूर्ण करा लिये जाएं। इसके अतिरिक्त स्मारक समिति के बाहरी क्षेत्र में पराग बूथ की तरफ रंगाई-पुताई व लाइटिंग के कार्यों के साथ ही पत्थरों की सफाई के कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराए जाएं। इसके बाद उन्होंने पांच कालीदास मार्ग चौराहे का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने चौराहे पर मोर की आकृति का स्कल्पचर लगाने और आकर्षक वॉल पेन्टिंग व हॉर्टीकल्चर वर्क कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी चौक पर लगे फव्वारे को ठीक कराकर संचालित किया जाए। रेलिंग की पेन्टिंग कराके पेड़ों पर स्पॉट लाइटें लगायी जाएं। इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष ने बंदरियाबाग चौराहे पर स्थित नोस प्लेटफार्म पर पत्थरों को सही कराकर फ ॉक्सटेल पाल्म लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने लालबत्ती चौराहे पर हॉर्टीकल्चर वर्क कराने के साथ ही फोकस लाइटें लगाने के निर्देश दिये। इसके बाद उपाध्यक्ष डॉ इन्द्रमणि त्रिपाठी व नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह ने संयुक्त रूप से शहीद पथ का निरीक्षण किया, जिसमें सर्विस रोड पर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिये गये। इसके अनुपालन में प्राधिकरण के प्रवर्तन जोन.2 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी व नगर निगम जोन.8 के जोनल अधिकारी सुजीत श्रीवास्तव द्वारा कार्यवाही करते हुए एक दर्जन से अधिक स्थानों पर से अतिक्रमण हटवाये गये। इस दौरान शहीद पथ के सर्विस रोड पर स्थित ढाबों के संचालकों द्वारा किये गये अतिक्रमण को लेकर उनके विरूद्ध नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के अंदर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये गये।

पुलिस को तकनीकी रूप से और अधिक सक्षम व उच्चीकृत होने की जरूरतः डीजीपी

● यूपी और यूके पुलिस के उच्चाधिकारियों ने अहम बिन्दुओं पर किया गहन विचार-विमर्श

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

डीजीपी डॉ. देवेंद्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय के सभागार में यूपी और यूके पुलिस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन ट्रेड मिशन डेलीगेट्स के मध्य बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में अन्ना शॉटबोल्ट डिप्टी ट्रेड कमिश्नर साउथ एशिया, रॉबर्ट बर्न्स पुलिस एंड सिक्योरिटी एडवाइजर यूके, विभोर सिंह डिप्टी हेड डीसीएफ, इंडिया सहित यूके की विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों व पुलिस मुख्यालय से डीजी प्रशिक्षण, एडीजी अपराध, एडीजी स्थापना, एडीजी दूरसंचार, एडीजी लॉजिस्टिक्स, एडीजी एवं डीजीपी के जीएसओ, एडीजी एटीएस, एडीजी तकनीकी सेवाएं, आईजी कानून-व्यवस्था सहित अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

बैठक में उपस्थित विभिन्न कम्पनियों के प्रतिनिधियों द्वारा महत्वपूर्ण विषयों और बिन्दुओं पर अपना-अपना प्रस्तुतिकरण करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से अपने अनुभवों का साझा किया गया। जिन विषयों पर चर्चा हुई उनमें साइबर सिक्योरिटी, फॉरेन्सिक साइंस, क्राइम इन्वेस्टीगेशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड सेफ सिटी, सिक्योर कम्युनिकेशन, प्रिजन एंड सिक्योर एक्सेस मैनेजमेंट, ड्रग एंड नॉरकोटिक्स प्रोहबिशन, पुलिस ट्रेनिंग आदि प्रमुख थे। इस मौके पर डीजीपी ने पुलिस पुलिस के दैनिक कार्यों में आधुनिक तकनीकों का अधिकाधिक प्रयोग सहित अपराधों के आधुनिक स्वरूप (आर्थिक एवं साइबर क्राइम) के निस्तारण के लिए पुलिस को तकनीकी रूप से और अधिक सक्षम, सबल व उच्चीकृत करने पर बल देते हुए कहा कि इस परिपेक्ष्य में यूके एवं उत्तर प्रदेश पुलिस के मध्य इस प्रकार की बैठक का विशेष महत्व है।

लविवि में लैंगिक समानता को लेकर स्पेसेज कार्यक्रम आयोजित

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

लखनऊ विश्वविद्यालय के जेंडर सेंसिटाइजेशन सेल ने बुधवार को यूनिवर्सिटी कैंपस के चंद्रशेखर आजाद लॉन में रूहानी ऑल गर्ल्स बैंड और प्रमुख सांस्कृतिक कार्यकर्ता और थिएटर कलाकार महेंद्र पाल के साथ स्पेसेज नाम की श्रृंखला में अपना तीसरा कार्यक्रम आयोजित किया। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले गीत जैसे बादल पे पाव हैं, दिल है छोटा सा, आशाएं, ओ री चिरैया गाये गए।

प्रकोष्ठ ने प्रख्यात नारीवादी लेखिका कमला भसीन के गीतों जैसे तोड़ तोड़ के बंधन, इरादा कर बुलंद का जश्न मनाया। छात्रों ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कविता पाठ किया। कार्यक्रम में 75 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच कैंटीन, लॉन, हॉस्टल जैसे अपने स्वयं के स्थानों में लिंग आधारित हिंसा, उत्पीड़न और लैंगिक समानता की चर्चा शुरू करने के लिए स्पेस नाम का कार्यक्रम शुरू किया था। इस प्रकोष्ठ का गठन कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने 2020 में किया था और तब से ये प्रकोष्ट समय समय पर विभिन्न कार्यकमों द्वारा छात्र छात्रओं को लिंग समानता से जुड़े विषयों से अवगत कराता आया है। प्रदर्शन के बाद जेंडर सेंसिटाइजेशन सेल टीम, परफॉर्मर्स और दर्शकों के बीच जेंडर आधारित हिंसा के व्यक्तिगत अनुभवों पर चर्चा हुई। दर्शकों ने लिंग, सेक्सुअलिटी, सेक्सिज्म की परिभाषाओं के बारे में अपनी शंकाओं को भी साझा किया। प्रकोष्ठ की कन्वीनर अर्थशास्त्र विभाग की प्रो रोली मिश्रा और उनकी टीम में डॉ प्रशांत ने दर्शकों के सवालों का जवाब दिया और सभी को अपने आसपास किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए प्रोत्साहित किया।

सीएमएस छात्रों ने निकाला धार्मिक सद्भावना मार्च

लखनऊ। सिटी मोन्टेसरी स्कूल, अशर्फाबाद कैम्पस के मेधावी छात्रों ने आज धार्मिक सद्भावना मार्च निकालकर सामुदायिक एकता एवं सामाजिक सौहार्द की पुरजोर अपील की। इस विशाल मार्च में हिन्दू धर्म से मधु स्मिता दास एवं स्वामी व्योमातितानंद, इस्लाम धर्म से मौलाना सूफयान निजामी एवं मौलाना यासूब अब्बास, सिख धर्म से राजेन्द्र सिंह बग्गा, ईसाई धर्म से डा. डोनाल्ड एच आर डिसूजा, जैन धर्म से शैलेन्द्र जैन, बौध धर्म से भंते कौशल बोधि ने सीएमएस छात्रों की अगुवाई की एवं अशर्फाबाद क्षेत्र के विभिन्न गली-मोहल्लों में घूमकर समाज में शान्ति, सद्भाव व सौहार्द का अभूतपूर्व उल्लास जगाया। मार्च की खास बात रही कि इसमें छात्रों की माताओं ने भी बड़ी संख्या में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। विदित हो कि सीएमएस अशर्फाबाद कैम्पस द्वारा धार्मिक सद्भावना सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज विद्यालय के छात्रों द्वारा धार्मिक सद्भावना मार्च निकाला गया। सीएमएस संस्थापक व प्रख्यात शिक्षाविद् डा. जगदीश गाँधी ने दीप प्रज्वलित कर धार्मिक सद्भावना सप्ताह का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर गणमान्य नागरिकों का स्वागत करते हुए डा. गाँधी ने कहा कि सामाजिक प्रगति व उत्थान के लिए धार्मिक एकता तथा विश्व एकता आज की अनिवार्य आवश्यकता है, जिसकी शिक्षा बच्चों को बाल्यावस्था से ही देनी चाहिए। सीएमएस प्रेसीडेन्ट प्रो. गीता गाँधी किंगडन ने कहा कि सीएमएस छात्र शैक्षिक क्षेत्र में नये-नये कीर्तिमान स्थापित करने के साथ ही विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भी जोरदार भागीदारी कर समाज के पुनरुत्थान को संकल्पित हैं।

अवध बार का वार्षिक चुनाव

आनंद मणि त्रिपाठी अध्यक्ष, मनोज कुमार मिश्रा महासचिव बने

विधि संवाददाता। लखनऊ

अवध बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद पर आनंद मणि त्रिपाठी ने जीत हासिल की है। वहीं महासचिव के पद पर मनोज कुमार मिश्रा विजयी हुए हैं। बुधवार की सांय घोषित परिणाम के मुताबिक वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर अनुज कुदेसिया, उपाध्यक्ष मध्य के दो पद पर अमित जायसवाल व अखिलेश प्रताप सिंह चौहान जबकि कनिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर रवि प्रकाश मिश्रा विजयी हुए हैं। कोषाध्यक्ष के पद पर भूपाल सिंह ने जीत हासिल की है। वहीं संयुक्त सचिव के तीन पदों पर अनीता तिवारी, सिंकन्दर यादव व अरविन्द कुमार तिवारी निर्वाचित हुए हैं। वरिष्ठ कार्यकारिणी के छह पदों पर देवेश चंद्र पाठक, अनुराधा सिंह, अनिल कुमार तिवारी, बनवारी लाल, निशा श्रीवास्तव व सूर्य प्रकाश सिंह जबकि कनिष्ठ कार्यकारिणी के छह पदों पर हर्षिता मोहन शर्मा, शशांक द्विवेदी, आशीष कुमार श्रीवास्तव, आदेश श्रीवास्तव, आरती रावत व रश्मि सिंह ने जीत हासिल की है।

मनी लॉर्ड्रिंग का मामला

यादव सिंह की पत्नी को न्यायिक हिरासत में भेजा जेल

लखनऊ (विसं)। जिला जज व ईडी के विशेष जज संजय शंकर पांडेय ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस.वे के चीफ इंजीनियर रहे यादव सिंह की पत्नी कुसुम लता को मनी लॉर्ड्रिंग के मामले में न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मंगलवार को ईडी की विशेष अदालत के समक्ष मुल्जिमा कुसुम लता हाजिर हुईं और साथ ही उनकी ओर से जमानत अर्जी भी दाखिल की गई।

विशेष अदालत ने जमानत अर्जी पर बहस के बाद अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। मनी लॉर्ड्रिंग का यह मामला आय से अधिक संपति से जुड़ा है। आठ अक्टूबर 2015 को ईडी ने इस मामले में लखनऊ में यादव सिंह के खिलाफ मनी लॉर्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच शुरु की थी।

नगर सृजन योजना, जल निगम के प्रोजेक्ट की मॉनीटरिंग के लिए ऐप का शुभारम्भ

लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने सम्भव की व्यवस्था के तहत राज्यव्यापी जनसुनवाई की। इस जनसुनवाई में शिकायतकर्ता और अधिकारियों से परेशानियों के संबंध में सीधे वार्ता की और समस्याओं के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिये। नगर विकास मंत्री नगरीय निकाय निदेशालय में सम्भव की व्यवस्था के तहत महीने के प्रथम बुधवार को नगरीय समस्याओं से संबंधित मंत्री स्तर की राज्य स्तरीय जनसुनवाई की। नगर विकास मंत्री ने जी 20 की होने वाली बैठकों के दृष्टिगत नगर आयुक्त आगरा, गाजियाबाद, वाराणसी एवं लखनऊ को निर्देश दिए कि इन नगरों के सभी सिविल वर्क को शीघ्र पूरा करें। बेहतर साफसफाईए सौन्दर्यीकरण एवं व्यवस्थापन के कार्य में कहीं कोई कमी न रहने पाये। ऐतिहासिक स्मारकों व पर्यटक स्थलों को जाने वाली सड़कों को दुरूरस्त किया जाए, चौराहों, फुटपाथों का सौन्दर्यीकरण किया जाए। सड़कों के किनारे खाली पड़ी जमीन से धूल न उड़े इसके लिए हरियाली की व्यवस्था करें। सभी कैन्टोनमेंट एरिया के क्षेत्रों की सड़कों एवं उसके किनारों को वहां के अधिकारियों से सम्पर्क कर व्यवस्थित कराएं। उन्होंने कहा कि नगरों को वैश्विक नगर बनाना है। इसके लिए पूरी सर्तकता के साथ कार्य कर बेहतर प्रदर्शन करना होगा। मंत्री ने इस दौरान मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना की मॉनीटरिंग के तथा जल निगम के प्रोजेक्ट की मॉनीटरिंग के लिए अलग-अलग ऐप का भी शुभारम्भ किया। इस दौरान प्रमुख सचिव नगर विकास अनिल कुमार, सचिव रंजन कुमार, निदेशक नेहा शर्मा, अपर निदेशक डॉ असलम अंसारी के साथ अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

आज से महोबा के विजय सागर पक्षी विहार में होगा बर्ड एवं नेचर फेस्टिवल का आयोजन

लखनऊ। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में गुरूवार 2 फरवरी को जनपद महोबा के विजय सागर पक्षी विहार में बर्ड एवं नेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस फेस्टिवल में देश के प्रतिष्ठित ईको.टूरिज्म ऑपरेटर, ट्रेवल राइटर, पक्षी प्रेमी एवं पर्यावरण विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। यह जानकारी देते हुए निदेशक ईको.पर्यटन बोर्ड प्रखर मिश्रा ने बताया कि 2 फरवरी को मुख्य कार्यक्रम में लगभग 1 हजार मेहमानों के शामिल होने की संभावना है। इस अवसर पर प्रातः बर्ड वाचिंग ट्रीप का आयोजन किया गया है। इसके पश्चात पक्षियों एवं ईको.टूरिज्म से सम्बंधित प्रस्तुतिकरण किया जायेगा। शाम को अतिथियों को महोबा क्षेत्र का स्थानीय भ्रमण कराया जायेगा। निदेशक ने बताया कि 3 फरवरी को ईको.टूरिज्म टूर ऑपरेटर बांदा स्थित कालिंजर किले तथा चित्रकूट में ईको टूरिज्म स्थलों का भ्रमण करेंगे। अगले दिन 4 फरवरी को ईको टूरिज्म टूल ऑपरेटर प्रयागराज होते हुए वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे। वाराणसी में क्रूज की यात्रा के पश्चात वाराणसी में नवस्थापित टेन्ट सिटी में रात्रि विश्राम करेंगे। श्री मिश्र ने बताया कि 5 फरवरी को ईको.टूरिज्म टूर ऑपरेटर प्रातः वाराणसी का स्थलीय भ्रमण करने के पश्चात दिल्ली रवाना होंगे। इस कार्यक्रम से ईको.टूरिज्म की प्रदेश में असीम संभावनाओं का व्यापक प्रचार.प्रसार होगा तथा बुंदेलखण्ड क्षेत्र में स्थित विजय सागर पक्षी विहारए उत्तर प्रदेशए मध्य प्रदेश तथा देश के विभिन्न प्रांतों के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनेगा।

सहारा हॉस्पिटल के पैथोलॉजी सैम्पल कलेक्शन सेन्टर का शुभारम्भ

लखनऊ। सहारा इंडिया परिवार के 46 वें स्थापना दिवस के अवसर पर बुधवार को गोमतीनगर स्थित सहारा हॉस्पिटल के पैथोलॉजी सैम्पल कलेक्शन सेन्टर का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर सौ से अधिक लोगों की शुगर की निःशुल्क जांच की गयी और छोटी.बड़ी सभी जांचों के लिए बीस प्रतिशत की छूट ऑफर दिया गया। सेन्टर का उद्घाटन हॉस्पिटल के डायेक्टर मेडिकल केयर डा मजहर हुसैन और सहारा इंडिया परिवार के सीनियर एडवाइजर अनिल विक्रम सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस सेन्टर पर लोग किसी भी डाक्टर या अस्पताल या फिर अपनी स्वेच्छा से भी अपनी जांच करवा सकते हैं।

अगले सप्ताह यूपी से पांच यूनिवर्सिटी जायेंगी क्यूएस रैंकिंग में

लखनऊ। दुनिया के टॉप शैक्षणिक संस्थानों में शामिल होने के लिए अगले सप्ताह क्यूएस रैंकिंग के लिए उपक्रम के जरिए प्रदेश के पांच विश्वविद्यालयों द्वारा आवेदन किया जायेगा। इनमें लखनऊ विश्वविद्यालय, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, सीसीएस मेरठ और एमजेपी रूहेलखंड विश्वविद्यालय और ट्रिपल आईआईटी शामिल है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में जानकारी देते हुए उपक्रम की महानिदेशक प्रो. पुनम टंडन ने बताया कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बेहतर भविष्य के लिए ऐसे ही शिक्षण संस्थान का मूल्यांकन करती है, जो बेहतर क्वालिटी की शिक्षा प्रदान करते हो। एक शैक्षणिक संस्थान और उसके शिक्षण की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए, रेटिंग प्रणाली छात्रों की प्रतिक्रिया, छात्र अनुपात के लिए फैकल्टी, डिग्री पूर्ण होने की दर जैसे विभिन्न तरीकों को अपनाती है। इसके अलावा यह टीचरों के एक विभिन्न समूह के साथ एक्टिव एजुकेशन और सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है, जिसमें छात्रों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक कम्पलीट विजन शामिल होता है। बता दें कि क्वाक्वेर्ली सायमंड्स द्वारा हर साल क्यूएस रैंकिंग जारी की जाती है।

कूड़ा कलेक्शन के लिए डोर टू डोर अभियान की शुरुआत

● कूड़ा कलेक्शन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने समस्त नगरीय निकायों में सूखे और गीले कचरे का शत प्रतिशत डोर टू डोर कलेक्शन करने के लिए 1 फरवरी से 31 मार्च तक 3 चरणों में चलने वाले 10तक डोर टू डोर अभियान का राज्यव्यापी शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने नागरिकों से प्रातः 10 बजे तक गीला और सूखा कचरा पृथक कर अपने घरों, संस्थानों से बाहर निकाल कर कूड़ा कलेक्शन गाड़ियों को देने की अपील की। नगर विकास मंत्री ने नगरी निकाय निदेशालय में आयोजित कार्यक्रम में इस अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाली 20 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। साथ ही होम कंपोस्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए लखनऊ की 10 महिलाओं को होम कम्पोस्टर भी प्रदान किए। उन्होंने कहा कि इस होम कंपोस्टर में 15 दिन तक किचन से निकला कचरा रखने पर खाद बन जाएगी जिसका प्रयोग घर के गमलों और बागवानी में किया जा सकता है।

नगर विकास मंत्री की उपस्थिति में 5 संस्थाओं के प्रतिनिधियों और नगर विकास विभाग के बीच एमओयू हस्ताक्षरित किये गये। ये संस्थाएं प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सतत एवं समग्र विकास के लिए नीति निर्धारण, तकनीकी सहयोग एवं क्षमता संवर्धन में सहायक होंगी। संस्थाएं नगरों के विकास में सहयोग एवं सलाह प्रदान करेंगी। इसमें जनाग्रह सेंटर फॉर सिटिजनशिप एण्ड डेमोक्रेसी शहरों के गवर्नेंस सिस्टम को मजबूत करने, कार्मिकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार करने में सहयोग प्रदान करेगी। टेरी द्वारा एकीकृत शहरी जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, सर्कुलर इकोनॉमी, वेस्ट मैनेजमेंट पर कार्य करेगी।

सनातन संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने अपर मुख्य सचिव खेलकूद से की मुलाकात

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह ने चंदौली जनपद में दो दिवसीय राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित कराने के लिए बुधवार को बापू भवन में अपर मुख्य सचिव खेलकूद डा नवनीत सहगल से मुलाकात की। इस संबंध में विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह ने बताया कि लखनऊ में अपर मुख्य सचिव खेलकूद डा नवनीत सहगल से मुलाकात हुईए जिसमे सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के आठ अति पिछड़ा घोषित जिलों में एक चंदौली जिला के युवाओं को खेल कूद में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्वर्गीय अमरनाथ सिंह के पुण्य तिथि पर राज्य स्तरीय दो दिवसीय खेल कूद एथलेटिक प्रतियोगिता कराने की स्वीकृत मिल गई है। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों से बात चीत कर प्रगति पर है। कार्यक्रम फरवरी माह में संभावित है जिसकी तिथि जल्द ही घोषित कर दी जाएगी।

दिल के मरीजों के लिए बलरामपुर में खुलेगी कैथ लैब

● जल्द ही शुरू होगा प्लास्टिक सर्जरी विभाग

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

दिल के मरीजों के लिए खबर अच्छी है। बलरामपुर अस्पताल में जल्द ही कैथ लैब का शुभारंभ होगा। इसके साथ ही अस्पताल में जल्द कई अन्य सुविधायें भी बढ़ने जा रही है। अभी यहां पर 756 बेड पर मरीजों को इलाज मुहैया कराया जा रहा है। यह जानकारी बुधवार को सीएमएस डॉ जीपी गुप्ता ने दी है।

बुधवार को एक प्रेस कान्फ्रेंस में डॉ गुप्ता ने बताया कि अस्पताल में जल्द ही प्लास्टिक सर्जरी विभाग फिर से शुरू कराया जाएगा ताकि मरीजों को राहत मिल सके। वहीं दिल के मरीजों के लिए कैथ लैब स्थापित की जाएगी। अभी कॉर्डियोलॉजी विभाग की ओपीडी का संचालन किया जा रहा है। भर्ती कर मरीजों को इलाज मुहैया कराया जा रहा है। एंजियोग्राफी व एंजियोप्लास्टी जैसी सुविधा नहीं है। वहीं अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डा हिमांशू चतुर्वेदी ने बताया कि अभी आठ ऑपरेशन थिएटर हैं। हर रोज 45 ऑपरेशन हो रहे हैं। अब मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर तैयार किया जाएगा। मॉर्डन किचन की सुविधा होगी। 300 किलोवॉट का सोलर पैनल लगाया जाएगा।

ये सुविधायें भी बढ़ेंगी

- लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा।
- सभी बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा होगी।
- कैंसर विभाग का विस्तार किया जाएगा।
- त्वचा रोग विभाग में लेजर की सुविधा होगी।

नैक टीम केजीएमयू के दौरे पर आज से

लखनऊ। नैक से ग्रेडिंग को लेकर नैक की टीम गुरुवार को किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी आयेगी। टीम इलाज शिक्षण कार्य से लेकर पर्यावरण व दूसरी व्यवस्थाओं को लेकर मानकों को परखेगी। केजीएमयू अधिकारियों का दावा है कि मानकों के आधार पर केजीएमयू को कसा गया है।

विशेषज्ञों के सुझावों पर भी अमल किया गया है। केजीएमयू में 4500 बेड हैं। 149 छोटे-बड़े भवन हैं। 77 विभागों का संचालन हो रहा है। 500 शिक्षक 800 रेजिडेंट डॉक्टर और लगभग 10 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं। नेक की आठ सदस्यीय टीम बुधवार को लखनऊ पहुंच गई। नैक टीम की अध्यक्षता अमृतसर के गुरुनानक देव विश्वविद्यालय के कुलपति डा जसपाल सिंह संधू को सौंपी गई है।

जनवरी में जब्त की गई 1.73 लाख लीटर अवैध शराब, 2166 अभियुक्त गिरफ्तार

● आबकारी विभाग की अवैध कारोबारियों पर कड़ी नजर, सीमावर्ती जिलों में रखी जा रही कड़ी चौकसी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी ने कहा कि अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी के विरुद्ध लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय व राज्य के राजमार्गों, लिंक मार्गों तथा इसके अतिरिक्त हरियाणा व दिली के बार्डर पर जनपद एवं प्रवर्तन की टीमों के साथ सघन चेकिंग भी लगातार कराई जा रही है। साथ ही ईंट-भट्ठों, आरओ, प्लांट, पुराने खंडहर तथा एकांत स्थित गोदामों, ढाबों एवं पेंट की दुकानों पर विशेष निगरानी रखने के लिए क्षेत्रीय आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन सी. ने बताया कि माह जनवरी-2023 में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री के विरुद्ध कुल 64795 छापे डाले गए। इन छापों में विभाग द्वारा 6672 मुकदमें पंजीकृत किए गए। जिसके अन्तर्गत लगभग 1.73 लाख बल्क लीटर अवैध शराब की बरामदगी की गई। अवैध शराब के कारोबार में संलग्न 2166 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के साथ-साथ आईपीसी की धाराओं में कठोर कार्रवाई कराई गई। उन्होंने बताया कि अभियान में लगभग 366174 किलोग्राम लहन की बरामदगी की गई, जिसे मौके पर नष्ट किया गया। शराब बनाने के उपकरण तथा कई भट्ठियां मौके पर तोड़ी गईं। अभियान के दौरान तस्कारी के प्रयोग में लाए गए 30 वाहन भी जब्त किए गए। प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान आबकारी एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा महत्वपूर्ण कामयाबी दर्ज की गई। इसके अन्तर्गत 21 जनवरी 2023 को जनपद बस्ती में आबकारी एवं थाना रुद्धौली द्वारा संयुक्त चेकिंग के दौरान मारूति ब्रेजा व होंडा मोबिलयों कार से अन्य प्रान्त में बिक्री के लिए अनुमन्य कुल 802 बोतलें जब्त करते हुए एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई तथा आबकारी अधिनियम की धारा 60/63/72 में मुकदमा दर्ज किया गया। इसी प्रकार मथुरा में 16 जनवरी 2023 को आबकारी व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा यमुना एक्सप्रेस वे पर चेकिंग के दौरान एक कार में 20 पेटी इम्पीरियल ब्लू ब्रांड गैर प्रान्त अवैध विदेशी मदिरा वरामद करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध थाना मॉट में सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया।

बजट पर बोले उप मुख्यमंत्री केशव

आम जनता, किसान-युवा, महिलाओं व हर वर्ग के लिए है कल्याणकारी

पायनियर समाचार सेवा। वाराणसी

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी दौरे पर हैं। डिप्टी सीएम करीब बारह बजे बाबतपुर एयरपोर्ट से शहर के लिए रवाना हुए। आज पेश हुए आम बजट पर उप मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी। बोले- पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में आकर बजट के बारे में बात करना मेरे लिए गर्व की बात है। बजट में सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। आम जनता हो, किसान हो, युवा और महिला हर वर्ग के लिए, ये बजट कल्याणकारी है। ये बजट भारत को विश्व में अग्रसर बनाने की ओर है।

बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा मे साल 2023-24 का बजट पेश किया। इसमें मध्यम वर्ग, किसानों और गरीबों को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने कई बड़े एलान किए। जिसमें टैक्स कटौती समेत महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात दी गई। वितमंत्री ने एलान किया कि अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले ये सीमा 5 लाख रूपये तक की थी। अभी सालाना पांच लाख तक की आय पर लोग कोई आय टैक्स नहीं देते। इस स्तर को न्यू टैक्स रिजीम में सात लाख करने का प्रस्ताव रखा गया है। साल 2020 में पर्सनल टैक्स रिजीम में छह दरें जो दी गई थीं, इसे घटा कर पांच स्तर तक किया जाएगा।

बजट व्यापक, प्रगतिशील और समावेशीः प्रो. माथुर

पायनियर समाचार सेवा। वाराणसी

एफएमएस, बीएचयू के डीन एंड हेड प्रो. एच पी माथुर ने 2023-24 के लिए प्रस्तावित बजट को व्यापक, प्रगतिशील और समावेशी कहा है। कहा कि हमारी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए बढ़ती खपत और समावेशिता जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर जोर एक सकारात्मक कदम है। सरकार ने पूंजी निवेश पर जोर दिया है जो खपत को बढ़ावा देगा और रोजगार पैदा करेगा, इन दोनों पर विशेष रूप से महामारी के मद्देनजर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है। बजट निरंतर आर्थिक विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है, जिसे भारत को खपत-आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए लक्षित घोषणाओं, छूट और सुधारों की झड़ी से उजागर किया गया है। बजट पर उप्र कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष, पूर्व मंत्री अजय राय ने जारी वक्तव्य में कहा कि मोदी सरकार में रोजगार नहीं, कारोबार नहीं, आमदनी नहीं, बचत नहीं, बस झूठा प्रचार और मार्केटिंग जारी है। न किसान न जवान न नौजवान किसी के लिए कोई सुविधा नहीं है। बजट में आमजनों के लिये कोई प्रावधान नहीं है। अमृत काल में आम इंसान अमृत के लिये तरस रहा है। इस बजट से पूंजीपतियों की लूट और आसान हो गई है। भाजपाई बजट महंगाई व बेरोजगारी का पर्याय है। किसान, मजदूर, युवा, महिला नौकरीपेशा, व्यापारी वर्ग में इससे आशा नहीं निराशा बढ़ती है क्योंकि ये चंद बड़े लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिए बना है।

स्वच्छ वायु-दीर्घ आयु थीम पर प्रदूषण नियंत्रण कार्यशाला का हुआ आयोजन

ऊंचाहार। एनटीपीसी उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के सौजन्य से एनटीपीसी ऊंचाहार में स्वच्छ वायु- दीर्घ आयु थीम पर आधारित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि रहे एनटीपीसी ऊंचाहार के कार्यकारी निदेशक अभय कुमार समैयार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यूपीपीसीबी के मुख्य पर्यावरण अधिकारी डॉ. राम करन, तकनीकी सलाहकार आर के सिंह व प्रभारीय निदेशक आशुतोष जायसवाल ने विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। विषय रायबरेली के वायु प्रदूषण के नियंत्रण और उपशमन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान पर क्षमता निर्माण पर महाप्रबंधक (मानव संसाधन एनटीपीसी सुरक्षा अकादमी) डॉ. अनिल कुमार डैंग ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि पर्यावरण हमारी वो विरासत है जिसे आदिकाल से ऋषि-मुनि व हमारे पूर्वज संरक्षित करते आए हैं कार्यशाला के दौरान एनटीपीसी लिमिटेड, आरसीसीपीएल प्राइवेट लिमिटेड, बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड व विशाखा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरण संरक्षण पर आधारित तथा उनके द्वारा इस क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का प्रस्तुतीकरण किया तथा अपने उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के विभिन्न उपायों को सभी श्रोताओं के साथ साझा किया। यूपीपीसीबी सहित एनटीपीसी लि., आरसीसीपीएल प्राइवेट लिमिटेड, बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड व विशाखा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। संचालन अपर महाप्रबंधक (पर्यावरण संरक्षण) प्रीति सिन्हा ने किया।

पक्षियों सें सीखें ट्रैफिक के नियमों का पालन करनाः के पी यादव

सोनभद्र। हिंडालको रेनूसागर पावर डिवीजन रेणुसागर प्रेक्षागृह में सड़क सुरक्षा जागरूकता माह अभियान समापन समारोह का शुभारंभ आदित्य वंदना के साथ शुरू हुआ, तत्पश्चात विद्यालय के बच्चों द्वारा सुरक्षा से संबंधित गीत गाया गया तथा हुनर दिखाते हुए सड़क सुरक्षा से सम्बंधित नाटक प्रस्तुत किया जो अत्यंत सराहनीय रहा। मुख्य अतिथि रेनूसागर पावर डिविजन के अध्यक्ष ,ऊर्जा , के पी यादव ने सड़क सुरक्षा को दिनचर्या में शामिल करने पर जोर दिया । कहा कि सुरक्षा विभाग व ट्रांसपोर्ट विभाग ने जो मुहिम चलाकर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के प्रति लोगों को जागरूक किया है वह काबिले तारीफ है। इस सड़क सुरक्षा अभियान में महिला मंडल की सदस्याओं के अलावा घरेलू महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया जो यह दर्शाता है कि हमारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान सार्थक हुआ है, मुख्य अतिथि ने कहा कि सेफ्टी बेल्ट व हेलमेट लगाना बेशक दुर्घटनाओं को कम नहीं करेगा, मगर शारीरिक नुकसान जरूर कम होगा। अंत में मुख्य अतिथि ने सुरक्षा संबंधित उदाहरण देते हुए कहा कि पेड़ पर बैठे पक्षियों को देखिए जबकि मनुष्य उनसे ज्यादा समझदार है लेकिन पक्षी जब उड़ते हैं तो कतार में उड़ते हैं इसलिए हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए और दूसरों को भी इसकी नसीहत देनी चाहिए ताकि दुर्घटनाओं में कमी आए। कार्यक्रम के मुख्य अधिकारी कैप्टन रोहित देव फरासी ने उपस्थित सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया व सड़क सुरक्षा जागरूकता माह अभियान के तहत पूरे कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत किया, अंत में कार्यक्रम का समापन ट्रांसपोर्ट विभाग के मुकेश कुमार श्रीवास्तव के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रमुख शैलेश विक्रम सिंह संजय सिंह गुलसन तिवारी सुदिप्ता नायक समीर आनंद मनीष सिंह आर सी पांडेय के अलावा अन्य विभागों के प्रमुख व महिला मंडल की सदस्य उपस्थित थे।

प्राकृतिक खेती को जानने-समझने के लिए लखीमपुर से शिवगढ़ आए कृषक

● प्राकृतिक कृषक शेषपाल सिंह से कृषकों ने ली प्रेरणा

शिवगढ़, रायबरेली। सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि को करीब से जानने और समझने के लिए लखीमपुर खीरी से शिवगढ़ क्षेत्र के कसना गांव आए। सामाजिक कार्यकर्ता एवं किसानों ने रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को करीब से जाना और समझा व संकल्प लिया कि अपने यहां जाकर प्राकृतिक खेती शुरु करने के साथ ही प्राकृतिक खेती का पंच स्तरीय बागवानी का मॉडल विकसित करेंगे। क्षेत्र के कसना गांव के रहने वाले प्राकृतिक कृषक शेषपाल सिंह पद्मश्री सुभाष पालेकर से प्रेरणा लेकर वर्ष 2017 से गोमूत्र, गोबर इत्यादि सामग्री से जीवामृत, घन जीवामृत, बीजा मृत बनाकर रसायन मुक्त खेती कर रहे हैं। बगैर किसी रासायनिक खाद एवं दवा के उनके खेतों में तैयार करीब 11 से 12 लम्बी और डेढ़ से 2 इंच मोटे गन्ने की फसल एवं पंच स्तरीय बागवानी को देखने के लिए गैर जनपदों के साथ ही दूर-दूर से किसान आते रहते हैं। लखीमपुर खीरी से सामाजिक कार्यकर्ता रवि द्विवेदी के साथ कसना आए लखीमपुर खीरी जिले के बैकवा मजरे मैगलगंज निवासी अरविंद सिंह, जमुनिया सहवाज मजरे मैगलगंज निवासी आलोक शुक्ला आदि किसानों ने प्राकृतिक खेती और पंच स्तरीय बागवानी को करीब से जाना और समझा। रवि द्विवेदी ने बताया कि वे सुभाष पालेकर जी से जुड़े हुए हैं और लगातार किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उसके साथ आए सभी कृषक प्रगतिशील कृषक हैं जो शेषपाल सिंह से प्रेरणा लेकर जा रहे हैं जो स्वयं प्राकृतिक खेती करेंगे और दूसरों को भी प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करेंगे। विदित हो कि शेषपाल सिंह ने पंच स्तरीय बागवानी का जो माडल डेवलप किया है उसमें पहले फलदार वृक्ष हैं, उसके बाद पेड़ लगे हैं जैसे आंवला, सहजन, अमरुद आदि। पेड़ों के नीचे एवं बीच में झाड़ियों वाले पौधे हैं जैसे गुलाब, कागजी नींबू आदि, उसके बाद जमीन के ऊपर और जमीन पर रेंगने एवं जमीन के अन्दर होने वाली फसलें हैं। जिनमें गेंदा, सतावर, चप्पल कद्दू, हल्दी, रजनीगंधा, ग्लेडियस इत्यादि फसलें शामिल हैं। शेषपाल सिंह कम लागत, कम मेहनत में उन्नतशील औद्योगिक खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। शेषपाल सिंह बताते हैं कि एक देशी गाय के गोमूत्र और गोबर से बगैर किसी रासायनिक खाद दवा का प्रयोग किए 30 एकड़ उन्नतशील खेती की जा सकती है।

हल्दी पाउडर, गुड़, राब बनाकर कमा रहे अच्छा लाभ

शेषपाल सिंह हल्दी पाउडर बनाकर महंगे दामों में बेचते हैं, जिसे खरीदने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं। शेषपाल सिंह बताते हैं कि वे जो हल्दी पाउडर बेचते हैं पूरी तरह से रसायन मुक्त होने के साथ ही बगैर उबाली हल्दी का पाउडर है जो सेहत के लिए फायदेमंद और अधिक गुणकारी है। इसके साथ ही रसायन मुक्त गन्ने का रस निकालकर गुड़ और राब बनाकर उसे महंगे दामों में बेचकर अच्छा लाभ कमा रहे हैं।

क्विक न्यूज

अपहरण की सूचना से परिजनों में हड़कम्प

लालगंज रायबरेली। युवक द्वारा अपने ही अपहरण की सूचना से परिजनों में हड़कम्प मच गया। मामले की सूचना पर पुलिस ने छानबीन प्रारम्भ करते हुए सर्विलांस की मदद से उसे खोजने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। पुलिस मामले में आर्थिक तंगी(लेनदेन) के एंगल से जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के भीरा गोविंदपुर गांव निवासी एक युवक ने अपने परिचितों को मोबाईल पर मैसेज भेजकर बताया कि उसकी बाईक बोलेरो गाड़ी से टकरा गई थी। जिसके बाद बोलेरो सवार युवको ने उसका बाईक समेत अपहरण कर लिया है और उसे लेकर डलमऊ की ओर जा रहे हैं। जिसके बाद उसके परिचितों व परिजनों में हड़कम्प मच गया। जिसके बाद मामले की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक की बहन का वैवाहिक समारोह होना है जिसमें पैसे आदि को लेकर मनगढ़ंत कहानी पीड़ित द्वारा बताई जा रही है।

दो भाईयों पर लाखों की चोरी करने का आरोप

लालगंज रायबरेली। मुर्गी फार्म की सुरक्षा में तैनात दो भाइयों पर लाखों की चोरी करने का आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। जानकारी के अनुसार पूरे बिंदा सिंह मजरे कोरिहरा गांव निवासी धर्मेंद्र सिंह पुत्र स्व0 गयाबक्श सिंह ने पुलिस को दिये गये शिकायती पत्र में बताया कि गांव में ही उसका मुर्गी फार्म है। जिसकी सुरक्षा में नवाबगंज थाना मौरावा जनपद उन्नाव निवासी सगे भाई मयंक सिंह, अभय सिंह पुत्रगण अवधेस सिंह को रखा गया था। पीड़ित का आरोप है कि बीती रात लगभग एक बजे दोनों आरोपियों ने मिलकर फार्म में मौजूद तीन हजार से अधिक मुर्गी के बच्चे, दस बोरी दाना, जनरेटर तथा बर्तन आदि लेकर चले गये है। पीड़ित की माने तो आरोपियों की वजह से उसे लगभग पांच लाख से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है। कोतवाली प्रभारी शिवशंकर सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

पथ संचलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया

ऊंचाहार(रायबरेली)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा बुधवार को नगर में पथ संचलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें कार्यकर्ताओं द्वारा 85 मीटर लम्बा तिरंगा ध्वज लेकर बच्चों की टोली के साथ संघ के कार्यकर्ताओं ने नगर का भ्रमण किया। यह पदसंचलन यात्रा बुधवार की सुबह नगर के रामलीला मैदान से शुरू हुई। कार्यक्रम रेलवे स्टेशन रोड, बस स्टेशन, थाना रोड, मुख्य चौराहा का भ्रमण करते हुए रामलीला मैदान में समाप्त हुआ है। इस दौरान बच्चों ने वंदे मातरम, भारत माता की जय के उद्घोष के साथ जयकारे लगाए गए। समूचा कस्बा भगवामय होते हुए जयकारों से गूंज उठा। इस बीच लोगों द्वारा फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत भी किया गया। रास्ते में राष्ट्रभक्त व राष्ट्रप्रेम का संदेश देते हुए कार्यकर्ताओं ने पूरे नगर के माहौल को राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कर दिया था। इस आयोजन में बड़ी संख्या में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज एनटीपीसी तथा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अरखा के बच्चों और अध्यापकों ने मुख्य रूप से सहभाग किया। कार्यक्रम जिला विभाग प्रचारक राहुल, जिला प्रचारक बृजेश तथा जिला प्रचार प्रमुख सर्वेश सिंह चौहान के सर्वेक्षण में आयोजित हुआ।

प्रशासन के संरक्षण में उजाड़ी जा रही हरियाली

बछरावां रायबरेली। थाना क्षेत्र में अवैध कटान बदसूरत जारी है। जिसमें पुलिस के साथ साथ वन विभाग भी गहरी नींद में सो रहे हैं । मामला थाना क्षेत्र के मैनाहार कटरा गांव का है, बुधवार को साई नदी के किनारे ठेकेदार द्वारा पुलिस की मिलीभगत के चलते नीम व चीलवल के लगभग आधा दर्जन से ज्यादा अधिक पेड़ों पर दिन दिहाड़े आरा चलवा दिया। आलम तो यह है कि लगातार क्षेत्र में चल रहे अवैध कटान पर पुलिस प्रतिबंध लगाने में नाकाम दिख रही है।

बजट चंद बड़े लोगों के लिएः देवी प्रसाद चौधरी

मीरजापुर। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने बजट पर कहा है, 'भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है पर जब जनता को पहले कुछ न दिया तो अब क्या देगी' भाजपाई बजट महंगाई व बेरोजगारी को और बढ़ाता है। किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकरीपेशा, व्यापारी वर्ग में इससे आशा नहीं, निराशा बढ़ती है क्योंकि ये चंद बड़े लोगों को ही लाभ पहुँचाने के लिए बनता है। ये बजट चुनावी बजट है किसानों के लिए कुछ नहीं है। किसानों की एमएसपी की बात नहीं की गई है, रेलवे को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। युवाओं के बारे में रोजगार के बारे मे कुछ नहीं कहा गया है। यह बहुत ही निराशाजनक बजट है।

बजट से भारत की प्रगति के संकेतः दीपक बजाज

मुग़लसराय/चन्दौली। आगामी लोकसभा चुनाव के पहले का आखिरी बजट निश्चित रूप से उम्मीदों का बजट है, जिसमें सरकार ने सबका साथ सबका विकास का प्रयास किया है, उक्त बातें आईआईए, फूड प्रॉसेसिंग कमेटी के चेयरमैन दीपक कुमार बजाज ने कहीं । बजट में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण की बात करें तो सरकार जहां श्री अन्न योजना से मोटे व पोषक अनाज को बढ़ावा दे रही है वहीं कोविड क्रेडिट गारंटी स्कीम में बजट बढ़ाकर 1 साल तक की अवधि बढ़ाना सरकार की अच्छी पहल है । खाद्य प्रसंस्करण से अकेले मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के कुल रोजगार का 12.2 प्रतिशत मिलता है। इस क्षेत्र में लॉजिस्टिक, कोल्ड चेन, कौशल विकास, पैकेजिंग, ढुलाई जैसी चुनौतियों में इस बजट में कोई विशेष प्रावधान न होना उत्साहवर्धक नहीं रहा फिर भी बजट से एक अच्छे भविष्य व भारत की प्रगति के संकेत मिलते हैं।

अमेठी में प्रशासन ने की कार्रवाई, हटाया अतिक्रमण

संवाददाता। अमेठी

सामान हटाते हुए दुकानदार

कस्बे में ककवा रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से फ्लाईओवर का निर्माण पिछले 2 वर्षों से किया जा रहा है। जिसके लिए अमेठी प्रशासन द्वारा सड़क के दोनों तरफ बने मकानों को अतिक्रमण मुक्त करने की नोटिस लगातार दी जा रही थी जिसके बावजूद वहां पर निवास करने वाले व्यापारियों और स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा था और फ्लाईओवर का निर्माण कार्य बाधित हो रहा था। ऐसे में आज सुबह 11.00 बजे के लगभग अमेठी प्रशासन द्वारा कई थानों की फोर्स के साथ कई बुलडोजर मौके पर पहुंचे और सारे अतिक्रमण पर लगातार बुलडोजर चलने लगा, जिसको देखकर व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई, व्यापारियों को अपनी दुकानों से सामान निकालने और हटाने तक का भी मौका नहीं मिला। नाराज प्रशासन के द्वारा बिना और कोई मौका देते हुए सीधे दुकानों को धराशाई कर दिया गया जिसमें मलबों के नीचे व्यापारियों के सामान दब गए। प्रशासन की इस ताबड़तोड़ कार्यवाही से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है कई दुकानें तो पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं। ऐसे में व्यापारियों में स्थानीय प्रशासन के खिलाफ खासा आक्रोश भी दिखाई पड़ रहा है। नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनूप अग्रवाल ने बताया कि आज जो प्रशासन द्वारा तोड़फोड़ की गई है यह बहुत ही बर्बरतापूर्ण कार्यवाई है। यहां तक कि व्यापारियों को सामान हटाने का भी मौका नहीं दिया गया। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि क्षेत्र निर्माण निगम के द्वारा यहां पर पुल बनना है ऐसे में जो भी अवैध अतिक्रमण यहां पर हुए थे उसको हटाने के संबंध में विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए पूर्व में नोटिस निर्गत की गई थी उसके पश्चात निशान लगाए गए थे तब आज यह कार्यवाई की जा रही है।

बच्चों को लेकर आ रही वैन स्कूल के समीप गड्ढे में पलटी, मची अफरा तफरी

सकलडीहा/चन्दौली। सकलडीह कोतवाली क्षेत्र के रानेपुर स्थित ग्रीन वैली कान्वेंट स्कूल की वैन स्कूल से दो सौ मीटर पूर्व बाइक सवार को बचाने में अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गयी। वाहन में एक दर्जन बच्चे सवार थे। वैन ड्राइवर वहां से फरार हो गया। घटना की जानकारी होने पर विद्यालय प्रबंधन और परिजनों में खलबली मच गया। एसडीएम मनोज पाठक सीओ राजेश कुमार राय कोतवाल अनिल कुमार पांडेय मौके पर पहुंचकर करीब आधा दर्जन से अधिक बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चहनिया भेजवाया। एसडीएम और सीओ ने मामले की जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया। रानेपुर स्थित ग्रीन वैली कान्वेंट स्कूल में इटवा गांव के दर्जनों बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल वैन गांव से बच्चों को लेकर आ रही थी किसामने से आ रहे वाइक सवार को पास देने के चक्कर में गड्ढे में पलट गयी। स्कूली वाहन में बैठे बच्चे चीखने चिल्लाने लगे। वैन चालक मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों की मदद से बच्चों को बाहर निकाला गया। एसडीएम व क्षेत्राधिकारी ने अपने वाहन से घायल बच्चों को चहनियां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। प्राथमिक उपचार उपरांत बच्चों को परिजन प्राइवेट हास्पिटल में इलाज के लिये अपने साथ ले गये।

सहमे बच्चों का एसडीएम व सीओ ने बढ़ाया हौसला

स्कूली वैन में कक्षा चार की छात्रा आयुषी पांडेय, कक्षा तीन की छात्रा सीता पांडेय, कक्षा दो की छात्रा लक्ष्मी पांडेय, कक्षा दो का छात्र यश पांडेय, कक्षा तीन की छात्रा आकांक्षा मौर्या, कक्षा एक का छात्र हिमांशु मौर्या, प्रीत पांडेय, कृष्णानंद पांडेय आदि छात्रों का एसडीएम मनोज पाठक व सीओ राजेश कुमार राय स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुंचकर बच्चों को खाने का सामाने देते हुए हौसला बढ़ाया।

कोच फैक्ट्री से डिब्बों की रैक लेकर जा रहा इंजन एक बोगी समेत पटरी से उतरा

लालगंज रायबरेली। मार्डन कोच फैक्ट्री से डिब्बो की रैक लेकर जा रहा इंजन एक बोगी समेत बेपटरी हो गया। मामले की सूचना मिलते ही रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में रेलवे विभाग के अधिकारियों ने इंजन व बोगी को पटरी पर लाने के लिये युद्धस्तर पर कार्य प्रारम्भ कर दिया। दुर्घटना लूप लाईन में हुई जिसके चलते रेल यातायात प्रभावित नहीं हुआ। विभाग की ओर से मामले में जांच प्रारम्भ कर दी गई है। वहीं प्रथम दृष्टया ड्राईवर द्वारा सिग्नल की अनदेखी हादसे का कारण होना बताया जा रहा है।

मार्डन कोच फैक्ट्री से 19 नवनिर्मित डिब्बो की रैक लेकर इंजन लालगंज स्टेशन के लिये निकला था। लेकिन स्टेशन से मात्र 1 किमी पहले ही रायबरेली रेलवे क्रासिंग के पास पहुंचते ही इंजन अचानक तेज आवाज से साथ डिरेल हो गया। इंजन के साथ उसके साथ लगी पीछे की एक बोगी भी बेपटरी हो गई। गेटमैन ने मामले की सूचना तत्काल स्टेशन अधीक्षक को दी जिसके बाद उच्चाधिकारियों को घटना की जानकारी दी गई। जिसके बाद पूरे रेलवे विभाग में हड़कम्प मच गया। गनीमत रही कि क्रासिंग को छूते हुए इंजन डिरेल हुआ यदि वह अपने स्थान से कुछ मीटर ही आगे बढ़ जाता तो जाम की समस्या बचाव कार्य में बाधा बन सकती थी साथ ही लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता। सुबह लगभग साढ़े पांच बजे हुए इस हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ एकत्र हो गई। पहुंची राहत व तकनीकी टीमो ने इंजन व बोगी को पटरी पर लाने के लिये दर्जनों मजदूरो के साथ कार्य प्रारम्भ कर दिया। मामले में रेलवे विभाग की जांच टीम भी सक्रिय हो गई। सूत्रों के अनुसार सुबह कोहरा काफी ज्यादा होने, सिग्नल की अनदेखी व ड्राईवर की लापरवाही आदि बिंदुओं के साथ दुर्घटना के संभावित सभी पहलुओं पर पड़ताल की जा रही है। टीम ने जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना के कारणों का पता चलने की बात कही है। दुर्घटना के 10 घंटे बाद डिरेल हुए इंजन व बोगी को पटरी पर लाया जा सका जिसके बाद रेलवे अधिकारियों ने राहत की सांस ली।

चालक व गार्ड का हुआ एल्कोहली मेडिकल परीक्षण

लालगंज। एमसीएफसे रैक लेकर आ रहे इंजन व बोगी के डिरेल होने पर विभाग की ओर से दोनों चालकों व गार्ड का सीएचसी में एल्कोहल बेसिस मेडिकल परीक्षण कराया गया। रायबरेली रेलवे विभाग के चालक आआर मीना, सहायक चालक श्रीरामऔतार व गार्ड अनिल कुमार को चिकित्सीय परीक्षण के लिये सीएचसी लाया गया था लेकिन यहां पर जांचों की सुविधा न होने के चलते उन्हें जिला चिकित्सालय भेज दिया गया।

सनबीम कॉलेज भगवानपुर में पुस्तक व क्राफ्ट मेले का हुआ आयोजन

वाराणसी। उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के निर्देशन में जी-20 सम्मलेन के प्रचार प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजन के अंतर्गत सनबीम कॉलेज फॉर विमेन भगवानपुर में दिनांक 31 जनवरी 2023 को जी-20 के प्रचार प्रसार हेतु पुस्तक व क्राफ्ट मेले का आयोजन हुआ। मेले में सनबीम कॉलेज की छात्राओं द्वारा बनाये गए पेपर क्राफ्ट, मेटल इंस्टालेशन, पेपर मचे, लिप्पन आर्ट आदि प्रदर्शित किये गए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे अर्थशास्त्र विभाग के डॉक्टर पारिजात सौरभ। उन्होंने पुस्तक मेला में कालेज की छात्राओं द्वारा बनाए गए क्राफ्ट की सराहना की। मेले में सनबीम समूह की सह निदेशिका प्रतिमा गुप्ता, कालेज प्रशासिका डॉ मधुलिका सिंह व प्राचार्य डॉ विभा श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे। कॉलेज की शिक्षक, शिक्षिका, व छात्राओं ने मेले में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया।

वंचितों पिछड़ों, गरीबों, किसानों व नौजवानों के विकास का है बजटः अनुप्रिया

● जेल में बंद गरीबों की जमानत के लिए खुद पैसा देगी सरकार, अपना दल (एस) के महत्वपूर्ण मुद्दे को बजट में किया गया शामिल ● केंद्रीय मंत्री पटेल ने प्रधानमंत्री व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जताया आभार

मीरजापुर। अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि वर्ष 2023-24 का आम बजट यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। केंद्रीय मंत्री पटेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट को वंचितों, पिछड़ों, गरीबों व किसानों के प्रति समर्पित बताया है। उन्होंने कहा कि देश के हर व्यक्ति को भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुफ्त राशन योजना को अगले एक वर्ष तक बढ़ाने की सराहनीय पहल की गई है। अब यह योजना जनवरी 2024 तक जारी रहेगी।

पटेल ने कहा कि अपना दल (एस) गरीबों, वंचितों व पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए निरंतर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की मांग करता रहा है। पार्टी यह भी कहती रही है कि आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वंचित व पिछड़ा समाज के लोग वर्षों तक जेल में पड़े रहते हैं, उनकी जमानत नहीं हो पाती है। केंद्र की लोकप्रिय नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना दल (एस) के इस महत्वपूर्ण मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए गरीबों की जमानत का पैसा खुद सरकार द्वारा वहन करने की घोषणा की है। इस सराहनीय पहल के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय वित्त मंत्री का बहुत बहुत आभार जताया।

पटेल ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने किसानों को एक साल तक लोन में छूट देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू करने की घोषणा की है, इसके तहत पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। देश के 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में 38800 शिक्षकों और स्टाफ की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा हर परिवार को मकान का सपना पूरा करने के लिए पीएम आवास योजना के बजट में 66 परसेंट की वृद्धि का सराहनीय निर्णय लिया गया है। पटेल ने कहा कि अब 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। आम बजट में मध्य वर्ग का भी खास ख्याल रखा गया है।

अपना दल (एस) के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा है कि यह बजट ऐतिहासिक, संपूर्ण समावेशी, हर एक भारतीय के जीवन में सकारात्मक बदलाव का बजट है। देश में एयर सर्विस को बढ़ावा देने के लिए 50 नए एयरपोर्ट और हेलिपैड भी बनाए जाएंगे। युवाओं के लिए 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स बनेंगे।

युवाओं का बजट

कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि आम बजट युवाओं, नौजवानों का बजट है। नए बजट में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को शुरू करने की घोषणा की गई है। 47 लाख युवाओं को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत 3 साल तक भत्ते दिए जाएंगे। युवाओं को ग्लोबल लेबल की ट्रेनिंग देने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे। देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। आम बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री ने महिला बचत सम्मान पत्र लाने की घोषणा की है। इस पर महिलाओं को 7.5 परसेंट ब्याज मिलेगा। यह पहल महिलाओं के आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था

भविष्य की उम्मीद

वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण ने उज्जवल भविष्य के बारे में बहुत उम्मीद जताई है और उसकी ये उम्मीदें यथार्थ पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी कहा है कि आज सारी दुनिया की नजरें भारत की अर्थव्यवस्था पर टिकी हैं। हालांकि, 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी की वृद्धि दर वर्तमान वित्त वर्ष से थोड़ी कम होने की आशंका है, पर भविष्य में अच्छे दिन आने वाले हैं। 400 से अधिक पेजों में फैले आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का यही संदेश है। वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में सर्वेक्षण की रिपोर्ट पटल पर रखी। इसमें भविष्य के प्रति आशा के अनेक संकेत हैं। हालांकि, सर्वेक्षण ने 2023-24 के लिए वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है, जबकि यह 2022-23 में 7 प्रतिशत तथा पिछले वित्त वर्ष में 8.7 प्रतिशत थी। लेकिन सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि महामारी से भारत तुलनात्मक रूप से तेजी से उबरा है तथा आने वाले वर्ष में वृद्धि ठोस रूप से घरेलू मांग तथा पूंजी निवेश के कारण होगी। उसका यह कहना ठीक है कि वर्तमान समय में वृद्धि दर को अनेक ढांचागत परिवर्तनों से सहायता मिल रही है जिनका क्रियान्वयन पिछले सालों में, खासतौर से 2014 के बाद किया गया है। सर्वेक्षण में संकेत किया गया है कि 'वित्तीय व्यवस्था पर दबाव' 2014 के पहले दिए गए भारी कर्ज के कारण था जिनकी अभिव्यक्ति गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों, कर्ज में कम वृद्धि तथा पूंजी सृजन की कम वृद्धि दर के रूप में सामने आई। अब महामारी के कारण पैदा

सुस्ती से बहाली वाले समय की तरह दबाव के वे साल पीछे छूट गए हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार वेंकटरमन अनंत नागेश्वरन ने पिछले कुछ वर्षों की स्थितियों पर भी नजर डाली है जिनमें 1998-2002 के वर्ष शामिल हैं। लगभग दो दशक पहले सरकार ने परिवर्तनकारी सुधार किए थे, पर अर्थव्यवस्था को लगे अस्थाई झटकों के कारण आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुई। जब ये झटके कमजोर पड़े तो 2003 से ढांचागत सुधारों ने अच्छा लाभ दिखाया।

वेंकटरमन का आशावाद न केवल इतिहास, बल्कि यथार्थ पर भी आधारित है। आमतौर पर उन्होंने सर्वेक्षण में एक गुलाबी तस्वीर पेश की है। वित्त वर्ष 15 के बाद 2022-23 की पहली छमाही में निजी उपभोग सर्वाधिक था तथा केन्द्र सरकार द्वारा बढ़ाए पूंजीगत खर्च के कारण निजी निवेश में तेजी आई है जिससे निगमों की बैलेंसशीटों में मजबूती आई है। इसके साथ ही एमएसएमई क्षेत्र में कर्ज की वृद्धि अच्छी है, अप्रैल-दिसंबर 2022 में अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारतीय रुपये ने बेहतर प्रदर्शन किया है, शहरी बेरोजगारी दर घटी है, खुदरा मुद्रास्फीति पर लगाम लगी है, अप्रैल-नवंबर 2022 में प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि हुई है तथा बेहतर व स्वस्थ होती बैलेंसशीटों से नए कर्ज का चक्र शुरू हुआ है। पिछले महीनों में बैंक कर्जों में दो अंक का उछाल आया है। लेकिन सर्वाधिक रोजगार का सृजन करने वाले विनिर्माण क्षेत्र की प्रगति इतनी अच्छी नहीं रही है। सर्वेक्षण में स्वीकार किया गया है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 'वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही में विनिर्माण क्षेत्र में थोड़ा घटा है'। लेकिन आशा प्रकट की गई है कि 'विदेशी मुद्रा का प्रवाह पूर्व-महामारी स्तरों से काफी ऊपर बना हुआ है जिसका कारण सरकार द्वारा बिजनेस सुगमता के लिए उठाए गए ढांचागत सुधार हैं।' भारत की तेज होती आर्थिक प्रगति के बावजूद बदलती हुई विश्व परिस्थितियों के कारण समस्यायें बनी हुई हैं। इनके चलते जनवरी-नवंबर 2022 में 2021 के इसी कालखंड की तुलना में औद्योगिक निवेश में कमी आई है। इसका एक कारण अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों द्वारा पैसे को आकर्षित करने के लिए अपनाई नीतियां भी हैं। वैसे कुल मिला कर आर्थिक सर्वेक्षण ने यथार्थवादी तस्वीर सामने रख कर भविष्य के प्रति पूरी उम्मीद जताई है।

तेजी से प्रगति करती अर्थव्यवस्था

भारत सरकार ने सबकी उम्मीदों पर ध्यान देते हुए बजट में सभी क्षेत्रों के लिए समुचित आबंटन किए हैं। इनसे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी।

रवि कुमार गुप्ता
रोहन गुप्ता
(लेखक, पेशे से अध्यापक हैं)

वित्तमंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने अन्य मंत्रियों के साथ मिल कर बजट तैयार किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए 'प्राप्तियों व खर्च की सूची सरकार को संसद के पटल पर रखनी चाहिए।' भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से प्रगति के रास्ते पर है। हाल में इसने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया और अब यह दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। बजटीय आबंटनों से अर्थव्यवस्था की गति और तेज होगी। उम्मीद की जाती है कि भारत 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इसके लिए सभी क्षेत्रों में बजट आबंटन बढ़ना चाहिए। अनेक अर्थशास्त्रियों व विशेषज्ञों ने पहले ही अनुमान लगाया था कि बजट 2023-24 संतुलित होगा। आर्थिक वृद्धि के लिए हर आयाम पर बुद्धिमानी से जोर देना जरूरी है। इनमें ढांचागत संरचना, शिक्षा, कर, प्रावीडेंट फंड, कर स्लैबों, सब्सिडी, उत्पादन से जुड़ी योजनाओं को प्रोत्साहन, विनिर्माण व सेवा क्षेत्र को बढ़ावा, सेमीकंडक्टर-आधारित औद्योगिक अवस्थापनायें, स्वास्थ्य, बैंकिंग, आवास, रक्षा तथा ग्रामीण आवश्यकतायें व मांगें शामिल हैं। कोविड-19 वैश्विक महामारी तथा रूस-यूक्रेन युद्ध ने वर्ष 2020-2022 में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और जीडीपी पर गहरा प्रभाव डाला है। भारत पर भी इसका काफी प्रभाव पड़ा है। विनिर्माण व सेवा क्षेत्र में सुस्ती के कारण रोजगारों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। हालांकि, सभी क्षेत्रों समुचित बजटीय आबंटनों से इन प्रभावों से निपटने में काफी सहायता मिलेगी।

शिक्षा समग्र विकास का महत्वपूर्ण औजार है। शिक्षा के अवसर सारी जनता को मिलने चाहिए। शिक्षा का कौशल व सीखने के प्रति उन्मुखीकरण बढ़ाने के लिए अच्छी किताबों, प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं व ढांचागत संरचना की जरूरत है। पिछले साल शिक्षा बजट में 11 प्रतिशत बढ़ोत्तरी कर इसे कुल जीडीपी का 3.1 प्रतिशत कर दिया गया था। अनेक शिक्षाशास्त्री इसे नाकाफी बताते हैं और वे इसे जीडीपी के 6 प्रतिशत तक ले जाने की आवश्यकता बताते रहे हैं। टैक्स भारत में समेकित निधि को मजबूत करने वाली प्राप्तियों में सर्व प्रमुख हैं। कर प्रत्यक्ष कर हो सकते हैं जिनको व्यक्तियों से आयकर, कार्पोरेट कर, संपत्ति कर, आदि के माध्यम से एकत्र किया जाता है। इसके साथ ही जीएसटी, स्टेट एक्साइज़ ड्यूटी, आदि के माध्यम से करों का परोक्ष संग्रह होता है। वित्त वर्ष 2022 में कर राजस्व व जीडीपी का अनुपात लगभग 17.11 प्रतिशत था। इस वित्त वर्ष में इसके बढ़ने का अनुमान पहले से लगाया जा रहा था। अक्टूबर, 2022 में जीएसटी संग्रह रिकार्ड 1.52 लाख करोड़ दर्ज हुआ जो एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन अनेक लोग अब भी कर नियमों में कमियों का अनुचित लाभ उठाते हुए कर देने से बचते हैं। अच्छी कर व्यवस्था के पांच प्रमुख आयाम हैं-न्यायोचित होना, सरलता, पारदर्शिता, सटीकता तथा प्रशासनिक सुगमता। पूंजी बाजार में निवेश भी ढांचागत संरचना में निवेश की तरह महत्वपूर्ण है इससे विनिर्माण, रोजगार, पर्यटन व बाजार में तेजी आने की संभावना तेज होती है। पूंजी बाजार का आधार मुख्यत: प्रावीडेंट फंड, म्यूचुअल फंड, एलआईसी प्रीमियम, एनएससी, बांड व अन्य सरकार द्वारा अधिकृत निवेश हैं जिनसे एक निश्चित समय में लाभ सुनिश्चित होता है। आयकर की धारा 80सी के अंतर्गत हमें कर कटौती में रियायत मिलती है। वर्तमान समय में यह सीमा 1.5 लाख थी जिसे कम से कम 50,000 रुपये बढ़ाने की विशेषज्ञों ने संस्तुति की थी। 2014 के बाद से इसमें संशोधन नहीं किया गया था। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मुद्रास्फीति को देखते हुए इसमें परिवर्तन अच्छा रहेगा।

पिछले वर्षों में जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान घटा है। वित्त वर्ष 2012 में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान जीवीए में 17.4 प्रतिशत था जो वित्त वर्ष 2021 में घट कर 14.5 प्रतिशत रह गया। सरकार ने इस क्षेत्र में पूंजीगत खर्च बढ़ाया है। इससे रोजगार सृजन तथा निर्यात बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इससे अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी होगी। विभिन्न एलेक्ट्रानिक उपकरणों, जैसे वाहनों, मोबाइल फोनों व अन्य उपकरणों में चिप्स के प्रयोग से सेमीकंडक्टर चिपों की मांग में कई गुना वृद्धि हुई है। चिपों की पूर्ति मुख्यत: जापान, ताइवान व चीन से आयात द्वारा होती है। सरकार ने इनकी स्वदेशी आपूर्ति बढ़ाने की दिशा में कई कदम बढ़ाए हैं। निजी क्षेत्र के सहयोग से चिपों के उत्पादन में सहायता मिल सकती है। विनिवेश का अर्थ निवेशित परिसंपत्तियों की बिक्री है। सरकार इस प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों-पीएसयू व पीएसयू के शेयरों को बेचती है। पिछले तीन साल में सरकार ने अनेक विनिवेशों की घोषणा की थी, लेकिन वह यह लक्ष्य पूरा करने में सफल नहीं हुई। बीपीसीएल, ओआईएल, आदि पीएसयू मुनाफे वाली कंपनियां हैं। अर्थशास्त्रियों के विचार से इनका विनिवेश नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो भी इसे ज्यादा ऊंचे स्तर पर नहीं ले जाना चाहिए। उच्च विनिवेश से राजस्व प्राप्त होता है, जबकि कम विनिवेश से सरकार को भावी निवेश से मुक्ति मिलती है। अत: विनिवेश में सावधानी बरती जानी चाहिए।

हमारा देश दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन सरकार द्वारा सब्सिडी पर भारी धनराशि खर्च करना आश्चर्यजनक है। खाद्य व उर्वरक सब्सिडी का जीडीपी में आठवां या 12 प्रतिशत हिस्सा है। उर्वरक सब्सिडी पर 2.3 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है जिसे घटा कर 1.4 लाख किया जा सकता है। इसी प्रकार खाद्य सब्सिडी को भी 2.7 लाख करोड़ से घटा कर 2.3 लाख करोड़ किया जा सकता है। यदि सरकार राजकोषीय घाटा कम करना चाहती है तो उसे सब्सिडी अवश्य घटानी चाहिए। उसे निश्चित रूप से राजकोषीय घाटे के मामले में संतुलन बरतना चाहिए तथा इसे वर्तमान वित्त वर्ष में जीडीपी के 6.4 प्रतिशत पर लाने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान समय में भारत में 83,000 से अधिक स्टार्टअप व 100 से अधिक यूनीकार्न हैं। दुनिया भर में कोरोनावायरस वैश्विक महामारी तथा मंदी के प्रभाव के कारण स्टार्टअप को पैसा मिलना कठिन हुआ है। इसलिए भारत सरकार शुरू से ही स्टार्टअप को समर्थन देने की नीति पर चल रही है। अनेक अर्थशास्त्रियों का अनुमान था कि सरकार स्टार्टअप के बिजनेस क्षेत्र में विस्तार कर इनका बिजनेस और सुगम बनाएगी। उल्लेखनीय है कि स्टार्टअप कुशल उद्यमियों व नौजवानों को रोजगार प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही स्टार्टअप का मूल्य 500 बिलियन डालर का आंकड़ा पार कर जाएगा। सरकार को स्टार्टअप का काम आसान बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं तथा विनियमों की घोषणा करनी चाहिए।

'आत्मनिर्भर भारत' का लक्ष्य रक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत कर प्राप्त किया जा सकता है। स्टाकहोम रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार हिंद-प्रशांत देशों में हथियारों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के मामले में भारत का चौथा स्थान है, पर भारत हथियारों व रक्षा उपकरणों के आयात के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। लेकिन इसके बावजूद भारत ने 14,000 करोड़ रुपये का रक्षा निर्यात किया है और 2025 तक इसके 25,000 करोड़ तक पहुंचने की आशा है। राजकोषीय नीति व बजट का उद्देश्य आय व बचत बढ़ाना, निवेश दर में वृद्धि करना, उत्पादक क्षेत्रों में खर्च बढ़ाना, मूल्य स्थिरीकरण तथा असमानता घटाना है। यदि असमानता में कमी नहीं आती है तो इससे जनता में टकराव बढ़ सकते हैं जिसका असर अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक हो सकता है और इससे अस्थिरता पैदा हो सकती है। जीएसटी लागू करने से कर संग्रह में सुगमता व तेजी आई है। किसी भी देश का बजट संतुलित होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अर्थव्यवस्था के सभी आयामों पर गौर करे तथा बजट सारी जनता की उम्मीदें पूरी करने का प्रयास करे। संभवत: वर्तमान बजट इन कसौटियों पर खरा उतरता है।

अव्यवस्थाओं का शिकार विमानन उद्योग

वीवी सुंदर
(लेखक संप्रेषण विशेषज्ञ हैं)

भारतीय विमानन उद्योग अब एक तमाशा है। हाल ही में एअर इंडिया पर एक अनियंत्रित यात्री की शर्मनाक कथित घटना, यात्रियों से भरी एक बस को छोड़ कर उड़ान भरने वाली एक एयरलाइन, दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (डायल) पर व्यवस्थित अराजकता, और अन्य हवाईअड्डों पर बार-बार होने वाली और असूचित घटनाएं एक चिंता पैदा करती हैं। सवाल। उद्योग किस दिशा में जा रहा है? यात्री टर्मिनल शुल्क का भुगतान करने के बदले इन हवाई अड्डों से एक यात्री को वास्तव में क्या मिलता है? एयरलाइंस अपने दायित्वों को कैसे संभालती हैं? यात्रा को सुरक्षित और कम तनावपूर्ण बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? भारत में हवाई अड्डे और एयरलाइंस स्पष्ट रूप से उस स्तर की सेवा प्रदान नहीं करते हैं जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है। यात्रा का तनाव शुरू होता है और जारी रहता है क्योंकि हवाईअड्डे जमीनी परिस्थितियों को कैसे संभालते हैं। दुनिया के व्यस्ततम या सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे होने के उदात्त उपाधियों और ख्याति की आवश्यकता किसे है? यात्री अधिक कुशल हवाई अड्डे को पसंद करेंगे! व्यस्ततम हवाई अड्डे से केवल ऑपरेटर को लाभ होता है, ग्राहक को नहीं।

हमारे वैभवशाली हवाईअड्डों पर विचार करें, जो उल्टे भले ही एक क्रांति का सूत्रपात करते प्रतीत होते हैं। कई आधुनिक हवाई अड्डों की भव्य प्रकृति के बावजूद, अक्षमता व्यापक प्रतीत होती है। लोगों को यात्रा करने के तरीके को बदलने के लिए विमानन बनाया गया था, जिससे उन्हें अन्य तरीकों से कम समय में लंबी दूरी की यात्रा करने की अनुमति मिल सके। हवाई अड्डे इस सिद्धांत में सेंध लगाते दिखाई देते हैं। वे अधिकांश यात्रियों का बहुमूल्य समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। घरेलू यात्रा के लिए भी एयरलाइंस और एयरपोर्ट ने 2-3 घंटे का रिपोर्टिंग टाइम तय किया है। यह एक अस्वीकार्य कदम है। क्या यह अजीब नहीं है कि इतने समय में कोई विदेशी तट पर उतर सकता है? ग्राहक को केंद्र में रखे बिना एयरलाइंस और हवाई अड्डे के संचालकों द्वारा

स्थापित किए गए पैमाने केवल स्वयं-सेवा कर रहे हैं। विडंबना और समान रूप से आकर्षक यह है कि कैसे तकनीक उस बिंदु तक उन्नत हो गई है जहां यह पता लगा सकती है कि क्या किसी के दिल के वाल्व की मरम्मत की जरूरत है, जबकि हवाई अड्डे की एक्स-रे मशीनें अभी भी बैग के माध्यम से नहीं देख सकती हैं और हमें इसके बजाय पुरानी प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर करती हैं। केबिन सामान के साथ-साथ हमारे जैकेट, बेल्ट, जूते और मोजे से सामान निकालना। इस तरह की नासमझ जांच किसी भी सभ्य प्रक्रिया का अपमान है। यह सार्वजनिक अपमान का एक रूप है जिसे हम सभी आवश्यक रूप से स्वीकार करने लगे हैं। क्या हम यह कह रहे हैं कि तैनात आदमी और मशीन एक-दूसरे के प्रति इतने शंकालु हैं कि वे इस बात की दोबारा जांच करना चाहते हैं कि यात्री किसी मिशन पर अपराधी तो नहीं है? यह पुरुषों और मशीनों दोनों की क्षमताओं पर सवाल उठाता है। एक्स-रे मशीनों के संचालक उन वस्तुओं या इलेक्ट्रॉनिक्स से अपरिचित हैं जिन्हें ठीक से संभाला जाना चाहिए। हम में से कई लोगों ने हाल के वर्षों में हवाईअड्डे के सामान्य वातावरण को बिगड़ते देखा है। टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएं और तंग क्वार्टर आपको सिरदर्द देते हैं, लेकिन हवा के संचलन की कमी स्थिति को बढ़ा देती है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड में, लाइनों को नेविगेट करते समय कोई भी आसानी से अपनी जैकेट में पसीना बहा सकता है। यात्रियों के लिए इससे क्या फायदे हैं?

व्यावहारिक समाधान, जैसे चेक-इन और सुरक्षा क्षेत्रों के अंदर यात्रियों या भीड़ के आकार को साफ करने में लगने वाले अनुमानित समय को प्रदर्शित करना फायदेमंद हो सकता है। यात्रियों के तनाव के स्तर को कम किया जा सकता है यदि वे वास्तविक समय में एयरलाइन या गंतव्य प्रस्थान के क्रम में साफ हो जाते हैं। बोर्डिंग के अंत तक यात्री पूरी तरह से अपने दम पर है। इसके बजाय, यह एयरलाइन और हवाईअड्डा संचालकों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे हवाईअड्डे के अंदर आने के बाद ग्राहक को अपना लें और टिकट की कीमत और उसके द्वारा भुगतान किए गए करों के बदले में अपनी यात्रा को सुरक्षित, सुरक्षित और परेशानी मुक्त बनाएं। किसी भी सेवा प्रदाता से न्यूनतम यही अपेक्षा की जाती है।

एक यात्री को कष्ट क्यों दिया जाना चाहिए क्योंकि वह एक विशिष्ट एयरलाइन उड़ा रहा है और अन्य एयरलाइनों के साथ सार्डिन की तरह बंच है जिसकी उस समय अधिकतम क्षमता है? अनिवार्य रूप से, प्रत्येक एयरलाइन यात्री को एक ही खरगोश छेद से क्यों गुजरना चाहिए? ये पैसे बचाने के एकमात्र उद्देश्य के साथ एक अलग युग के लिए डिज़ाइन की गई प्रणालियां हैं। यह उन प्रक्रियाओं की समीक्षा करने का समय है जो घर्षण और तनाव पैदा करते हैं और उन्हें समाप्त करते हैं। हम खामोश हवाई अड्डे नहीं चाहते; हम उत्साहित हवाईअड्डे चाहते हैं। हवाईअड्डे जो ग्राहकों की जरूरतों के प्रति सचेत हैं और जो व्यावहारिक हैं। हम ऐसे हवाईअड्डे चाहते हैं जो यात्री के टर्मिनल में प्रवेश करने से लेकर प्रस्थान करने तक गति, दक्षता और देखभाल प्रदान करें।

काश, एयरपोर्ट संचालक और एयरलाइंस इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे होते। लापरवाही और हवाई रोष हवाईअड्डे, एयरलाइंस और हितधारकों के टूटे, लापरवाह और हाथों से दूर रहने वाले रवैये का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणाम है।

आप की बात

खेलो इंडिया

प्रदेश में खेलो इंडिया का शुभारंभ हो गया है । भारत सरकार की पहल पर सन 2017 में खेलो इंडिया खेल का श्री गणेश हुआ था। अब इन खेलों में जमीन से जुड़े हुए खेलों की संख्या 30 से अधिक हो गई है। जिसमें स्कूली व यूनिवर्सिटी के बच्चे खेलों में भाग लेकर आगे कदम बढ़ा रहे हैं। खेलो इंडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसके माध्यम से भिन्न-भिन्न प्रकार के खेलों से ऐसी कई प्रतिभाएं राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपना प्रदर्शन करेगी जो निश्चित ही एशियाड ओलंपिक व अन्य स्पर्धाओं में देश का नाम रोशन करेगी व इनसे एशियाड और ओलंपिक जैसे खेलों में पदकों की संख्या बढ़ेगी । 2017 से पहले जो खेल हाशिए पर जा रहे थेए अब खेलो इंडिया स्पर्धा के बाद वे पुनर्जीवित हो चुके हैं। यह भारत सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति का परिणाम है कि आज खेलो इंडिया खेलों की धूम प्रदेश ही नहीं पूरे देश में है। यह एक ऐसा मील का पत्थर है जो भविष्य में देश के नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की नई-नई पौध को प्रोत्साहित करेगा । खेलों को प्रोत्साहन देने से युवाओं व किशोरों में नशाखोरी व नेट के अत्यधिक उपयोग जैसी बुराइयों से मुक्ति पाने में सहायता मिलेगी तथा समाज व देश की समस्यायें हल करने की टीम भावना जाग्रत होगी।

हेमा हरि उपाध्याय, उज्जैन

फिलिस्तीन समस्या

अमेरिकी विदेश मंत्री ऐंटनी ब्लिंकन जब तेलअवीव पहुंचे तो लगा शायद वे फिलिस्तीन व इस्राइल के बीच तनाव घटाने आए होंगे। वे येरुसलेम,पश्चिमी तट और रामल्ला गए। बेंजामिन नेतन्याहू से शांति बरतने की अपील की। महमूद अब्बास से इस्राइली बस्ती बसाये जाने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने वही पुराना राग दोहराया कि समस्या का समाधान दो राज्यों की नीति में है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इसे समस्या का एकमात्र समाधान बताया था। मगर इसराइल ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। क्योंकि इसका अर्थ हथियाई भूमि खाली करना होगा। लेकिन यह संभव नहीं लगता है। 13 सितंबर 1993 को इजरायल के प्रधान मंत्री यित्जाक राबिन और पीएलओ के वार्ताकार महमूद अब्बास ने व्हाइट हाउस में आमतौर पर ओस्लो समझौते के रूप में संदर्भित अंतरिम स्वशासन व्यवस्था पर सिद्धांतों की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। नेतन्याहू ने 1996 में सत्ता संभालते ही इस समझौते को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इस्राइल में पुन: प्रधानमंत्री बनने के बाद नेतन्याहू शायद और कट्टर हो गए हैं। ऐसे में फिलिस्तीनी समस्या का समाधान अब और जटिल हो गया है।

जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

लाभदायक कड़कनाथ

अभी हाल ही में क्रिकेट खिलाड़ी महेन्द्र सिंह धोनी कड़कनाथ प्रजाति की और आकर्षित हुए। मुर्गे की कड़कनाथ प्रजाति को जीआई टेग मिल चूका है। इस प्रजाति के रोजगार को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। कड़कनाथ में भरपूर प्रोटीन के साथ ही फैट व कोलेस्ट्रॉल कम होता है। एक जानकारी के मुताबिक यह मुर्गा अन्य प्रजातियों के मुर्गो से बेहतर और महंगा होता है तथा इसकी तासीर गर्म होती है। इसलिए इसका सेवन ठंड में लाभकारी होता है। इसमें कोलेस्ट्रोल की मात्रा बहुत कम होती है तथा यह विटामिनों से भरपूर रक्त, हड्डियों व गहरे काले रंग का होता है। वैसे इसकी संकर प्रजातियों के रंग अलग हो सकते हैं। मध्यप्रदेश के झाबुआ और आलीराजपुर आदि जिलों के अलावा छत्तीसगढ़ की जलवायु इसके लिए हितकारी है। कड़कनाथ मुर्गा पालन केंद्र अन्य जिलों के क्षेत्रो में स्थापित कर एवं ऐप के जरिए कड़कनाथ क्षेत्र को रोजगार हेतु बढ़ाने हेतु प्रयत्न करना होगा। कड़कनाथ के प्रोत्साहन से इस क्षेत्र के आदिवासियों को बेहतर रोजगार मिलेगा व उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

संजय वर्मा, धार

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते है।

फरमाया

कांग्रेस कहीं नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा केवल अपने उद्देश्य के बारे में भ्रम पैदा करती है।

- राकेश सिन्हा
भाजपा नेता

मैंने यह यात्रा अपने या कांग्रेस के लिए नहीं की है। यह देश की जनता के लिए है।

- राहुल गांधी
कांग्रेस नेता

मैं आपको विशाखापट्टनम में आमंत्रित करता हूं जो आने वाले दिनों में हमारी राजधानी होगी।

- वाई.एस. जगन रेड्डी
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री

इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन, करोड़ों के प्रस्ताव आए

अयोध्या। माह फरवरी 2023 में प्रथम ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हेतु जनपद अयोध्या के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जनपद स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन आयुक्त कार्यालय के गांधी सभागार में किया गया। अयोध्या इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन नंद गोपाल गुप्ता नंदी मंत्री औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई निवेश उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री द्वारा अपने उदबोधन में जनपद अयोध्या में लगभग 1902 82 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए निवेशकों को सरकार द्वारा प्रदान की जा रही प्रोत्साहन सुविधाएं सहजता से उपलब्ध कराये जाने का भरोसा दिलाते हुए प्रदेश के अर्थिक विकास हेतु निवेशकों/उद्यमियों से अधिक से अधिक निवेश करने की अपेक्षा की गई। मंत्री ने सम्बोधित करते हुये कहा है कि सभी निवेशक भाईयों का निवेश किया हुआ एक-एक पायी सुरक्षित एवं संरक्षित रहेगा। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था के द्वारा भयमुक्त वातावरण का निर्माण किया गया है। इसमें सभी निवेशक भाई आज मंच पर आकर अपने निवेश की पूंजी के बारे में बता रहे हैं।

इस अवसर पर जिलाधिकारी नितीश कुमार ने कहा कि अयोध्या में पर्यटन एवं संस्कृति के क्षेत्र में बड़ी तेजी से विकास हो रहा है। जनपद में निवेश सुरक्षित एवं संरक्षित रहने के साथ अन्य निवेशकों को भी आकर्षित करेगा। जनपद में निवेश की आपार संभावनायें है। जिलाधिकारी द्वारा निवेशकों को भरोसा दिलाया गया कि निवेश हेतु निवेशकों से प्राप्त सुझाव के अनुसार जनपद में औद्योगिक विकास के अनुकूल वातावरण का सृजन किया जायेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी नितीश कुमार ने उद्योग से जुड़े हुये विशिष्ट व्यक्तियों के अलावा विधायक रूदौली राम चन्द्र

यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रोहित सिंह भी उपस्थित रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनिराज ने कहा कि अयोध्या में विशेष सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी। हम सभी निवेशकों को विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें जनपद अयोध्या में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उद्घाटन समारोह के उपरान्त उपायुक्त उद्योग, अमरेश कुमार पाण्डेय द्वारा एमएसएमई नीति-2022 एवं आगामी 10 से 12 फरवरी, 2023 को आयोजित इंवेस्टर समिट के बारे में विस्तार से बताया गया। क्षेत्रीय प्रबन्धक यूपी सीडा, केएन श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक एचपी सिंह एवं उपायुक्त उद्योग अमरेश कुमार पांडेय द्वारा अपने.अपने विभागों में चल रही योजनाओं की विस्तार से जानकारी निवेशकों को दी गयी। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहन से सम्बन्धित प्रोत्साहन नीतियों यथा टेक्सटाइल पालिसी.2022 एमएसएमई नीति.2022, आईआईईपी पालिसी.2022 पर्यटन नीति-2022 तथा बैंक द्वारा संचालित वित्तीय योजनाओं का पावर पॉइट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुतीकरण किया गया। इन्वेस्टर्स समिट.2023 में जनपद अयोध्या में अब तक एमएसएमई क्षेत्र में रू. 527.20 करोड़, यूपी सीडा में रू. 845 करोड़, पर्यटन में रू. 6176.15 करोड़, अयोध्या तथा विकास प्राधिकरण में रू. 4037 करोड़ कुल मिलकर रू. 19,042.82 करोड़ निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए है, जिसमें 44,997 रोजगार का सृजन होगा। इन्वेस्टर्स समिट में मंत्री औद्योगिक विकास उप्र लखनऊ द्वारा औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में उत्कृष्ट योग्यदान हेतु निवेशकों/उद्यमियों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया।

चकबंदी अधिकारी मिल्कीपुर की सीएम से शिकायत

● **पक्षकारों के प्रभाव में आकर एकपक्षीय निर्णय दिए जाने का लगाया आरोप**

मिल्कीपुर अयोध्या। चकबंदी अधिकारी मिल्कीपुर द्वारा राजस्व गांव पिठला के अभिलेखों में बैनामे के आधार पर दर्ज खातेदारों को बेदखल किए जाने का मामला प्रदेश के मुख्यमंत्री के दरबार जा पहुंचा है। पीड़ित खातेदार ने मुख्यमंत्री के जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत करते हुए चकबंदी अधिकारी मिल्कीपुर पर मुकदमे की सुनवाई के दौरान पक्षकारों के प्रभाव में आकर उनसे अनुचित अनुतोष प्राप्त करते हुए आदेश पारित किए जाने का आरोप लगाया है। बताते चलें कि मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र स्थित राजस्व गांव पिठला के राजस्व अभिलेखों में दर्ज गाटा संख्या 6 मि. में भूखंड का शिकायतकर्ता अरुण कुमार सिंह सहित रामऋषि एवं निर्मला देवी द्वारा बैनामा लिया गया था। जिसके आधार पर बैनामेदार राजस्व अभिलेखों सहित मौके पर काबिज एवं दाखिल चला आ रहे हैं। इस बीच न्यायालय चकबंदी अधिकारी मिल्कीपुर राकेश खन्ना द्वारा बीते 20 जनवरी 2023 को मुकदमा संख्या 644, 645, 805 व 806/2023 में 17 अक्टूबर 1967 को पूर्व चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त कर दिया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि एक चकबंदी अधिकारी के आदेश को निरस्त किए जाने के लिए दूसरे चकबंदी अधिकारी को कानून में कोई अधिकार ही नहीं दिया गया है। 2-2 बार चकबंदी प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत दो बार धारा 52 का प्रकाशन भी हो चुका है। चकबंदी अधिकारी ने मुकदमे के अन्य पक्षकार खतौनी में किस आधार पर इंद्राज किए गए हैं, इसका भी कोई न तो उल्लेख अपने द्वारा पारित आदेश में ही किया है और न ही पत्रावली में कोई साक्ष्य ही दाखिल कराया है। पीड़ित खातेदार का आरोप है कि चकबंदी अधिकारी मिल्कीपुर राकेश खन्ना ने मुकदमे के अन्य पक्षकारों से दुरभि संधि करते हुए उनसे अनुचित अनुतोष प्राप्त कर प्रार्थी सहित अन्य बैनामेदारों की अपूर्णनीय हकतल्फी की है। चकबंदी अधिकारी द्वारा मुकदमे के कुछ पक्षकारों के प्रभाव में आकर एकपक्षीय निर्णय दिया है। पीड़ित का कहना है कि तत्कालीन गाटा संख्या 6 में 146 बीघे 9 बिस्वा 10 धुर भूमि राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा जारी कई अधिसूचना के आधार पर आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज के पक्ष में अधिग्रहित की गई थी। जिसके आधार पर आज भी कृषि विवि द्वारा अपनी भूमि पर बाउंड्री वाल निर्माण करते हुए वृक्षारोपण इत्यादि कराया गया है। चकबंदी अधिकारी ने अपने आदेश में कृषि विवि के खाते में दर्ज भूमि को यथावत रखते हुए इसी भूखंड में स्थित जूनियर हाई स्कूल पीपला की 40 बीघा भूमि को भी यथावत रखा है। पीड़ित का आरोप है कि मुकदमे के अन्य पक्षकारों द्वारा केवल आधार वर्ष खतौनी ही पत्रावली में दाखिल किया गया है।

बजट में जनहितकारी नीति की झलक

अंबेडकर नगर। भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा और जनहितकारी बजट केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया है। बजट में गरीबों की जरूरतों को ध्यान में रखना भाजपा सरकार की जन हित में काम करने वाले नीति की झलक दिखाई देती है। उपरोक्त बातें भाजपा जिलाध्यक्ष डाक्टर मिथिलेश त्रिपाठी ने बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का बजट देश की प्रगति में सहायक सिद्ध होगा। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए विधान परिषद सदस्य डाक्टर हरि ओम पाण्डेय ने कहा कि बजट में गरीब, किसान, व्यवसाई सहित सभी का ध्यान रखा गया है। इससे अच्छा बजट और कुछ हो ही नही सकता है। जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि बजट में टैक्स छूट की सीमा बढ़ाए जाने से मध्यम वर्ग सहित व्यापारी और कर्मचारियों को काफी राहत मिली है। भाजपा सरकार द्वारा पेश बजट आम जनता के हितों की रक्षा करने वाला है।

एलईडी वैन को झंडा दिखाकर रवाना किया

अंबेडकरनगर। सीडीओ अनुराज जैन ने निपुण भारत मिशन जन जागरूकता अभियान एवं बालिका शिक्षा एवं सशक्तिकरण को गति प्रदान करने हेतु एलईडी वैन को झंडा दिखाकर रवाना किया गया जनपद के 120 स्थानों पर निर्धारित 2 घंटे प्रति स्थान पर 1/2/2023 से 30 दिनों तक एलईडी वैन के माध्यम से निर्धारित विषयों पर फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। एलईडी वैन प्रदर्शन का मिनट 2 मिनट कार्यक्रम दिखाया जाएगा।

खाद्यान्न का वितरण आज

अयोध्या। जिलाधिकारी नितीश कुमार ने बताया कि जनपद अयोध्या के सभी विकास खण्डों के आंगनबाड़ी केन्द्रों से पंजीकृत लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण 2 फरवरी को किया जायेगा। जनपद में संचालित 2294 आंगनबाड़ी केंद्रों (शहर परियोजना को छोड़कर) पर पंजीकृत 07 माह से 3 वर्ष के कुल 1,07,122 बच्चे, 3 से 6 वर्ष के पंजीकृत 61,138 बच्चे तथा पंजीकृत गर्भवती एवं धात्री महिलाओं माताओं 41,866 को खाद्यान्न वितरण किया जायेगा। खाद्यान्न वितरण मानक में 6 माह से 3 वर्ष के लाभार्थियों को गेहूं दलिया एक किलोग्राम, चना दाल एक किलोग्राम, सोयाबीन रिफाइन्ड 500 एमएल। 3 से 6 वर्ष के लाभार्थियों में गेहूं दलिया आधा किग्रा, चना दाल आधा किग्रा। गर्भवती/धात्री माताएं.गेहूं दलिया डेढ़ किग्रा, चना दाल एक किग्रा, सोयाबीन/ रिफायन्ड 500एमएल अतिकुपोषित बच्चे 06 माह से 06 वर्ष गेहू दलिया डेढ़ किग्रा, चना दाल दो किलोग्राम, सोयाबीन/रिफाइन्ड 500 एमएल है।

जिसकी कथनी और करनी में अंतर होता है वह समाज महान और दीर्घजीवी नहीं हो सकता

अयोध्या। विश्व हिंदू परिषद अयोध्या महानगर द्वारा आयोजित समरसता सम्मेलन अवध विश्वविद्यालय के संत कबीर सभागार में संपन्न हुआ। मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय संगठन महामंत्री विनायक दामोदर देशपांडे ने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी भारत माता के सपूत हैं। आज हम अपने देश में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं ऐसे समय में भी हमारे हिंदू समाज में सामाजिक भेदभाव एवं छुआछूत की जो भयंकर बीमारी है यह अत्यंत लज्जास्पद है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के सिद्ध संत पुरंदर दास कहते थे कि गाय और बकरी अलग.अलग रंग के हो सकते हैं परंतु क्या उनका दूध भी अलग.अलग रंग का होता है, उसी प्रकार हम सभी ऊपर से अलग-अलग दिखते हैं परंतु अंदर से हम सब एक हैं। देशपांडे ने कहा कि गुरु गोलवलकर कहते थे अस्पृश्यता का हिंदू धर्म में कोई स्थान नहीं है और विहिप का मुख्य कार्य जन जागरण एवं सेवा है। सभी में ब्रह्म है तो क्या जाति के अनुसार किसी में ब्रह्म का अंश कम या ज्यादा हो सकता है। तत्वज्ञान में हम महान हैं परंतु आचरण हमारा वैसा नहीं है और जिस समाज की कथनी और करनी में अंतर होता है वह समाज महान और दीर्घजीवी नहीं हो सकता। उन्होंने महिलाओं की दशा पर चर्चा करते हुए कहा कि प्राचीन काल में महिलाएं हमारे समाज के हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाती थी परंतु 12 वीं सदी के बाद महिलाओं की सुरक्षा हेतु उन पर बहुत से प्रतिबंध लगाए गए। गुप्त काल तक पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता परंतु महिलाओं की रक्षा हेतु पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई। बाल विवाह भी 12 वीं सदी के बाद ही प्रारंभ हुआ। यह सारी विसंगतियां मुस्लिम आक्रमणकारियों के अत्याचारों के नाते हिंदू समाज में आईं। हमारे धर्मनिष्ठ पूर्वजों ने मैला उठाना स्वीकार किया परंतु अपना धर्म नहीं बदला। उनका स्वाभिमान भंग हो गया इसलिए उन्हें भंगी कहा गया। हमारे समाज में 16: अनुसूचित जाति और 8: जनजाति हैं अगर इन 24: लोगों ने धर्म परिवर्तन कर दिया होता तो आज हमारी क्या दशा होती। हमारे इन 24: पूर्वजों के धर्म परिवर्तन न करने के कारण ही आज हम पूजा आरती कर पा रहे हैं परंतु इन कुरीतियों में हमारा भी दोष है और इन कुरीतियों से मुक्त होने का संकल्प करने के लिए ही आज का यह समरसता कार्यक्रम हो रहा है। हमें भाईचारे का निर्माण करना है। इससे पूर्व राम दरबार पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके विनायक दामोदर देशपांडे एवं तिवारी मंदिर के महंत गिरीश पति तिवारी जी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गिरीश पति तिवारी ने अपने संबोधन में श्री अयोध्या धाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा

पारब्रह्म परमेश्वर सगुण रूप श्री राम।

जो भी जन आवे यहां सब को सीताराम।।

क्विक न्यूज

विज्ञान आधारित आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने की है मुहिम

प्रयागराज। नई पीढ़ी के लोगों के बीच आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने के अपने मिशन के हिस्से के रूप में विश्व की सबसे बड़ी विज्ञान आधारित आयुर्वेद कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड ने दो क्रांतिकारी आयुर्वेदिक उत्पाद प्रीमियम शुगर फ्री हेल्थ रिस्टोरेटिव रत्नप्राश शुगर फ्री और आयुर्वेदिक डाइजेस्टिव टॉनिक आमपाचक काढ़ा को बाजार में पेश करने की घोषणा की है। रत्नप्राश शुगर फ्री एक आयुर्वेदिक मिश्रण है जो सामान्य तंदुरुस्ती को बरकरार रखने में कैलोरी के प्रति जागरूक उपभोक्ता और मधुमेह रोगी बहुत उपयोगी है। असली मोती के पोषकतत्व से भरपूर रत्नप्राश आपको पूरे दिन सक्रिय रखता है। लोग पूरे साल की किसी भी ऋतु में इसका सेवन कर सकते हैं। रत्नप्राश शुगर फ्री में असली मोती मुख्य तत्व है जो पाचनशक्ति की प्रक्रिया को संतुलित बनाये रखता है। दूसरी तरफ आमपाचक काढ़ा आयुर्वेदिक सूत्रीकरण के साथ पाचन तंत्र को मजबूत करने और भूख बढ़ाने में मदद करता है। डाबर इन्डिया लिमिटेड के मार्केटिंग हेड एथिकल डॉ दुर्गा प्रसाद ने बताया कि आयुर्वेद के हमारे एक सौ अड़तीस साल की धरोहर और प्रकृति के अमूल्य ज्ञान के साथ डाबर ने हमेशा प्रमाणभूत आयुर्वेद हस्तप्रत के अभ्यास के साथ सुरक्षित किफायती और असरकारक हेल्थकेयर पर ध्यान केन्द्रित किया है। आयुर्वेद को अधिक समकालीन बनाने और नई पीढ़ी में उसे लोकप्रिय बनाने के प्रयासरूप यूपी आयुर्वेद विभाग द्वारा प्रयागराज में आयोजित होने वाले बाजरा और पोषण पर राष्ट्रीय सेमिनार में डाबर भी भाग लेगी।

आरेडिका ने बनाया एक माह में 256 बोगी उत्पादन का रिकार्ड

रायबरेली। आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली के बोगी शॉप द्वारा जनवरी 2023 के माह में कुल 256 कोच सेट बोगी का उत्पादन किया गया, जो आरेडिका के इतिहास में किसी भी वर्ष के किसी भी माह का सर्वाधिक उत्पादन है। उल्लेखनीय कि इससे पूर्व का रिकार्ड जनवरी 2022 का है जो 254 कोच सेट बोगी का था। इस ऐतिहासिक कार्य को पूर्ण करने में बोगी शॉप तथा व्हील शॉप के कर्मचारियोंए पर्यवेक्षकों तथा अधिकारियों ने निष्ठाए समर्पण एवं मेहनत का अनुकरणीय योगदान दिया है। बोगी एवं व्हील शॉप कर्मचारियों और अधिकारियों के अनुकरणीय योगदान को देखते हुए महाप्रबंधक महोदय ने सीडब्ल्यूई फर्निशिंग एसएस कैरो और उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/बोगी एवं व्हील विनोद कुमार दुबे को बधाई दी साथ ही त्रिलोचन अंथवाल कार्य प्रबंधक बोगी एवं प्रकाश चन्द मीना एसएसई बोगी को मैन आफद मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बोगी एवं व्हील शॉप के कर्मचारियों को प्रोहत्सान हेतु ग्रुप आवार्ड भी प्रदान किया गया।

अस्थाई गौशाला का डीएम ने किया उद्घाटन

भीटी अंबेडकरनगर। महुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत कटेहरी विकासखंड के ग्राम सभा बरामदपुर लोहरा में बुधवार को डीएम सैमुअल पालऔर मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में 100 जानवर पशु आश्रयका उद्घाटन किया गया जिसमें पशु आहार भुसा उपलब्ध था वहीं पर किसान उसके बावजूद भी आवारा जानवरों से परेशान है मौके पर पशु चिकित्सा महरुआ अधीक्षक डॉक्टर बी पी सिंह मुख्य विकास अधिकारी प्रधान प्रतिनिधि उदल सिंह के मौजूदगी में ग्राम विकास अधिकारी रामप्रकाश सहित क्षेत्र के तमाम किसान मौजूद रहे।

प्रयागराज में विस्तार कराने की बनाई गयी योजना

प्रयागराज। विभिन्न प्रकार के अवसरों को लेकर उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी को और सशक्त बनाया जा रहा है। हीरे के आभूषणों के लिए ओरा ने प्रयागराज में पहला और भारत में अपना 68वां स्टोर शुरू किया। हीरे के आधुनिक आभूषणों के कलेक्शन को पेश किया जाएगा। दीपू मेहता मैनेजिंग डायरेक्टर ओरा ने कहा उत्तर प्रदेश हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें खुशी है कि हम अभिषेक रंजन अग्रवाल एवं पीयूष रंजन अग्रवाल के साथ साझेदारी में प्रयागराज के सरदार पटेल मार्ग पर अपना नया ओरा शोरूम खोलने जा रहे हैं। इस साल उत्तर प्रदेश के कई और शहरों में अपने गुणवत्तापूर्ण आभूषणों को उपलब्ध कराने और नए बाज़ारों में विस्तार की योजनाएं बनाई हैं। हम अपने लोगों को खरीददारी का बेजोड़ अनुभव प्रदान करना चाहते हैं।

नपाप द्वारा दस्तक अभियान का शुभारंभ

टाण्डा अम्बेडकरनगर। स्वछता को लेकर नपाप टाण्डा द्वारा दस्तक अभियान का शुभारंभ नपाप टाण्डा के प्रभारी अधिषाषी अधिकारी/एसडीएम दीपक वर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जो कि 31 मार्च 2023 तक 3 चरणों में चलेगा। वर्मा ने बताया कि नगर पालिका परिषद टांडा के कर्मचारियों द्वारा व्यापक जन सहयोग की अपेक्षा के साथ डोर टू डोर कंपेन करें, इस एक्टिविटी के लिए समस्त सफाई कर्मी ड्रेस में रहें और इसमें आसपास के लोगों, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा विद्यालय के छात्र छात्राओं इत्यादि को जोड़ करके एक व्यापक एवं भव्य जागरूकता रैली का रूप देना है, लोगों को सूखा और गीला कूड़ा के बारे में समझाते हुए, हरी और नीली डस्टबिन के बारे में बताते हुए, पॉलिथीन निषेध के बारे में जागरूक करते हुए सोर्स सेग्रीगेशन के बारे में बताएं।

सिंग फॉर द नेशन प्रतियोगिता होगी आयोजित

प्रयागराज। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सिंग फॉर द नेशन प्रतियोगिता की घोषणा एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने की है। सिंग फॉर द नेशन देश की सबसे लोकप्रिय प्रतियोगिता है और इंस्टाग्राम पर चल रही है। इसमें भाग लेने वालों को 18 हजार नौ सौ नब्बे रुपये का एक एलजी एक्स बूम स्पीकर जीतने का खास मौका मिलेगा। मजेदार गतिविधि के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना जगाना इस प्रतियोगिता का लक्ष्य है। एल जी बेस्ट शॉप के के डिजिटल एम जी मार्ग सिविल लाइन्स प्रयागराज में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस विषय में एलजी इलेक्ट्रानिक्स इंडिया में होम एंटरटेनमेन्टी के डायरेक्टर हाक ह्यून किम ने कहा 74वें गणतंत्र दिवस के जश्नक को जोरदार बनाते हुए एलजी इलेक्ट्रॉननिक्सड ने अपने उपभोक्ताओं के लिये अपनी तरह की एक अनोखी प्रतियोगिता सिंग विद द नेशन का आयोजन किया है। प्रतियोगिता का लक्ष्य है ग्राहकों को एलजी एक्स बूम स्पीकर के इस्तेशमाल का बेहतरीन अनुभव देना।

क्राइम प्रिवेंशन काउंसिल बांटेगा कंबल

● **संस्था ने बैठक कर लिया अहम निर्णय**

पायनियर समाचार सेवा। प्रयागराज

क्राइम प्रिवेंशन काउंसिल ऑफ इंडिया की समीक्षा बैठक मंगलवार को क्षेत्रीय कार्यालय लूकरगंज में आयोजित हुई। बैठक में परिषद की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। परिषद के नेशनल चेयरमैन डॉ एस के पांडेय ने कहा कि परिषद के हर सदस्य को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। प्रशासन को सहयोग करने और गरीबों को मदद करने के लिए हर संभव तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों के सहयोग से परिषद 12 फरवरी को संस्था कौड़िहार बाजार में जगदीशपुर चांधन गांव में दो सौ कंबल का वितरण करेगी। वहीं पांच पांच सदस्यों का ग्रुप बनाकर शहर में मलिन बस्तियों का दौरा भी किया जाएगा। जिससे गरीब परिवार की

बैठक में शामिल संस्था के पदाधिकारी।

महिलाओं बेटियों को परिषद की तरफ से निःशुल्क सेनेटरी पैड का वितरण किया जा सके। बैठक का संचालन वर्किंग चेयरमैन सलमान अहमद ने किया। धन्यवाद ज्ञापन नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉ अखिल निगम ने किया। बैठक में एस एच टी जाफरी अयूब अतुल निगम तरन्नुम निशा रागिनी देवी दुर्गेश नंदिनी कनक बागची उंजला नाज आकांक्षा निगम मो. अख्तर राजकुमार चंद्रशेखर सिंह मुनेश कुमार अस्फिया खान गोसिया परवीन नफीसा बानो हिमांशु जायसवाल दीपक कुमार चंदन कुमार जयशंकर डा अज़हर संदीप कुमार श्रीवास्तव प्रमोद भारतीय इफ्तियार अहमद शकील अहमद आदि उपस्थित रहे। यह जानकारी क्राइम प्रिवेंशन काउंसिल ऑफ इंडिया के नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी डा अखिल निगम ने दी है।

युवक को गोली मारने वाला गिरफ्तार

टाण्डा अम्बेडकर नगर। बीते सोमवार की रात्रि में अलीगंज चौराहे पर युवक को गोली मार कर घायल करने के मामले में थाना अलीगंज पुलिस ने एक नामजद अभियुक्त मो. जैद पुत्र हिदायतुल्लाह निवासी मोहल्ला अलीगंज को गिरफ्तार कर न्यायालय चालान भेज दिया है। थाने के दरोगा मय हमराह सिपाहियों के साथ क्षेत्र के रुस्तम पुर मोड़ के पास से आज बुद्धवार को दिन में लगभग 2 बजे गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि अभियुक्त मो. जैद ने बताया कि गोली लगने से घायल अखलाक उर्फ लक्खू ने कुछ माह पूर्व जबरदस्ती दबाव बनाकर एक लड़की से उसका निकाह करा दिया था जिसकी रंजिश को लेकर लक्खू को सबक सिखाने हेतु बाबू उर्फ फरीद से मिलकर योजना बनाकर बाबू उर्फ फ़रीद द्वारा लाये गये दो युवकों द्वारा लक्खू को गोली मरवा दी। तहरीर पर मो. जैद व उसके चाचा होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड के पूर्व कार्यवाहक चेयरमैन डा. अमसन्तुल्लाह व उनके पुत्र डा. रिजवान को साजिश रचने व शंका के आधार पर बाबू उर्फ फरीद तथा मो. जैद के अलावा दो अन्य के विरुद्ध मुकदमा धारा 307, 120 बी आईपीसी के तहत दर्ज कराया था। बीते सोमवार की रात्रि में लगभग 8.30 बजे अलीगंज चौराहे पर अलाव ताप रहे युवक अखलाक उर्फ लक्खू पुत्र आलम कुरेशी को अपाची बाइक पर सवार तीन लोगों ने आकर गोली मार कर फ़रार हो गए थे जिसको लेकर टाण्डा में सनसनी फैल गयी थी।

वाहन से घूम रहा संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया

भीटी। अंबेडकरनगर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी भीटी के नेतृत्व व निर्देशन अपराधियों की रोकथाम के लिए चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्ति एव संदिग्ध वाहन होटल ढाबा रात्रि गश्त के दौरान ग्राम सभा डड़ियमथानी के पास एक व्यक्ति दिखाई दिया। युवक को पुलिस ने धर दबोच लिया गश्त में निकली टीम द्वारा गिरफ्तार करके पूछताछ करने के बाद उसने अपना नाम सहित पुत्र स्वस वीरेंद्र वर्मा निवासी दोहरीपुर थाना अकबरपुर कोतवाली बताया।

मगहर महोत्सव आयोजन के बैठक के बाद एसपी के साथ स्थलीय निरीक्षण पर निकले डीएम

● **महोत्सव मर्यादा और गरिमा के अनुकूल कार्यक्रम मंच पर होंगे: डीएम**

संतकबीरनगर। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी 7 से 9 फरवरी 2023 तक मगहर महोत्सव आयोजन से सम्बंधित बैठक में कार्यक्रमों के सफल संचालन के संबंध में की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अंतिम रूप दिया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता, अपर जिलाधिकारी मनोज कुमार, मुख्य विकास अधिकारी संत कुमार उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने मगहर महोत्सव के सफल, सुव्यवस्थित एवं आकर्षक संचालन के संबंध में गठित सभी समितियों के सदस्यों को निर्धारित दायित्वों एवं जिम्मेदारियों के अनुसार पूरी लगन एवं तन्मयता के साथ कार्य करने का निर्देश देते हुए

कबीर चौरा स्थल का निरीक्षण करते जिलाधिकारी।

आवश्यक मार्ग दर्शन एवं सुझाव भी दिये। डीएम ने विभिन्न विभागीय अधिकारियों को उनके विभाग से सम्बंधित जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन के निर्देश देते हुए मगहर महोत्सव की मर्यादा और गरिमा के अनुकूल ही कार्यक्रमों के भव्य संचालन के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि संत कबीर दास की पवित्र धरती पर आयोजित होने वाले मगहर महोत्सव के माध्यम से जनसामान्य में स्वच्छ एवं स्वस्थ्य संदेश जाना चाहिए, जिससे महोत्सव में प्रतिभाग करने वाले हर आम आदमी को कबीर दास के विचारों से प्रेरणा मिल सके। पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता ने मगहर महोत्सव के सुरक्षित एवं सुचारू संचालन में चाक-चौबन्द, पुलिस व्यवस्था एवं सुरक्षा सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया।

बच्चे हैं देश के भविष्यः डीएम

● **बाल संरक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण का समापन**

श्रावस्ती। प्रदेश को अगले पांच वर्षों में बाल श्रम से मुक्त किये जाने हेतु श्रम विभाग द्वारा बाल संरक्षण जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर डीएम नेहा प्रकाश की अध्यक्षता में बाल संरक्षण के विभिन्न साझेदारों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की गई। डीएम ने जनपद में श्रम विभाग, यूनिसेफऔर उद्यमिता विकास संस्थान, उप्र के सहयोग से चलाये गये बाल संरक्षण अभियान के प्रथम चरण की समीक्षा करते हुए कार्यक्रम का समापन किया। संस्कार संस्था ने जागरूकता कार्यक्रम के दौरान सर्वे का भी कार्य किया था। कुछ बच्चे ऐसे चिन्हित किये गए थे जिनका विद्यालय में नामांकन नही था या नामांकन तो था परंतु वो बच्चे विद्यालय नही जाते थे। कुछ परिवार ऐसे भी मिले जिन्हें सरकार की कोई भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओ का लाभ नही मिला है और जिनके

बच्चे सम्भावित बाल श्रमिक हैं। संस्था ने सभी आंकड़े डीएम के सामने प्रस्तुत किये। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे बच्चों और परिवारों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाय। बच्चे देश के भविष्य है। श्रावस्ती को बालश्रम मुक्त कराये जाने हेतु बालश्रम अभियान चलाकर बाल श्रमिकों को मुक्त कराया जा रहा है। बाल श्रम अधिनियम का उल्लघंन पाये जाने पर कार्रवाई भी की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार यादव, जिला कार्यक्रम अधिकारी पीके दास, जिविनि सन्त प्रकाश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक श्रमायुक्त सन्त पाल, श्रम प्रवर्तन अधिकारी दिनेश कुमार विश्वकर्मा, बाल कल्याण समिति अध्यक्षए एएचटीयू और चाइल्ड लाइन सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

बिजली फ्री नहीं मिलती, भुगतान को तैयार रहें : डीएम

बस्ती। डीएम प्रियंका निरंजन ने विद्युत उपभोक्ता पहचान एवं समाधान पखवाड़े का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विद्युत विभाग द्वारा नये प्रयास किए जा रहे है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इससे विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याए खत्म होंगी। उन्होने आम जन से अपील की कि बिजली निःशुल्क नहीं मिल सकती है और इसके लिए सभी को भुगतान करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

उन्होंने विद्युत अभियन्ताओं को निर्देशित किया कि गांव में तैनात विद्युत सखी को अधिक से अधिक कार्य करने का अवसर दें, उनका सहयोग प्राप्त करें। इससे ग्रामीण क्षेत्र में भुगतान की स्थिति में सुधार होगा तथा लोगों की विद्युत भुगतान की प्रवृति को बढावा मिलेगा। इस अवसर पर उन्होने जागरूकता वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

अधीक्षण अभियन्ता सुशील कुमार मौर्य ने बताया कि चारों विद्युत वितरण क्षेत्र में उपभोक्ता नजदीकी

बिलिंग काउण्टर, उपखण्ड कार्यालय, विद्युत उपकेन्द्र अथवा विभागीय कार्मिक एंव बिलिंग एजेन्सी के मीटर रीडरों को अपने संयोजन पर पूर्व पंजीकृत मोबाइल नम्बर, पता, ई-मेल आईडी को परिवर्तित कराने के लिए या नये मोबाइल नम्बर, ई-मेल आईडी दर्ज कराने के लिए सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि मोबाइल नम्बर पर विद्युत आपूर्ति बाधित होने की सूचना, बिल भेजने एवं बिल जमा होने की सूचना, नयी लाभकारी योजनाओं की सूचना, क्षेत्र में विशेष कैम्प आयोजन की सूचना, उपभोक्ता से संवाद करने की सुविधा प्राप्त होंगी। उन्होने अपील किया कि टोल फ्री नम्बर 1912 पर विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान अधिशासी अभियन्ता एम.के. मिश्रा, अमित कुमार तथा कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

अपराध से अर्जित की गई संपत्ति कुर्क

संवाददाता। सीतापुर

● गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के बाद डीएम के आदेश पर सीज हुई संपत्ति

● गो तस्करी के मामले में शामिल था आरोपी तालिब हरदोई का है निवासी

योगी सरकार में अपराधियों के सफाए और क्राइम कंट्रोल करने के लिए चलाए जा रहे अभियान में सीतापुर की पुलिस ने एक और गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सीतापुर के पिसावां पुलिस ने गो-तस्करी में शामिल आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करने के बाद बुधवार को करीब 20 लाख से अधिक की संपत्ति पर सरकारी ताला लगा दिया है। गैंगस्टरों के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई से अपराधियों के होश उड़े हैं। आइये आपको पिसावां पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई से रूबरू कराते है।

एएसपी साउथ एनपी सिंह की माने तो हरदोई जिले के थाना पिहानी इलाके के मोहल्ला नागर पश्चिम का निवासी तालिब शातिर अपराधी है, वह गिरोह बनाकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था, जिसमें गो-वंशीय पशुओं की तस्करी उसका पेशा था। उसके खिलाफ पूर्व में डीएम के आदेश पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। इसके बाद उसकी संपत्ति के बारे में पता लगाया जा रहा था, पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि आरोपी के पास आय का स्रोत नहीं है, वह गो-तस्करी के जरिए पैसे कमाकर संपत्ति बना रहा था। इसके बाद डीएम अनुज सिंह के आदेश पर बुधवार को मोहल्ला नागर पश्चिम कस्बे में उसके मकान और हरदोई में एक मंजिला मकान को जब्त करने की बड़ी कार्रवाई की गई है। एएसपी की माने तो जब्त की गई संपत्ति की कीमत 20 लाख 30 हजार रूपए है। सीतापुर के एएसपी साउथ एनपी सिंह के अनुसार इस तरह का अपराध करने वाले अन्य अपराधियों के बारे में पुलिस लगातार जानकारियां जुटा रही है। अन्यकई गैंगस्टर भी पुलिस के रडार पर है, उनके खिलाफ भी जल्द ही बड़ा एक्शन लिया जाएगा।

कांग्रेसियों ने चलाया हाथ से हाथ जोड़ो अभियान

बरेली। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत सुबह 11 बजे ब्लाक रामनगर के ग्राम महमूदपुर से हुई मजरा दौलतपुर, तिगरा खानपुर होते हुए समापन शाम को 6 बजे ग्राम मऊ चनदपुर में हुआ । आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के यात्री लगभग 20 किलोमीटर तक चले । हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के ग्राम मऊ चनदपुर पर समापन पर एक सभा हुई जिसकी अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने की। संचालन जिला महासचिव सूर्य गांधी ने किया।

बैठक में उपस्थित कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा पहलू हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है, जिसके माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी जी का संदेश पत्र लोगों को दे रहे हैं।

राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना ने हिंदू जोड़ो यात्रा की शुरू

संवाददाता। सीतापुर

● नैमिषारण्य से शुरू हुई यात्रा, गांव, कस्बे से शहर तक जाएगी

● यात्रा के जरिए धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने की कही बात

कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है, लेकिन यूपी के सीतापुर में बुधवार से राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना ने हिंदू जोड़ो यात्रा की शुरूआत की है। इस यात्रा के जरिए संगठन की मंशा है कि सनातन धर्म के लोगों से संपर्क बढ़ा कर हिंदुओं को एकजुट किया जा सके। अब यह यात्रा अपने मकसद में कितना कामयाब होती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

दरअसल मंगलवार को सामाजिक संगठन राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना की ओर से प्रस्तावित हिंदू जोड़ो यात्रा का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू के नेतृत्व में नैमिषारण्य से हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व और राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप हिंदू, जिला अध्यक्ष देश दीपक हिन्दू के मार्गदर्शन में पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने चक्रतीर्थ पर पूजन अर्चन किया। इसके बाद पूरा दल मां ललिता देवी के मंदिर में पहुंचा। यहां से सभी लोग हनुमानगढ़ी गए, फिर नैमिषारण्य कस्बे में पैदल भ्रमण करते हुए लोगों से मिलकर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने की अपील की। नैमिषारण्य से यात्रा लक्ष्मण नगर, ठाकुरनगर गांव पहुंची। जहां सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र के बारे में अवगत कराया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने कहा कि यह यात्रा अनवरत चलती रहेगी। गांव-गांव जाकर के हिंदुत्व और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का। कांग्रेस की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं।

एसबीएम-नगरीय 2.0 : खीरी में हुआ 10 तक डोर-टू-डोर अभियान का आगाज

संवाददाता। लखीमपुर खीरी

नगरीय सुविधाओं के स्तरोन्नयन, नगरों के सौन्दर्यीकरण, स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से बुधवार को स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 के तहत जनपद खीरी में नगरीय निकायों में 10 तक डोर टू डोर अभियान का आगाज हुआ। विधायक योगेश वर्मा, डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने एडीएम संजय सिंह के साथ नगर पालिका परिषद लखीमपुर द्वारा आयोजित अभियान का शुभारंभ करते हुए कलेक्ट्रेट में जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि नगरीय निकायों में स्वच्छ भारत मिशन, नगरीय 2.0 के तहत सूखे, गीले कचरे को अलग-अलग कराकर शत प्रतिशत डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने के लिए 01 फरवरी से 31 मार्च तक 03 चरणों में '10तक- डोर टू डोर' अभियान प्रार्थना, सहमत, चालान की दृष्टि से चलाया जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण 01 से 15 फरवरी तक, द्वितीय चरण 16 फरवरी से 03 मार्च तक और तीसरा चरण 04 मार्च से 31 मार्च तक चलाया जाएगा।

विधायक सदर योगेश वर्मा ने कहा कि नगरों को 'गुड टू ग्रेट' तथा वैश्विक मापदंडों के अनुरुप बनाने के लिए सबसे पहले कूड़े का वैज्ञानिक विधि से निस्तारण करना जरूरी है। इसके लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत कूड़े का सोर्स सेग्रीगेशन किया जाना जरूरी है।

मौर्य को महासचिव बनाकर सपा ने असली चेहरा किया उजागर

फतेहपुर। अखिल भारत हिंदू महासभा की मासिक बैठक में जहां संगठन मजबूती पर चर्चा की गई वहीं समाजवादी पार्टी द्वारा अनवरत सनातन धर्म व रामचरितमानस पर की जा रही अशोभनीय टिप्पणी की कड़ी निंदा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री मनोज त्रिवेदी ने कहा कि रामायण के प्रति स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर उनको पुरस्कार देकर उनकी रामायण के प्रति की गई टिप्पणी का समर्थन करके सनातन धर्म के प्रति अपना असली चेहरा उजागर कर दिया है, जबकि कट्टर समाजवादी नेता डा. राम मनोहर लोहिया सदैव भगवान श्रीराम व रामायण के प्रति श्रद्धा प्रेम रखते थे। बैठक में वर्तमान समय में गरीबों के नये राशन कार्ड आनलाइन करने के बाद न बनने तथा कोटेदारों द्वारा राशन की घटतौली किए जाने का मुद्दा भी उठा। निर्णय लिया गया कि पंद्रह फरवरी को जिला पूर्ति कार्यालय का घेराव करके समस्याओं का निदान कराया जायेगा। बैठक में जिला प्रवक्ता स्वामी राम आसरे आर्य, करन सिंह पटेल, शशीकांत मिश्र, एसके गुप्ता, श्रवण कुमार राजपूत, प्रमोद पांडेय, अंजली मिश्रा, शकुंतला देवी मौजूद रहे।

वाणिज्य कर विभाग की टीम ने की छापेमारी, मचा हड़कंप

संवाददाता। मौदहा (हमीरपुर)

बांदा से आई वाणिज्य कर विभाग की टीम ने अचानक कस्बा स्थित सप्लायरों की दुकान में छापेमारी कर दी, जिससे जहां उनमें हड़कंप मच गया तो वहीं कुछ दुकानदार आनन-फानन में अपनी-अपनी दुकानों का शटर गिराकर रफूचक्कर हो गए।

वाणिज्य कर विभाग की टीम नगर में व्यापार कर रहे व्यापारियों के ऊपर अभी भी अपनी नजरें तिरछी किए हुए है, जिस पर अधिकांश दुकानदारों में भय का माहौल व्याप्त है। वहीं आज दोपहर बाद अचानक बांदा से आई वाणिज्य कर विभाग की मंडलीय टीम ने कस्बा स्थित रश्मि पेट्रोल पंप के बगल में मौजूद तिवारी ट्रेडर्स की दुकान में छापेमारी कर दी जहां भारी मात्रा में गिट्टी, सीमेंट, मोरम, डस्ट तथा लोहा मौजूद था, हालांकि वाणिज्य कर विभाग की टीम द्वारा मौके का सर्वे शुरू कर दिया था। हालांकि टीम द्वारा की गई छापेमारी को देखकर अगल बगल स्थित दुकानदार अपनी-अपनी दुकानों का शटर गिरा कर वहां से रफूचक्कर हो गए, वहीं इस संबंध में ज्यादा जानकारी देते हुए एसआईबी के डिप्टी कमिश्नर वीपी सिंह ने बताया कि अभी जांच चल रही है जिसमें कुछ कहना मुश्किल है लेकिन जांच में उचित कार्यवाही ही की जाएगी।

डीएम की सख्ती का असर, 21 लाख बकाया होने पर मकान सीज

मऊ/चित्रकूट। जिलाधिकारी अभिषेक आनन्द की सख्ती का असर अधिकारियों पर नजर आ रहा है। मऊ तहसील क्षेत्र के बड़े बकायेदारों के खिलाफ जारी अभियान में तहसीलदार राजेश कुमार यादव की अगुवाई में राजस्व कर्मियों ने क्षेत्र के बकायेदार का मकान सीज कर दिया है।

बुधवार को मऊ तहसील के एसडीएम नवदीप शुक्ला के निर्देश पर राजस्व कर्मियों ने दस बकायेदारों के खिलाफ वसूली अभियान के तहत कमल नारायण मिश्रा पुत्र संगमलाल मिश्रा निवासी बरियारीकला पर 21 लाख के बकाया होने पर उनका मऊ स्थित मकान सीज कर दिया है। तहसीलदार राजेश कुमार यादव की अगुवाई में चले अभियान में दो अन्य बकायेदार जगपत पुत्र मंगू निवासी धवाडा व दीपक पुत्र श्यामलाल निवासी सिकरो के धनराशि न जमा करने पर तहसील में कैद किया गया।

एसडीएम शुक्ला ने बताया कि ये कार्यवाही तहसील क्षेत्र के बकायेदारों के खिलाफ की जा रही है। बकायेदार तुरन्त धनराशि अमीनों के पास जमा कर दें। बकायेदार की रिकवरी तत्काल प्रभाव से सम्पर्क कर अमीन जमा करा दें। ऐसा न करने पर बकायेदारों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

इंडियन बैंक जिले में बैंकिंग सेवाओं को आसान बनायेगी

उरई (जालौन)। इंडियन बैंक के द्वारा जालौन में संचालित हो रहे बैंकिंग सेवा केंद्र संचालकों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिले में बैंकिंग सेवाओं को अधिक आसान बनाने हेतु कई बैंकिंग सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से पैसों की जमा और निकासी व सोशल सर्विस स्कीम के अंतर्गत अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आदि सेवाएं दी जाती हैं। इसी क्रम में जिले के मुख्यालय में सिटी सेंटर के मीटिंग हॉल में जिले के सभी बैंक मित्रों को आमंत्रित किया गया। साथ ही उनके द्वारा किए गए टारगेट के आधार पर राशि का वितरण किया गया। इस दौरान सम्मान समारोह में अचल कार्यालय झांसी से संजीव कुमार, मुख्य प्रबंधक अभिषेक पटेल, वरिष्ठ प्रबंधक अनुराग शर्मा, अग्रणी जिला प्रबंधक संदीप सिन्हा व एफआई मैनेजर मानवेंद्र पटेल उपस्थित रहे। मीटिंग में सीएससी सीनियर मैनेजर नीरज तिवारी, सीएससी जिला प्रबंधक आलोक पाल, सौरभ कुमार याज्ञिक व जिला समन्वयक रिहान अहमद उपस्थित रहे।

राकेश सचान ने वर्ष 2023-24 के आम बजट को महिला, गांव, गरीब और किसानों का बजट बताया

संवाददाता। कानपुर देहात

● एमएसएमई मंत्री ने ओडीओपी योजना को पूरे देश में विस्तार देने पर दी बधाई

उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, रेशम, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग तथा खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने कहर कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज पेश किये गये वर्ष 2023-24 के आम बजट में महिला, गांव, गरीब और किसानों को प्राथमिकता दी गई है।

इस बजट में खासतौर से श्रमिकों एवं मध्यम वर्ग का ख्याल रखा गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की बजट में किये गये प्राविधान से प्रदेश की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। प्रदेश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर होगा। सचान ने एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना को पूरे देश में विस्तार देने के लिए प्रधानमंत्री जी व वित्तमंत्री जी को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरे देश में लागू करने से व्यापक स्तर पर रोजगार का सृजन होगा और देश व प्रदेश की जीडीपी बढ़ाने में मदद मिलेगी। ओडीओपी योजना के तहत यूनिटी मॉल खोलने, एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना तथा पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना से हस्तशिल्पियों, पारंपरिक कारीगरों एवं उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने प्रदेश में इनक्यूबेशन केन्द्र की मंजूरी को उद्यमियों का हितैशी बताया और कहा कि इनक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से नये उद्यमियों पर फोकस किया गया है। इससे उद्योगों तथा उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी।

परिचय पत्रों का लोकतंत्र सेनानियों ने नवीनीकरण कराने की मांग की

उरई (जालौन)। भारतीय लोकतंत्र रक्षक सेनानी समिति उप्र के प्रदेशाध्यक्ष राजाराम व्यास व जिलाध्यक्ष अवध शर्मा बब्बा ने जिलाधिकारी को संबोधित एक मांग पत्र सदर उप जिलाधिकारी राजेश सिंह को सौंपा जिसमें जनपद के सभी लोकतंत्र रक्षक सेनानियों के परिचय पत्रों को नवीनीकरण कराने की मांग की। बुधवार को लोकतंत्र रक्षक सेनानियों के प्रतिनिधि मंडल ने उप जिलाधिकारी सदर से भेंट कर उन्हें जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा जिसमें कहा गया कि जनपद के लोकतंत्र सेनानियों के परिचय पत्रों की समयावधि कालातीत होने के सन्निकट है।

अधिवक्ता कल से करेंगे कलम बंद हड़ताल

संवाददाता। कायमगंज फर्रुखाबाद

● दूसरे संगठनों का भी समर्थन मिला

कायमगंज बार एसोसिएशन द्वारा 20 जनवरी से पुलिस के विरुद्ध आंदोलन जारी है। आज अधिवक्ताओं की बैठक में निर्णय लिया गया कि वे कल से आंदोलन को और तेज करते हुए कलम बंद हड़ताल करेंगे।

जिस समय अधिवक्ताओं की बैठक चल रही थी। उसी समय अलीगंज बार अध्यक्ष प्रमोद कुमार मिश्रा तथा उनके साथ ही अनिल कुमार अवस्थी सचिव, कोषाध्यक्ष महेंद्र पाल कश्यप, रामकृष्ण चतुर्वेदी तथा धीरज सिंह कायमगंज न्यायालय परिसर में धरना स्थल पर पहुंचे, और उन्होंने अपना समर्थन देते हुए चल रहे धरने पर बैठ गए।

उन्होंने बताया कि बार एसोसिएशन अलीगंज, कायमगंज अधिवक्ताओं के साथ है। इसके अलावा अधिवक्ताओं को समर्थन देने के लिए कायमगंज से भारतीय किसान यूनियन के मुन्ना लाल सक्सेना भी अपना समर्थन देते हुए दरी पर बैठ गए। बताते चलें कि पिछली 20 जनवरी से अधिवक्ताओं तथा पुलिस में आर पार की लड़ाई अब उग्र रूप लेते हुए कलम बंद हड़ताल तक पहुंच गई है।

अधिवक्ताओं की मांग है कि वह कंपिल एसएचओ का यहां से स्थानांतरण करें। जबकि पुलिस द्वारा जो वार्ता की गई है, उसमें दोषी एक दरोगा को हटाने की बात कही गई है। जिसको लेकर अधिवक्ता सहमत नहीं हुए और आज एक आपात बैठक करते हुए कलम बंद हड़ताल की घोषणा कर दी। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन, अलीगंज बार एसोसिएशन के अलावा एटा, जलेसर के भी अधिवक्ताओं ने अपना समर्थन कायमगंज न्यायालय में धरना प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं को दिया है।

इस संबंध में बार एसोसिएशन अध्यक्ष राघव चंद शुक्ला ने बताया कि अलीगंज भारतीय किसान यूनियन के अलावा और भी तहसीलों के अधिवक्ताओं ने समर्थन देने की बात कही है। हमारी कल से कलम बंद हड़ताल शुरू हो जाएगी।

बालिका शिक्षा जागरूकता प्रचार वाहन को एडीएम ने किया रवाना

संवाददाता। उरई (जालौन)

अपर जिलाधिकारी न्यायिक मोतीलाल यादव व परियोजना निदेशक शिवाकांत द्विवेदी ने प्रचार वाहन को कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश द्वारा बालिकाओं की शिक्षा, सशक्तीकरण, स्वालम्बन एवं बालिकाओं के प्रति समाज में व्याप्त रूढ़ियों तथा हानिकारक परंपराओं का समूल नाश करने के उद्देश्य से बालिका शिक्षा एवं महिला सशक्तीकरण के मुद्दों पर जन जागरूकता अभियान (निपुण भारत मिशन) के संचालन का महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल 14 फिल्मों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार जनपद के समस्त ब्लॉकों में किया जाएगा। इस अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सचिन कुमार आदि अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

जागरूकता रैली को ईओ ने किया रवाना

फतेहपुर। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 2.0 के अंतर्गत एक फरवरी से 31 मार्च तक तीन चरणों में चलने वाले अभियान के प्रथम चरण में डोर टू डोर अभियान के अन्तर्गत आम जनमानस में जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से बुधवार को जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिसका शुभारंभ नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी समीर कुमार कश्यप ने हरी झंडी दिखाकर किया। पालिका परिसर ने निकलकर रैली वर्मा चौराहा से पटेल नगर, सेल्फी प्वाइंट तक गई। कार्यक्रम में लोगों को घर-घर व दुकानों में जाकर गीला तथा सूखा कूड़ा अलग-अलग डोर-टू-डोर कूड़ा गाड़ी को देने हेतु प्रेरित किया गया।

विद्युत केवाईसी कराएं-सेवाओं को सरल बनाएं अभियान

संवाददाता। फतेहपुर

विद्युत केवाईसी कराएं, सेवाओं को सरल बनाएं के नारे के साथ बुधवार को विद्युत उपभोक्ता पहचान व समाधान पखवाड़ा का शुभारंभ अधीक्षण अभियंता रविंद्र कुमार जैन ने विद्युत टीमों को हरी झंडी दिखाकर घर-घर ग्राहकों का डाटा एकत्र करने के लिए रवाना किया। उक्त कार्यक्रम के शुभारंभ पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए अधीक्षण अभियंता रविंद्र कुमार जैन ने बताया कि ग्राहकों को विद्युत सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें एवं उनकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए विद्युत उपभोक्ता पहचान व समाधान पखवाड़े का शुभारंभ बुधवार को किया गया है जो 15 फरवरी को समाप्त होगा।

उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान विद्युत टीम घर-घर जाकर ग्राहकों का डाटा एकत्र करेगी और उनके मोबाइल नंबर पर ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन करने के बाद उनका समस्त डाटा ऑनलाइन कर दिया जाएगा जिससे विभाग के पास ग्राहकों की समस्त जानकारी उपलब्ध होगी एवं ग्राहक को भी अपनी विद्युत सेवा से संबंधित समस्त जानकारी समय-समय पर मिलती रहेगी। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान बिल का भुगतान न होने पर विद्युत विच्छेदन के पूर्व जानकारी, बिल भुगतान की सुविधा, विद्युत बिल से संबंधित समस्त जानकारियां, समस्याओं का त्वरित निस्तारण, विभागीय योजनाओं एवं कैंपों की जानकारी, विद्युत बाधित होने की स्थिति में ग्राहक को जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है जो 15 फरवरी को समाप्त होगा। उन्होंने बताया कि इससे जहां ग्राहकों को अपने विद्युत बिल एवं योजनाओं से संबंधित जानकारियां आसानी से उपलब्ध होंगी। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विद्युत चेकिंग के नाम पर जो समय बर्बाद होता है,उसकी बचत होगी और वह ग्राहकों की जो समस्याएं हैं उन्हें समय से निस्तारित कर सकेंगे। उन्होंने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दें।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर भी नहीं हो पा रहा अमल!

संवाददाता। फतेहपुर

● 'जो जमीन सरकारी वह जमीन हमारी' की तर्ज में तालाबों की हुई प्लाटिंग

● कागजों में दर्ज तालाबों व सरकारी भूमि में बस गये मोहल्ले के मोहल्ले

● शहर के दर्जन भर तालाबों का अस्तित्व खतरे में, कई के मिट चुके नामो-निशान

सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ न करने एवं जल संचय करने के सैकड़ो वर्षो से संसाधन के रूप में रहे तालाबों का अस्तित्व बचाने के लिए केन्द्र सरकार सहित सभी राज्य सरकारों को कड़े निर्देश दिये हैं, जिसकी वजह से तालाब, खलिहान सहित अन्य सार्वजनिक रूप से उपयोग की जाने वाली जमीनों की हिफाजत करने एवं भू-माफियाओं पर कार्यवाही करने का भी आदेश दिया है जिसको अमलीजामा पहनाने के लिए राज्य सरकारों ने सभी जिलाधिकारियों को शासनादेश जारी कर अचल सम्पत्ति की रक्षा करने एवं अनाधिकृत कब्जा हटवाने के आदेश दिये हैं, किन्तु नगर पालिका परिषद की लचर नीति के चलते सार्वजनिक तालाबों, सरकारी भूमि में मोहल्ले के मोहल्ले बस गये हैं , जिन्हें अब खाली करा पाना जिला प्रशासन के बस की बात नहीं है। मालूम हो कि वर्तमान जिलाधिकारी ने सार्वजनिक तालाबों, सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले लोगों पर कार्यवाही के निर्देश पालिका प्रशासन सहित राजस्व विभाग के जिम्मेदारों को दिये हैं, किन्तु यह फरमान कितना अमल में लाया जायेगा यह तो आने वाला समय ही बतायेगा! सर्वोच्च न्यायालय एवं सरकारी फरमानों का अमलीजामा सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, जबकि जिला ही नहीं शहर के सभी सार्वजनिक तालाबों, खलिहानों, कब्रिस्तानों की अरबों की बेशकीमती जमीनों पर दबंग-माफियाओं ने कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से अरबों की अचल सम्पत्ति आज दबंग-माफियाओं की तिजोरी में बंद हो चुकी है और कागजों में दर्ज तालाबों पर रिहायशी मकान और मोहल्ले के मोहल्ले बस गये हैं। जिला मुख्यालय की स्वच्छता, पानी और बिजली के साथ विकासपरक कार्यो की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाला नगर पालिका परिषद कार्यालय से जुड़ा बरतानिया हुकूमत में निर्मित कराया गया रानी विक्टोरिया के नाम के तालाब को आस-पड़ोस के लोग कूड़ा-करकट डालकर समतल बना रहे हैं। यही नहीं तालाब की जमीन पर रिहायशी पक्के मकान बनवाकर दर्जनों लोग परिवार सहित रह रहे हैं।

इसी तरह पीरनपुर का नौहत्था तालाब, अरबपुर मोहल्ला का नजमुद्दीन शाह बाबा का तालाब, ज्वालागंज का गोरे शहीदन शाह बाबा का तालाब, सैयदबाड़ा का कूड़ तालाब, मुराइनटोला का नवइया तालाब, ज्वालागंज बस स्टाप का चंदी तालाब, श्री नारायण दास बाबा कुटी शांतीनगर एवं नया तालाब शांतीनगर के साथ-साथ रेलवे कालोनी के पीछे इस्माइलगंज का तालाब, पक्का तालाब सहित अन्य तालाबों में दबंग भू-माफिया ने सरकारी हुक्मरानों से मिलीभगत कर तालाबों की पुराई कर जमीन की प्लाटिंग करवाकर अरबों की सम्पत्ति कमा ली है।

सरकारी जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त करायेगी टास्क फोर्स-एसडीएम

संवाददाता। मानिकपुर/चित्रकूट

एसडीएम प्रमेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक में एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स की बाबत अवैध ढंग से भूमि में कब्जा करने वालों पर टीम की कड़ी नजर रहेगी। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्यवाही भी की जायेगी।

ज्ञात है कि सूबे के मुख्य सचिव के आदेश पर एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स बाबत मंगलवार को तहसील सभागार में एसडीएम प्रमेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक में टीम का गठन किया गया। एसडीएम प्रमेश कुमार श्रीवास्तव टीम के अध्यक्ष व पुलिस क्षेत्राधिकारी, लोनिवि के अधिशाषी अभियंता, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता, वन क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष व जिला पंचायत तथा तहसील स्तरीय अधिकारियों को सदस्य और तहसीलदार को संयोजक सदस्य बनाया गया। अन्य विभाग जिनके स्वामित्व की भूमि पर अतिक्रमण अवैध कब्जे का बिन्दु निहित है, तहसील स्तरीय विशेष आमंत्रित सदस्य भी मौजूद रहे।

एसडीएम प्रमेश श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्य सचिव के आदेश पर एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स की बैठक हुई है। बैठक में सभी थाना प्रभारी, भूमि संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी ने अपनी-अपनी जगहों पर भूमि विवाद के मामले रखे। ऐसे मामलों के निस्तारण की रणनीति बनाई गई है।

सभी वर्गों के कल्याण को समर्पित है बजट

संवाददाता। चित्रकूट

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुद्धवार को संसद में पेश किये गये मोदी सरकार -2 के आखिरी पूर्ण बजट को ऐतिहासिक बताते हुए बांदा-चित्रकूट सांसद आर के सिंह पटेल ने जमकर सराहना की है। सांसद ने कहा कि इस बार का बजट देश के युवाओं, किसानों, मजदूरों तथा छोटे दुकानदारों एवं मध्यम वर्गीय व्यापारियों, बेरोजगारों, के कल्याण को समर्पित है। देश की आजादी के 75वें साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकता सितारा माना है। चालू वर्ष का हमारा आर्थिक विकास दर 7 प्रतिशत पर होने का अनुमान लगाया गया है। यह बजट कोविड-19 और एक युद्ध के कारण विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था के बड़े पैमाने पर सुस्त पड़ने के बावजूद संभव हुआ है।

मोदी सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए बांदा-चित्रकूट सांसद पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार अन्त्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को मुक्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना एक जनवरी 2023 से पुनः लागू कर रहे हैं , जिसमें लगभग 2 लाख करोड़ रूपये से अधिक के संपूर्ण व्यय का वहन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ परिवारों में शौचालय, उज्जवला के अंतर्गत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ कोविड टीकाकरण, 47.8 करोड़ पीएम जनधन बैंक खाते, पीएम सुरक्षा और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमाकवर व पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ का नकद अंतरण। चुनौतियों के बीच वैश्विक एजेण्डा को संचालित करना-जी20 की अध्यक्षता, दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्वयं-सहायता समूहों से जोड़ कर असाधारण कामयाबी हासिल की है। इन समूहों में बड़े उत्पादन उद्यमों या समूह होंगे जिनमें से प्रत्येक में कई हजार सदस्य होंगे। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में जनपद चित्रकूट एवं बाँदा को शामिल किया गया है, जहां घरेलू के साथ-साथ विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थानों का भरमार है। कृषि वर्धक निधि (एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड) से युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री-स्टार्ट-अप्स खोल दिया गया है। बताया कि मोदी सरकार द्वारा आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम के तहत 2,200 करोड़ के परिव्यय से हाड़ वैल्यू बागवानी फसलों के लिए रोग-मुक्त, गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया गया। जिससे बुन्देलखण्ड के बांदा-चित्रकूट के किसानों को लाभ मिलेगा।

सेंसेक्स चढ़ा लेकिन निफ्टी फिसला

भाषा। मुंबई

संसद में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश होने के दिन बुधवार को घरेलू शेयर बाजारों में खासा उतार-चढ़ाव देखा गया। बाजार के ऊपरी स्तर पर जाने के बाद मुनाफावसूली हावी होने से दोनों प्रमुख सूचकांक मिले-जुले रुख के साथ बंद हुए।

बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक सेंसेक्स 158.18 अंक यानी 0.27 प्रतिशत की बढ़त के साथ 59,708.08 अंक पर बंद हुआ। बजट भाषण के समय बाजार के उत्साहित होने से सेंसेक्स 1,223.54 अंक तक उछल गया था लेकिन बाद में बिकवाली का सिलसिला चलने से इसने अपनी अधिकांश बढ़त गंवा दी।

इसके उलट एनएसई के सूचकांक निफ्टी में 45.85 अंक यानी 0.26 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 17,616.30 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में आईटीसी ने सर्वाधिक 2.61 प्रतिशत की बढ़त हासिल की। टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक भी लाभ की स्थिति में रहे। दूसरी तरफ बजाज फिनसर्व, भारतीय स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में 5.65 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, बजट में खपत और पूंजीगत व्यय पर खासा जोर दिया गया है। इससे बाजार में उम्मीदों को बल मिला लेकिन अपराह्न कारोबार में निवेशकों का ध्यान अडाणी प्रकरण और फेडरल रिजर्व की बैठक पर चले जाने से उठापटक का दौर शुरू हो गया।

नायर ने कहा कि सरकार की तरफ से नई कर प्रणाली को बढ़ावा देने से जीवन बीमा कंपनियों के कर-बचत के लिहाज से कम आकर्षक रह जाने की आशंका में जमकर बिकवाली हुई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) धीरज रेली ने बजट को व्यावहारिक बताते हुए कहा कि इसमें कोई बड़ी नकारात्मक घोषणा न होने से बाजार ने अच्छी प्रतिक्रिया दी लेकिन अब निवेशकों की नजर फेडरल रिजर्व की मौद्रिक घोषणा पर टिकेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा बढ़ाने और लघु बचत योजनाओं को प्रोत्साहन देने के साथ ही सरकार के पूंजीगत व्यय को 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा की। सैमको सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषक संजय मूरजानी ने कहा, व्यक्तिगत आयकर के मोर्चे पर सरकार की तरफ से दी गई राहतों ने बाजार को खासी तेजी दी। इसके अलावा पूंजीगत लाभकर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना भी बाजार को रास आया। हालांकि दोपहर के बाद के कारोबार में अडाणी समूह को लेकर चिंता हावी होने और अमेरिकी केंद्रीय बैंक की आसन्न मौद्रिक घोषणा को लेकर दबाव देखा गया।

इसके असर में व्यापक बाजार में बीएसई स्मॉलकैप 1.10 प्रतिशत गिर गया जबकि मिडकैप में 0.96 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इस बीच, वैश्विक बाजारों में कुल मिलाकर सकारात्मक रुझान रहने से निवेशकों को बल मिला। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग मजबूती के साथ बंद हुए। यूरोप के बाजार बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अमेरिकी बाजार भी मंगलवार को लाभ में रहे थे। अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85.42 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों से निकासी जारी रखी है। शेयर बाजारों के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को 5,439.64 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर बेचे।

नई कर व्यवस्था में बदलाव से आयकरदाताओं को होगा लाभ

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में नई कर व्यवस्था में बदलाव से करदाताओं को लाभ होगा। अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय नौ लाख रुपए है तो उन्हें अब 45,000 रुपए की ही कर देने होंगे, जो पहले 60,000 रुपए बनता था।

इसी प्रकार, किसी व्यक्ति की आय अगर 15 लाख रुपए सालाना है, उसे केवल 1.5 लाख रुपए या अपनी आय का केवल 10 प्रतिशत ही कर देना होगा। यह नई कर व्यवस्था के मौजूदा स्वरूप के तहत बनने वाले 1,87,500 रुपए से करीब 20 प्रतिशत कम है। वित्त मंत्री ने कहा, यह नई कर व्यवस्था सभी करदाताओं को बड़ी राहत देगा। नई कर व्यवस्था में जिस बदलाव का प्रस्ताव किया गया है, उसके तहत सात लाख रुपए तक की आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा। हालांकि, निवेश और आवास भत्ता जैसी छूट वाली पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही पुरानी कर व्यवस्था में मानक कटौती के रूप में 50,000 रुपए का लाभ अब नई कर व्यवस्था में भी मिलेगा। इसके अलावा, बजट में गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय अर्जित अवकाश के एवज में किए जाने वाले भुगतान पर कर छूट की सीमा को तीन लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है।

सीमा शुल्क में कटौती से 3,000 तक सस्ता हो सकता है टीवी सेट

भाषा। नई दिल्ली

स्थानीय स्तर पर विनिर्मित टीवी सेट के दाम 3,000 रुपए तक घट सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयात किए जाने वाले कलपुर्जों पर बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) को पांच प्रतिशत से घटाकर आधा यानी 2.5 फीसदी कर दिया है।

उद्योग की कुछ कंपनियों का कहना है कि ओपन सेल के घटकों पर सीमा-शुल्क में कटौती से टीवी के दाम करीब पांच प्रतिशत कम हो सकते हैं। एलईडी टीवी सेट की विनिर्माण लागत में 60 से 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा ओपन सेल पैनल का होती है। ज्यादातर टीवी विनिर्माता इन पैनलों का आयात करते हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, टेलीविजन के विनिर्माण में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए टीवी पैनल के ओपन सेल के हिस्सों पर बुनियादी सीमा शुल्क को घटाकर 2.5 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया जाता है।

उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स एवं उपकरण विनिर्माता संघ (सीईएएमए) के अध्यक्ष एरिक ब्रेगैंजा ने कहा कि इस कदम से क्षेत्र की वृद्धि होगी और घरेलू स्तर पर मूल्यवर्द्धन होगा। उन्होंने कहा कि यह उद्योग के लिए एक अच्छा कदम है और इससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

भारतीय बाजार में थॉमसन, कोडक और व्हाइट-वेस्टिंगहाउस जैसे अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के लिए लाइसेंस रखने वाली सुपर प्लास्ट्रोनिक प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं संस्थापक अवनीत सिंह मारवाह ने कहा कि इस कदम से टीवी सेट के दाम पांच फीसदी तक कम हो जाएंगे।

सोनी इंडिया के प्रबंध निदेशक सुनील नैय्यर ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से टेलीविजन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया के चेयरमैन मनीष शर्मा ने कहा कि मध्यम और उच्च वर्ग दोनों के लिए कर में कटौती की गई है जिससे करदाता के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा और इसके परिणामस्वरूप मांग और खपत बढ़ेगी।

हायर अप्लाइंसेस इंडिया के अध्यक्ष सतीश एन एस ने कहा कि सीमा शुल्क में कटौती से विनिर्माताओं को तो लाभ होगा ही, कई उपभोक्ताओं किफायती दर पर टेलीविजन खरीद पाएंगे जिससे उनकी जीवनशैली बदलेगी।

दूरसंचार, डाक परियोजनाओं के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान

भाषा। नई दिल्ली

सरकार ने डाक और दूरसंचार परियोजनाओं के लिए आम बजट में 1.23 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जिसमें से 52,937 करोड़ रुपए की पूंजी सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल में डाली जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि कुल आवंटन में 97,579.05 करोड़ रुपए दूरसंचार विभाग के लिए और 25,814 करोड़ रुपए डाक परियोजनाओं के लिए हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार बीएसएनएल में 52,937 करोड़ रुपए लगाएगी। इसके अलावा रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क के लिए सरकार ने 2,158 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार परियोजनाओं के लिए 715.8 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। डाक विभाग के लिए कुल 25,814 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जिसमें से 250 करोड़ रुपए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में डाले जाएंगे।

दूरसंचार क्षेत्र से गैर-कर राजस्व संग्रह का लक्ष्य 30 प्रतिशत बढ़ाया गया

नई दिल्ली। सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए गैर-कर राजस्व संग्रह का अनुमान 30 प्रतिशत बढ़ाकर 89,469.17 करोड़ रुपए कर दिया है। बुधवार को संसद में पेश आम बजट में यह जानकारी दी गई। सरकार ने दूरसंचार विभाग में चालू वित्त वर्ष के लिए भी गैर-कर राजस्व संग्रह लक्ष्य संशोधित कर 68,784 करोड़ रुपए कर दिया है जबकि पहले यह 52,806 करोड़ रुपए था। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में दूरसंचार क्षेत्र का वास्तविक राजस्व 85,828 करोड़ रुपए रहा।

दूरसंचार क्षेत्र से गैर-कर राजस्व का संबंध मुख्यत: दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से मिलने वाले लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की प्राप्तियों से होता है।

एनएचएआई के लिए आवंटित राशि बढ़ाकर 1.62 लाख करोड़ की गई

भाषा। नई दिल्ली

केंद्र सरकार अवसंरचना पर ज्यादा ध्यान दे रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए आगामी वित्त वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के लिए आवंटित राशि बढ़ाकर 1.62 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। एनएचएआई को आवंटित चालू वित्त वर्ष में संशोधित राशि 1.42 लाख करोड़ रुपए थी।

आम बजट 2023-24 में राजमार्ग क्षेत्र के लिए परिव्यय बढ़ाकर 2.70 लाख करोड़ रुपए किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में राजमार्ग क्षेत्र के लिए 1.99 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसे बाद में संशोधित कर 2.17 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। एनएचएआई और राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के निर्माण का जिम्मा देखती हैं।

सहकारी क्षेत्र के लिए कर राहत

भाषा। नई दिल्ली

● सहकारिता मंत्रालय के बजट आवंटन में कटौती

सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बुधवार को कई उपायों की घोषणा की जिसमें विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करने वालीं नई सोसायटी पर 15 प्रतिशत की रियायती दर से कर लगाने तथा नकद निकासी पर टीडीएस के लिए तीन करोड़ रुपए की ऊपरी सीमा तय करना भी शामिल है।

सरकार ने सहकारिता मंत्रालय के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 1,150.38 करोड़ रुपए का कुल बजट परिव्यय निर्धारित किया है। हालांकि यह राशि वित्त वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान 1,624.74 करोड़ रुपए से कम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा नकद जमा और नकद में ऋण के लिए प्रति सदस्य दो लाख रुपए की उच्च सीमा तय करने की घोषणा की। सरकार ने चीनी सहकारी समितियों को आकलन वर्ष 2016-17 से पहले की अवधि के लिए गन्ना किसानों को किए गए भुगतान को व्यय के रूप में दावा करने का मौका भी दे दिया है। इससे उन्हें लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राहत मिलने की उम्मीद है।

सरकार की यह घोषणा छोटे एवं सीमांत किसानों और अन्य कमजोर तबकों के लिए सहकारी-आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देने के प्रयासों के बीच की गई है।

सीतारमण ने कहा कि सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सरकार 2,516 करोड़ रुपए के निवेश से 63,000 पैक्स समितियों का कम्प्यूटरीकरण पहले ही शुरू कर चुकी है। सभी हितधारकों और राज्यों के परामर्श से पैक्स समितियों के लिए मॉडल नियम बनाए गए थे ताकि इन्हें बहुउद्देशीय समिति बनाया जा सके। सहकारी समितियों के देशव्यापी मानचित्रण के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तैयार किया जा रहा है।

चालू वित्त वर्ष में खाद्य, उवर्क, पेट्रोलियम सब्सिडी 5.21 लाख करोड़ रहने का अनुमान

भाषा। नई दिल्ली

खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर सरकार की सब्सिडी चालू वित्त वर्ष में 17 प्रतिशत बढ़कर 5.21 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष 2023-24 में इसके 28 प्रतिशत कम होकर करीब 3.75 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।

बजट दस्तावेज के अनुसार, सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपने संशोधित अनुमान (आरई) में खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर कुल सब्सिडी 5,21,584.71 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया है। पिछले वित्त वर्ष में इसका वास्तविक बजट 4,46,149.24 करोड़ रुपए था।

इन तीन मदों पर कुल सब्सिडी में से चालू वित्त वर्ष में खाद्य सब्सिडी मामूली रूप से घटकर 2,87,194.05 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो 2021-22 में 2,88,968.54 करोड़ रुपए थी। हालांकि, इस वित्त वर्ष के दौरान उर्वरक सब्सिडी बढ़कर 2,25,220.16 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष में 1,53,758.10 करोड़ रुपए थी। इस दौरान यूरिया पर सब्सिडी 1,00,988.13 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,54,097.93 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि फॉस्फेटिक और पोटाशिक (पी एंड के) उर्वरकों पर सब्सिडी 52,769.97 करोड़ रुपए से बढ़कर 71,122.23 करोड़ रुपए हो गई है। पेट्रोलियम सब्सिडी भी उक्त अवधि में 3,422.60 करोड़ रुपए से बढ़कर 9,170.50 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष के दौरान केंद्र ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के बीच वैश्विक कीमतों में तेज वृद्धि को देखते हुए यूरिया के साथ-साथ फॉस्फेटिक और पोटाश (पी एंड के) उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को कम कीमत पर उर्वरक मिलते रहें। अगले वित्त वर्ष के लिए खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर कुल सब्सिडी 2022-23 में 5,21,584.71 करोड़ रुपए से 28 प्रतिशत घटकर 3,74,707.01 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।

इसमें से उर्वरक सब्सिडी चालू वित्त वर्ष के 2,25,220.16 करोड़ रुपए से घटकर 2023-24 में 1,75,099.92 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। पेट्रोलियम सब्सिडी चालू वित्त वर्ष के 9,170.50 करोड़ रुपए से घटकर 2,257.09 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। खाद्य सब्सिडी, वित्त वर्ष 2022-23 के 2,87,194.05 करोड़ रुपए से घटकर अगले वित्तवर्ष में 1,97,350 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, क्योंकि सरकार ने महामारी के दौरान शुरू की गई मुफ्त खाद्यान्न योजना को बंद कर दिया है।

बुनियादी ढांचा विकास पर पूंजीगत व्यय 33% बढ़ा, 10 लाख करोड़ करने की घोषणा

भाषा। नई दिल्ली

वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में बुनियादी ढांचा विकास पर पूंजीगत व्यय 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.3 प्रतिशत बैठता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि हाल में स्थापित अवसंरचना वित्त सचिवालय की मदद से और निजी निवेश आकर्षित किया जा सकेगा।

सीतारमण ने कहा, पूंजीगत निवेश की रूपरेखा लगातार तीसरे वर्ष उल्लेखनीय रूप से बढ़ाई गई है। इसे 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया है जो जीडीपी का 3.3 फीसदी होगा। उन्होंने कहा कि यह 2019-20 की तुलना में लगभग तीन गुना होगा। उन्होंने कहा कि एक विशेषज्ञ समिति की भी स्थापना की जाएगी जो अवसंरचना वर्गीकरण और वित्तीय रूपरेखा को अमृत काल के लिए उपयुक्त बनाने का काम करेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि बंदरगाह, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों में संपर्क स्थापित करने के लिए सौ अहम परिवहन ढांचा परियोजनाओं की पहचान की गई है।

वित्त मंत्री ने कहा, इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी और इनमें 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसमें से 15,000 करोड़ रुपए निजी स्रोतों से आएंगे। पिछले साल 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गतिशक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को घटाने के लिए एकीकृत बुनियादी ढांचे का विकास करना है।

आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस बजट में समृद्ध एवं समावेशी भारत की संकल्पना की गई है जिसमें विकास का लाभ हर वर्ग तक, प्रत्एक नागरिक तक विशेषकर देश के युवाओं, महिलाओं, किसानों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति के लोगों तक पहुंच सके।

ऑनलाइन खेलों में जीती गई शुद्ध राशि पर 30% टीडीएस का प्रस्ताव

नई दिल्ली। सरकार ने आम बजट में ऑनलाइन खेलों में जीती जाने वाली शुद्ध राशि पर 30 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव दिया है। उसने 10,000 रुपए की मौजूदा कर सीमा को भी खत्म कर दिया है।

बजट 2023-24 में ऑनलाइन खेलों में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के लिए दो नए प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। इसमें वित्त वर्ष के दौरान जीती गई शुद्ध राशि के भुगतान पर 30 फीसदी कर लगाना और टीडीएस लगाने के लिए 10,000 रुपए की मौजूदा सीमा को खत्म करना शामिल है। यदि राशि उपयोगकर्ता के खाते से नहीं निकाली जाती है तो वित्त वर्ष के अंत में स्रोत पर कर काटा जाएगा। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बजट बाद संवाददाताओं से कहा कि कुल मूल्य में जीती गई शुद्ध राशि पर कर लगाया जाएगा।

सार्वजनिक बिजली कंपनियां करेंगी 60,805 करोड़ रुपए का निवेश

नई दिल्ली। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की आठ बिजली कंपनियों की तरफ से किए जाने वाले कुल निवेश को वित्त वर्ष 2023-24 में करीब 15 प्रतिशत बढ़ाकर 60,805.22 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। संसद में बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की गई।

इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष के लिए सार्वजनिक बिजली कंपनियों का निवेश अनुमान भी संशोधित कर 52,878.08 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान पहले 51,470.14 करोड़ रुपए का था।

बजट प्रस्तावों के मुताबिक, पनबिजली उत्पादक कंपनी एनएचपीसी के निवेश अनुमान को 7,128.95 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से बढ़ाकर 10,857.22 करोड़ रुपए कर दिया गया है। चालू वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान 7,361.05 करोड़ रुपए का था। इसी तरह एसजेवीएन लिमिटेड का निवेश अनुमान अगले वित्त वर्ष के लिए बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पावरग्रिड के मामले में यह अनुमान 8,800 करोड़ रुपए पर स्थिर रखा गया है।

रिहायशी संपत्ति में पूंजीगत लाभ फिर से निवेश करने पर 10 करोड़ की छूट सीमा तय

भाषा। नई दिल्ली

सरकार ने बुधवार को एक संपत्ति बेचकर दूसरी रिहायशी संपत्ति खरीदने को लेकर दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ कर पर कटौती को लेकर 10 करोड़ रुपए की सीमा लगाने का प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, कर रियायत और छूट को बेहतर लक्षित करने के लिए मैं धारा 54 और 54 एफ के तहत आवासीय मकान में किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभ से कटौती की सीमा को 10 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करती हूं।

आयकर की दोनों धाराएं दीर्घकालीन संपत्तियों (आवासीय या अन्य पूंजीगत संपत्ति) की बिक्री से प्राप्त राशि के रिहायशी संपत्ति खरीदने के लिए फिर से निवेश से जुड़ा है। बजट दस्तावेज के अनुसार नए प्रावधान का उद्देश्य काफी महंगा रिहायशी मकान खरीदने के बाद उच्च नेटवर्थ करदाताओं की तरफ से बड़ी कटौती के दावे पर अंकुश लगाना है। आयकर कानून की धारा 54 और 54 एफ के तहत दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले पूंजीगत लाभ पर कटौती का प्रावधान है। यह छूट उस स्थिति में मिलती है जब करदाता रिहायशी संपत्ति खरीदता या निर्माण करता है।

धारा 54 के तहत उस स्थिति में दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर कटौती उपलब्ध होती है जब रिहायशी मकान के हस्तांतरण से होने वाले पूंजीगत लाभ को दोबारा से रिहायशी मकान में निवेश किया जाता है। वहीं 54 एफ के तहत कटौती का लाभ तब मिलता है जब रिहायशी मकान को छोड़कर दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले पूंजीगत लाभ को रिहायशी मकान में निवेश किया जाता है। दस्तावेज में कहा गया है कि इन प्रावधानों का मकसद आवास की कमी को दूर करना तथा मकान निर्माण गतिविधियों में तेजी लाना था। लेकिन यह पाया गया कि उच्च नेटवर्थ वाले करदाता काफी महंगा मकान खरीदकर इन प्रावधानों के तहत बड़ी छूट का दावा करते हैं। इस तह इस प्रावधान का जो उद्देश्य था, वह पूरा नहीं हो रहा था। बजट दस्तावेज के मुताबिक इस पर रोक लगाने के लिए अधिकतम कटौती की सीमा लगाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसका दावा करदाता धारा 54 और 54एफ के तहत कर सकते हैं। इसके तहत एक संपत्ति बेचकर दूसरी रिहायशी संपत्ति खरीदने को लेकर दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ कर पर कटौती को लेकर 10 करोड़ रुपए की सीमा लगाने का प्रस्ताव किया गया है।

विदेश यात्रा, बाहर रुपए भेजने पर टीसीएस को 20% करने का प्रस्ताव

भाषा। नई दिल्ली

सरकार ने बुधवार को विदेश यात्रा के टूर पैकेज और भारत से बाहर रुपए भेजने पर पर टीसीएस दर को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव बजट में रखा है। बुधवार को संसद में पेश बजट के जरिए प्रस्तावित वित्त विधेयक 2023-24 के माध्यम से विदेशी यात्रा कार्यक्रमों पर स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) वसूलते हुए आयकर अधिनियम की धारा 206सी में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत भारत से बाहर सात लाख रुपए से ज्यादा राशि भेजने पर 20 प्रतिशत टीसीएस लगाया जाएगा। ए संशोधन एक जुलाई, 2023 से प्रभावी होंगे। सलाहकार फर्म नांगिया एंडरसन के अमित अग्रवाल ने कहा कि टीसीएस को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करना विदेशी मुद्रा भंडार की आरामदेह स्थिति को देखते हुए काफी आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि इस तरह सरकार विदेश दौरों पर बेतहाशा खर्च को हतोत्साहित करना चाहती है।

आम बजट राष्ट्र निर्माण में मददगार, वृद्धि केंद्रित है : उद्योग मंडल

नई दिल्ली। भारतीय कंपनियों ने बुधवार को आम बजट 2023-24 पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे राष्ट्र निर्माण में मददगार, वृद्धि-केंद्रित और राजकोषीय रूप से विवेकपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि बजट में लगातार पूंजीगत व्यय और वित्तीय समावेश पर जोर दिया गया है। उद्योग जगत की दिग्गज हस्तियों ने कहा कि दृष्टि, संरचना और अनुशासन के साथ बजट भारत को विश्व गुरु बनने की राह पर ले जाता है। उद्योग निकाय भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि बजट विकासोन्मुख है और इसमें पूंजीगत व्यय तथा समावेशन पर जोर दिया गया है। बजट में 2047 तक एक विकसित भारत के लिए मजबूत नींव रखी गई है। उद्योग मंडल फिक्की के अध्यक्ष सुभ्रकांत पांडा ने कहा कि बजट घोषणाओं ने अर्थव्यवस्था की नब्ज को समझा है, और साथ ही राजकोषीय समेकन की प्रतिबद्धता को भी निभाया गया है। उन्होंने कहा, वृद्धि चक्र की गति बनाए रखने के लिए निवेश और उपभोग को बढ़ावा देने की जरूरत थी। हमें यह जानकर खुशी हुई कि सरकार ने पूंजीगत व्यय में 33 प्रतिशत वृद्धि के साथ पूंजीगत व्यय पर जोर जारी रखा है। उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा कि 2023-24 का बजट राष्ट्र निर्माण के लिए एक मसौदा है, जिसमें बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया है। एसोचैम के अध्यक्ष सुमंत सिन्हा ने कहा, पूंजीगत व्यय में 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ इसे 10 लाख करोड़ रुपए करने का फैसला भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाए रखने के संकल्प को दर्शाता है।

चालू वित्त वर्ष का विनिवेश लक्ष्य घटाया

● 2023-24 में 51,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य

भाषा। नई दिल्ली

सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए विनिवेश लक्ष्य को 65,000 करोड़ रुपए से घटाकर 50,000 करोड़ रुपए कर दिया है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में विनिवेश से 51,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य तय किया है। चालू वित्त वर्ष और साथ ही अगले वित्त वर्ष में सरकारी संपत्तियों के मौद्रीकरण से लगभग 10,000 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। पूंजीगत प्राप्तियों के बजट में विनिवेश से मिली रकम को विविध प्राप्तियों के तहत रखा जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट दस्तावेज़ के अनुसार चालू वित्त वर्ष में विविध पूंजीगत प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 60,000 करोड़ रुपए है। इस 60,000 करोड़ रुपए में 50,000 करोड़ रुपए विनिवेश से और 10,000 करोड़ रुपए संपत्ति के मौद्रीकरण से मिले हैं। अगले वित्त वर्ष में विनिवेश से 51,000 करोड़ रुपए सहित विविध पूंजीगत प्राप्तियां 61,000 करोड़ रुपए आंकी गई हैं। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) की वेबसाइट के अनुसार, सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अबतक सीपीएसई में अल्पांश हिस्सेदारी बेचकर 31,100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है, पूरे साल के बजट में इसके लिए 65,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। अगले वित्त वर्ष में आईडीबीआई बैंक के अलावा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, बीईएमएल, एचएलएल लाइफकेयर, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और विजाग स्टील जैसी कंपनियां का निजीकरण करना चाहती है।

नागर विमानन मंत्रालय को आवंटन आधे से ज्यादा घटाया, मिले 3113.36 करोड़ रुपए

नई दिल्ली। लोकसभा में बुधवार को पेश आम बजट 2023-24 में नागर विमानन मंत्रालय के लिए 3,113.36 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह राशि चालू वित्त वर्ष के लिए आवंटित राशि की आधी से कम है। यह कमी विशेष रूप से एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड के लिए निर्धारित राशि में भारी कमी के कारण हुई है। चालू वित्त वर्ष के लिए संशोधित आवंटन 9,363.7 करोड़ रुपए था, जो पूर्व में अनुमानित 10,667 करोड़ से कम था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को लोकसभा में पेश बजट 2023-24 में मंत्रालय के लिए 3,113.36 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आवंटित राशि में यह भारी गिरावट एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) के लिए निर्धारित कम पैसे के कारण है। सरकार की विनिवेश प्रक्रिया के बीच पिछले साल जनवरी में टाटा समूह ने एयर इंडिया का अधिग्रहण कर लिया था।

सरकार ने खिलौनों पर आयात शुल्क बढ़ाकर सत्तर प्रतिशत किया

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को खिलौना और उसके कलपुर्जे तथा सामान पर आयात शुल्क बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया। इस पहल का मकसद इन उत्पादों के आयात में कमी लाना तथा घरेलू विनिर्माण गतिविधियों को गति देना है। बजट दस्तावेज के अनुसार इसी प्रकार, साइकिल के आयात पर भी सीमा शुल्क 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत किया गया है। खिलौनों और उसके कलपुर्जे तथा सामग्री पर आयात शुल्क में वृद्धि में इलेक्ट्रॉनिक खिलौने शामिल नहीं है। स्थानीय स्तर पर खिलौना विनिर्माण को गति देने के लिए फरवरी, 2020 में खिलौनों पर मूल सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि देश में एक समय 2,960 करोड़ रुपए मूल्य के खिलौनों का आयात किया गया था। लेकिन सरकार के कदमों से 2021-22 में आयात घटकर 870 करोड़ रुपए रह गया। दूसरी तरफ, खिलौनों का निर्यात 2021-22 में 61 प्रतिशत बढ़कर 2,601 करोड़ रुपए रहा।

आयकर, कॉरपोरेट कर राजस्व 10.5% बढ़कर 18.23 लाख करोड़ रहने का अनुमान

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को अगले वित्त वर्ष में कॉरपोरेट और व्यक्तिगत आय कर 10.5 प्रतिशत वृद्धि के साथ 18.23 लाख करोड़ रुपए रहने अनुमान है। चालू वित्त वर्ष के लिए प्रत्यक्ष कर राजस्व का संशोधित अनुमान 16.50 लाख करोड़ रुपए रहा है, जबकि बजट अनुमान 14.20 लाख करोड़ रुपए था। चालू वित्त वर्ष (2022-23) में प्रत्यक्ष कर (आय और कॉरपोरेट कर) वित्त वर्ष 2021-22 में इन मदों से अर्जित राजस्व 14.08 लाख करोड़ रुपए से 17 प्रतिशत ज्यादा रहने का अनुमान लगाया गया है। चालू वित्त वर्ष में कॉरपोरेट कर से राजस्व 8.35 लाख करोड़ रुपए जबकि व्यक्तिगत आयकर 8.15 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।

समाचार एजेंसियों के लिए आयकर छूट खत्म करने का प्रस्ताव

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में बजट पेश करते हुए समाचार एजेंसियों की आयकर छूट खत्म करने का प्रस्ताव प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक समाचार एजेंसी है और अगर इस बजट प्रस्ताव को संसद की मंजूरी मिल जाती है तो उसपर भी इसका असर पड़ेगा। बजट के वित्त विधेयक में आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड 22बी में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। अधिसूचित समाचार एजेंसियों को आयकर भुगतान से छूट प्राप्त है, बशर्ते संगठन अपनी आय केवल समाचारों के संग्रह एवं वितरण पर खर्च करता हो और उसे अपने सदस्यों के बीच वितरित नहीं करता हो। वित्त विधेयक के प्रावधानों की व्याख्या करने वाले ज्ञापन में कहा गया है कि समाचार एजेंसियों को मिली कर छूट को हटाने का कदम आयकर अधिनियम के तहत छूट और कटौती को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की सरकार की घोषित नीति के अनुरूप है। अधिनियम की धारा 10 के खंड 22बी के तहत समाचार एजेंसियों को मिली छूट को आकलन वर्ष 2024-25 से वापस लेने का प्रस्ताव है। कई समाचार पत्रों के साझा स्वामित्व वाली पीटीआई को इस खंड के तहत आकलन वर्ष 1994-95 से आयकर छूट मिलती रही है। इसकी वजह यह है कि पीटीआई अपने शेयरधारकों को कोई लाभांश नहीं देती है और यह एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में काम करती है। कंपनी की सभी आय का इस्तेमाल समाचार संग्रह के लिए ही किया जाता है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया को भी आयकर छूट मिली हुई है क्योंकि यह समाचार एजेंसी भी इसी सिद्धांत पर काम करती है।

कृषि उद्योग, किसान संगठनों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

भाषा। नई दिल्ली

कृषि उद्योग से जुड़े लोगों और किसान संगठनों ने बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बजट में खाद्य तेलों पर ध्यान नहीं दिया गया और कृषि उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) घटाने तथा पीएम-किसान योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता बढ़ाने की मांग को अनसुना किया गया है। गोदरेज एग्रोवेट के प्रबंध निदेशक बलराम यादव ने बजट को भारतीय किसानों के लिए तकनीक केंद्रित और समावेशी करार दिया, जबकि सिंजेन्टा इंडिया के मुख्य सस्टेनिबिलिटी अधिकारी के सी रवि ने कहा कि यह कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। भारतीय किसान संघ (बीकेएस) के राघवेंद्र पटेल ने कहा, हालांकि सरकार ने इस बजट में कृषि और किसानों के हित में कई दूरगामी और अच्छे परिणाम देने वाले कदम उठाए हैं, फिर भी किसानों की उम्मीदें इस बजट से कहीं अधिक थीं।

उन्होंने एक बयान में कहा कि कोविड-19 के बाद, किसानों को कृषि लागतों की कीमतों में वृद्धि के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वे पीएम-किसान के तहत वित्तीय सहायता में वृद्धि और विभिन्न लागतों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कमी के रूप में समाधान की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना से किसानों के शोषण पर अंकुश लगेगा, जबकि सहकारी समितियों के माध्यम से छोटे स्थानों पर कृषि उपज के भंडारण के अच्छे परिणाम मिलेंगे।

ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में, एनसीडीईएक्स के प्रबंध निदेशक अरुण रास्ते ने कहा कि भंडारण क्षमता का विकेंद्रीकरण, जिसके बारे में वित्तमंत्री ने बात की है, एक प्रमुख निर्णय है और मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन को युक्तिसंगत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने एक बयान में कहा कि एनसीडीईएक्स एफपीओ और छोटे व्यापारियों के साथ काम करता है जो विनियमित गोदामों का उपयोग करते हैं और मानक विकेंद्रीकृत भंडारण से देश को अत्यधिक बर्बादी को खत्म करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, हालांकि, इसका अधिक प्रभाव होगा यदि वेयरहाउसिंग विकास एवं नियमन प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) विनियमन को जल्द ही संसदीय स्वीकृति मिल जाती है, और इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदें गोदाम रसीदों की जगह ले लेती हैं।

छोटे किसानों को फायदा होगा : कृषि मंत्री

नई दिल्ली। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा कि बजट 2023-24 से देश भर के छोटे किसानों को फायदा होगा, जिसमें आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। तोमर ने कहा कि वित्तवर्ष 2023-24 के लिए उनके मंत्रालय के लिए कुल बजटीय आवंटन बढ़ाकर अनुमानित 1.25 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिसमें सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम-किसान के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन शामिल हैं। मंत्री ने एक बयान में कहा, बजट से छोटे किसानों को लाभ होगा। इसमें प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में कृषि और किसान कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिसमें अगले वित्तवर्ष के लिए कृषि ऋण को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए करना, मोटे अनाज और स्टार्टअप को बढ़ावा देना शामिल है। भारत में कुल कृषकों का 86 प्रतिशत हिस्सा, छोटे और सीमांत किसानों का है, जिनके पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है।

सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) के अध्यक्ष अजय झुनझुनवाला के अनुसार, बजट अपेक्षित तर्ज पर था सिवाय इसके कि यह खाद्य तेलों के मोर्चे पर चुप था क्योंकि उद्योग निकाय खाद्य तेलों पर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की घोषणा की उम्मीद कर रहा था। उन्होंने कहा कि हरित विकास को बढ़ावा देने की घोषणा एक स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि अरंडी खली और नीम बीज खली प्राकृतिक खेती के लिए सबसे अच्छे जैविक खाद हैं और जो उनकी खपत को बढ़ावा देंगे। इस तरह अरंडी के बीज उगाने वाले घरेलू किसानों और नीम के बीज इकट्ठा करने वाले आदिवासियों का समर्थन करेंगे।

झुनझुनवाला ने कहा कि कच्चे ग्लिसरीन पर आयात शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करना भी एक स्वागत योग्य कदम है जिससे घरेलू ग्लिसरीन शोधन उद्योग को मदद मिलेगी। सीएनएच इंडस्ट्रियल इंडिया और सार्क के प्रबंध निदेशक (कृषि प्रभाग) नरिंदर मित्तल ने कहा कि बजट में टिकाऊ कृषि और आर्थिक विकास पर जोर दिया गया है। अनुपम रसायन के प्रबंध निदेशक आनंद देसाई ने कहा कि कुछ कच्चे माल - विकृत इथाइल अल्कोहल, एसिड ग्रेड फ्लोरस्पर और कच्चा ग्लिसरीन - पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट से भारतीय रासायनिक कंपनियों की समग्र उत्पादन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा।

एग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक कल्याण गोस्वामी ने कहा, यह बहुत संतुलित बजट है। इंडियन चैंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर (आईसीएफए) के अध्यक्ष एम जे खान ने कहा, कृषि और ग्रामीण विकास पर बजट में किए गए साहसिक प्रावधान कृषि को टिकाऊ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे और इस प्रक्रिया में किसानों के लिए आय के अधिक अवसर पैदा होंगे। नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉरपोरेशन (एनबीएचसी) के प्रबंध निदेशक और सीईओ रमेश दोरईस्वामी ने कहा, कुल मिलाकर बजट कृषि क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और कृषि-प्रौद्योगिकी कंपनियों के विकास पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण अपने सहयोगी मंत्रीगणों व अधिकारियों के साथ

रियल एस्टेट ने सराहना की

नई दिल्ली। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय रूप से बढ़ोतरी करने वाले आम बजट को रियल्टी उद्योग की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। रियल्टी उद्योग का कहना है कि यह बजट आर्थिक वृद्धि को गति देगा और वैश्विक मंदी के प्रभाव को कम करने में मददगार होगा। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में बुनियादी ढांचा विकास पर पूंजीगत व्यय 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद (नारेडको) के वाइस चेयरपर्सन निरंजन हीरानंदानी ने कहा, भारत ने वैश्विक और आर्थिक चुनौतियों का समझदारी से सामना किया है। इस बजट में देश की आर्थिक वृद्धि के लिए कदम उठाए गए हैं जिनमें बुनियादी ढांचे में पूंजीगत व्यय को बढ़ाना शामिल है।

रियल एस्टेट क्षेत्र के निकाय क्रेडाई के अध्यक्ष (एनसीआर) और गौड़ समूह के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मनोज गौड़ ने कहा, बजट 2023-24 विकासोन्मुखी है। इससे बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिलेगी जो भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंदी से बचाने में मददगार होगा। यह बजट राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने, अनुपालन बोझ को कम करने पर केंद्रित है। कारोबारी सुगमता को बेहतर करने के लिए 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का कदम सराहनीय है।

आम बजट को रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए अच्छा बताते हुए एसकेए समूह के निदेशक संजय शर्मा ने कहा, बजट में समग्र विकास करने वाले कारकों पर जोर दिया गया है, जिसमें पूंजीगत व्यय को 10 लाख करोड़ रुपए करना शामिल है। शहरी बुनियादी ढांचे के लिए 10,000 करोड़ रुपए के प्रावधान से रियल एस्टेट क्षेत्र को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा, वहीं सात लाख रुपए तक की आय पर आयकर छूट की घोषणा रियल एस्टेट के लिए वरदान साबित हो सकती है क्योंकि इससे मध्यम वर्ग में मांग बढ़ेगी। सीआरसी समूह के निदेशक (विपणन एवं व्यवसाय प्रबंधन) सलिल कुमार ने कहा, सरकार ने इस बजट में शहरी बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की जो व्यवस्था की है उससे व्यवस्थित विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसका अप्रत्यक्ष रूप से लाभ आवासीय और वाणिज्यिक दोनों ही क्षेत्रों को मिलेगा।

रहेजा डेवलपर्स के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नवीन एम रहेजा ने कहा, पीएम आवास योजना कोष में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए खर्च में वृद्धि के साथ, यह बजट आवासीय और वाणिज्यिक रियल एस्टेट के विकास को बढ़ावा देने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे देश में रियल एस्टेट का योजनाबद्ध विकास होगा, शहरी जीवनस्तर में भी सुधार होगा और डेवलपर को बेहतर घर प्रदान करने का अवसर मिलेगा। क्रेडाई (पश्चिमी यू.पी.) के अध्यक्ष एवं काउंटी समूह के निदेशक अमित मोदी ने कहा, कारोबारी सुगमता को बढ़ाने के लिए 39,000 से अधिक अनुपालन कम किए गए और 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया, जो इस साल के बजट की सबसे बड़ी उपलब्धि है। रियल एस्टेट को इसका लाभ मिलेगा।

सीमा शुल्क दरों में बदलाव से निर्यात को मिलेगा प्रोत्साहनः गोयल

नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बुधवार को पेश बजट में कुछ उत्पादों पर सीमा शुल्क दरों में बदलाव किए जाने से देश का निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। गोयल ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत से वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात सम्मिलित रूप से करीब 14-15 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। स्वीकार किया कि मौजूदा आर्थिक हालात में विदेशों में वस्तुओं की मौजूदगी अधिक रहने और मुद्रास्फीति की वजह से वस्तु निर्यात थोड़ा कम रह सकता है। मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के बाद अगले वित्त वर्ष में वस्तु निर्यात के मामले में भी बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई। वित्त मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के लिए बजट आवंटन करने में सहृदय रही हैं। ऐसे में मुझे यकीन है कि इससे हमारे निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। कुछ उत्पादों के आयात पर शुल्क की दर में बदलाव के प्रस्तावों पर गोयल ने कहा कि वित्त मंत्री ने बड़ी बुद्धिमानी से शुल्क को ऊपर-नीचे किया है।

सरकार का अडाणी मुद्दे पर टिप्पणी से इनकार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडाणी समूह पर लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों पर कोई टिप्पणी करने से बुधवार को इनकार कर दिया। अडाणी समूह को 90 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने बजट के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, हम सरकार में हैं और किसी निजी कंपनी से संबंधित मुद्दों पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं।

कपड़ा निकायों ने बजट को गति देने वाला बताया

कोयंबटूर। क्षेत्र के प्रमुख कपड़ा निकायों ने बुधवार को केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए इसे मजबूत और स्थिर आर्थिक वृद्धि की ओर लक्षित बताया। तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (टीईए) के अध्यक्ष के एम सुब्रमण्यन ने कहा कि बजट में सात प्राथमिकताओं सप्तऋषि का उल्लेख है जो आर्थिक वृद्धि को गति देंगे। एक बयान में उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देने से लाजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि वह हरित विकास पर ध्यान दिए जाने की सराहना करते हैं। पिछले साल 600 करोड़ रुपए के मुकाबले वित्तवर्ष 2023-24 के लिए एटीयूएफ (संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि) योजना के लिए 900 करोड़ रुपए के बढ़े हुए आवंटन का स्वागत करते हुए, सुब्रमण्यन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बढ़ा हुआ आवंटन एटीयूएफ के लंबित दावों को दूर करने में मदद करेगा। उन्होंने एमएसएमई क्षेत्र के लिए 9,000 करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना के विस्तार का स्वागत किया। सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि सैम ने एक बयान में समावेशी विकास और कौशल विकास पर जोर देने की सराहना की, जो श्रम और पूंजी प्रधान कपड़ा उद्योग को मदद करेगा। भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष टी राजकुमार ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि उत्प्रेरक कोष की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे कृषि पद्धति को बदलने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

आम बजट 2023-24 से रत्न, आभूषण उद्योग निराश

मुंबई। रत्न एवं आभूषण उद्योग ने बुधवार को कहा कि वह वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट से निराश है क्योंकि सरकार ने सीमा शुल्क 10 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। उनका मानना है कि इससे कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा। अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद के अध्यक्ष संयम मेहरा ने कहा कि केंद्रीय बजट 2023-24 में रत्न और आभूषण उद्योग की महत्वपूर्ण चिंताओं को दूर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, एक ओर जहां प्रयोगशाला में विकसित कच्चे हीरे और मशीनों के विकास के लिए एक आईआईटी को अनुसंधान और विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा, वहीं सोने पर सीमा शुल्क में कमी करने जैसे मुद्दों सहित इस उद्योग के अन्य क्षेत्रों को नजरअंदाज कर दिया गया है। यह गंभीर रूप से रत्न एवं आभूषण उद्योग को नुकसान पहुंचाएगा और कालाबाजारी को बढ़ावा देगा। जीजेसी पिछले कई वर्षों से सोने के सीमा शुल्क में कमी करने का आग्रह कर रहा है। हालांकि, इस बजट में अप्रसंस्कृत चांदी छड़ पर शुल्क को सोने और प्लैटिनम के बराबर लाने के लिए बढ़ाया गया है। मेहरा ने कहा, इस कदम से जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हम सरकार से आयात शुल्क कम करने का आग्रह करते रहेंगे। हम चार फरवरी को मुंबई में वित्त मंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं, जहां हम एक बार फिर उद्योग की सीमा शुल्क में कमी, आभूषणों पर ईएमआई, पूंजीगत लाभ कर में राहत और स्वर्ण मौद्रीकरण योजना सहित अन्य महत्वपूर्ण चिंताओं पर जोर देंगे।

वित्त मंत्री ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रयोगशाला में हीरा बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर आयात शुल्क में कटौती का भी प्रस्ताव किया है। विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) के क्षेत्रीय सीईओ भारत, सोमसुंदरम पीआर ने कहा, जबकि सोने पर सीमा शुल्क 12.5 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना सही दिशा में एक कदम है। बजट के एक प्रस्ताव पर सकारात्मक टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि बजट घोषणा के अनुसार भौतिक सोने को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद में बदलने से कोई पूंजीगत लाभ नहीं होगा। हालांकि, बजट में सोने, चांदी और प्लैटिनम पर आयात शुल्क में कमी के मुद्दे पर विचार नहीं किया गया। जीजेईपीसी के पूर्व अध्यक्ष और कामा के प्रबंध निदेशक, कोलिन शाह ने कहा कि वित्त मंत्री ने निर्यात और रोजगार सृजित करने के लिए लैब में विकसित हीरों की क्षमता को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, पांच साल के लिए एक आरएंडडी अनुदान, स्थानीय विनिर्माण क्षमता बनाने में मदद करेगा, जिससे आने वाले वर्षों में मशीनरी के आयात पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। पीएनजी ज्वेलर्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सौरभ गाडगिल ने कहा कि इस साल के बजट में सबसे बड़ी निराशा यह है कि इसने सोने पर आयात शुल्क में कमी के मसले को हल नहीं किया गया है।

वाहन उद्योग ने विकासोन्मुख बताया

नई दिल्ली। वाहन उद्योग ने बुधवार को पेश आम बजट 2023-24 को विकासोन्मुख बताते हुए कहा है कि प्रस्तावित कदमों से तेज गति से स्थाई लेकिन समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। वाहन उद्योग की संस्था भारतीय वाहन विनिर्माता सोसायटी के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने कहा कि 13.7 लाख करोड़ रुपए के प्रभावी प्रस्ताव के साथ पूंजी परिव्यय में 33 प्रतिशत वृद्धि से अर्थव्यवस्था वृद्धि को गति मिलेगी, जिससे घरेलू वाहन उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वाहन कलपुर्जा विनिर्माता संघ के अध्यक्ष संजय जे कपूर ने कहा कि यह बजट डिजिटल रूप से सक्षम आत्मनिर्भर भारत का खाका है, जिसमें ऐसे कदमों का समावेश किया गया है, जो अर्थव्यवस्था को तेज गति से स्थाई लेकिन समावेशी वृद्धि प्रदान करेंगे। उन्होंने आगे कहा, निर्यात, विनिर्माण, स्थानीय मूल्यवर्द्धन पर केंद्रित और हरित ऊर्जा और परिवहन को बढ़ावा देने वाले कदम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। व्यक्तिगत आयकर के प्रस्तावों से लोगों के हाथ में और ज्यादा पैसा आएगा, जिससे खपत बढ़ेगी और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

वाहन डीलरों के संगठन फाडा के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने कहा कि अवसंरचना व्यय में 10 लाख करोड़ की पूंजी परिव्यय से वाहन बिक्री को मदद मिलेगी। इसके अलावा व्यक्तिगत कर स्लैब में कटौती से दोपहिया और यात्री वाहन उद्योग को लाभ होगा। इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माता सोसायटी के महानिदेशक सोहिंदर गिल ने कहा कि अच्छी गुणवत्ता के मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन कलपुर्जों की कमी के मुश्किल दौर से निकलने के बाद स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला ने आकार लेना शुरू कर दिया है। मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आर सी भार्गव ने कहा कि सरकार वर्षों से अवसंरचना निर्माण पर व्यय बढ़ाकर कारोबारी सुगमता बढ़ाने की कोशिश की है।

उन्होंने कहा कि अगले साल चुनाव से पहले अंतिम पूर्ण बजट होने के बावजूद सरकार लोकलुभावन वादों से दूर रही और विकासोन्मुख बजट पेश किया। टीवीएस मोटर कंपनी के प्रबंध निदेशक सुदर्शन वेणु ने इस बजट को बेहतर तरीके से तैयार दस्तावेज बताया। उन्होंने कहा, अवसंरचना पर बढ़ते व्यय पर जोर और लीथियन आयन बैटरी विनिर्माण को सहयोग से इस उद्योग को बहुत लाभ होगा।

कटौती, छूट दावा 3.75 लाख से कम होने पर नई कर व्यवस्था फायदेमंद

नई दिल्ली। किसी करदाता का अगर सालाना कटौती और छूट दावा 3.75 लाख रुपए से कम है तो उसे नई कर व्यवस्था अपनाने से लाभ होगा और उसे पुरानी कर व्यवस्था के मुकाबले कम कर का भुगतान करना होगा। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि आयकर विभाग करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न भरने को लेकर सरल और कम कर दर वाली व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरे आकलन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 का बजट पेश करते कहा कि सरकार ने मध्यम वर्ग के लाभ के लिए नई कर व्यवस्था के ढांचे में बदलाव के साथ करदाताओं के लिए नई कर व्यवस्था को अधिक आकर्षक बनाया है। बजट में किए गए प्रस्ताव के अनुसार, नई कर व्यवस्था के तहत सात लाख रुपए तक की सालाना आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा। हालांकि, निवेश और आवास भत्ता जैसी छूट वाली पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई व्यवस्था के तहत आयकर रिटर्न भरते समय अगर किसी करदाता का कटौती को लेकर दावा 3.75 लाख रुपए से कम है, तो उसे नई कर कर व्यवस्था अपनाने की सलाह होगी। उन्हें बजट में किए गए प्रस्ताव के अनुसार लाभ मिलेगा और उन पर कम कर देनदारी बनेगी। आयकर रिटर्न के आंकड़ों के विश्लेषण के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है। अधिकारी ने कहा, हमें भरोसा है कि नई कर व्यवस्था अपनाने वाले करदाताओं की संख्या पुरानी व्यवस्था अपनाने वाले से अधिक होगी। कर विभाग पूर्व की तरह इस संदर्भ में ऑनलाइन कैलकुलेटर उपलब्ध करा सकता है।

नई दिल्ली में लोकसभा में बजट सत्र में उपस्थित सोनिया गांधी राहुल गांधी व अन्य सांसद

अमेरिकी उप रक्षामंत्री कैथलीन हिक्स ने एनएसए अजीत डोभाल से कहा

गठबंधन और साझेदारी सर्वोच्च प्राथमिकता

हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रतिस्पर्धी रणनीतिक माहौल और चीन के आक्रामक व्यवहार के बीच अहम मुलाकात

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिका की उप रक्षा मंत्री डॉ. कैथलीन हिक्स ने यहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल से मुलाकात में कहा कि उनके विभाग के लिए गठबंधन और साझेदारी का निर्माण करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन ने यह जानकारी दी।हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रतिस्पर्धी रणनीतिक माहौल और चीन के आक्रामक व्यवहार के बीच यह मुलाकात हुई। पेंटागन ने मंगलवार को कहा कि हिक्स ने यहां डोभाल के साथ बैठक के दौरान अमेरिका-भारत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी के लिए प्राथमिकताओं पर चर्चा की। पेंटागन के अनुसार, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नीतियों व उनके संचालन में समन्वय को गहरा करने और दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। भारतीय दूतावास ने मंगलवार को ट्वीट किया, दोनों ने अमेरिका-भारत रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। पेंटागन के प्रवक्ता एरिक पाहोन ने बैठक के बाद एक बयान में कहा कि हिक्स ने दोहराया कि गठबंधन बनाना तथा साझेदारी करना उनके मंत्रालय की पहली प्राथमिकता है और अमेरिकी राष्ट्रीय रक्षा रणनीति का अभिन्न अंग भी है। पाहोन ने बताया कि उन्होंने (हिक्स ने) क्षेत्र में भारत के नेतृत्व के लिए डोभाल का शुक्रिया अदा किया और साथ ही अमेरिका तथा भारतीय सेनाओं के बीच समन्वय को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की ताकि क्षेत्र के तेजी से बढ़ते विवादित रणनीतिक माहौल से निपटा जा सके। उन्होंने कहा, दोनों ने अमेरिका और भारतीय कंपनियों के बीच अभिनव संयुक्त प्रयासों के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा की जो भारत की विशिष्ट संचालन की जरूरतों के अनुरूप है। बैठक के रीडआउट (जानकारी) के अनुसार, हिक्स और डोभाल ने कहा कि वे अमेरिका-भारत रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए तत्पर हैं।

भारत, अमेरिका ने आईसीईटी की पहली बैठक की : राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने यहां अपने अमेरिकी समकक्ष जेक सुलिवन के साथ मिलकर इनीशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (आईसीईटी) की पहली उच्च-स्तरीय बैठक की। व्हाइट हाउस ने यह जानकारी दी।व्हाइट हाउस ने मंगलवार को डोभाल और सुलिवन के बीच आईसीईटी की पहली बैठक के समापन के बाद एक फैक्ट शीट (तथ्यात्मक जानकारी) में कहा, हम आपसी विश्वास और भरोसे पर आधारित एक मुक्त, सुलभ और सुरक्षित प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करेगा। मई 2022 में तोक्यो में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के बीच बैठक के बाद पहली बार एक संयुक्त बयान में आईसीईटी का उल्लेख किया गया था। इसका मकसद दोनों देशों की सरकारों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सामरिक प्रौद्योगिकी साझेदारी तथा रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ाना व विस्तारित करना है। व्हाइट हाउस ने कहा, अमेरिका और भारत इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रौद्योगिकी को डिज़ाइन, विकसित, शासित और उपयोग करने के तरीकों में हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों तथा सार्वभौमिक मानवाधिकारों का ध्यान रखा जाएगा। हम आपसी विश्वास और भरोसे पर आधारित एक मुक्त, सुलभ और सुरक्षित प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों तथा लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करेगा। डोभाल और सुलिवन ने अपने-अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ इस उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) के प्रशासक, नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक, नेशनल स्पेस काउंसिल के कार्यकारी सचिव और विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका समूह की बैठक

वाशिंगटन। द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीके पर चर्चा करने के लिए भारत और अमेरिका के शीर्ष अंतरिक्ष अधिकारियो ने यहां मुलाकात की।अमेरिका मे भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने एक ट्वीट में कहा, भारत और अमेरिका द्विपक्षीय अंतरिक्ष साझेदारी को उच्च कक्षाओ (ऑर्बिट) मे ले जाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैउ उनकी टिप्पणी मंगलवार को विदेश विभाग के फोगी बॉटम मुख्यालय में नासा के प्रशासक बिल नेल्सन और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के साथ भारत-अमेरिका सिविल स्पेस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप (सीएसजेडब्ल्यूजी) को संबोधित करने के बाद आई है। सीएसजेडब्ल्यूजी की आठवी बैठक 30-31 जनवरी के बीच हुई।

भारत, अमेरिका प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षेत्र में करीबी सहयोग के लिए तैयार

वाशिंगटन। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत के डोभाल और उनके अमेरिकी समकक्ष जेक सुलिवन द्वारा क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (आईसीईटी) पर भारत-अमेरिका पहल की शुरुआत एक महत्वपूर्ण संकेत है कि दोनो देश बाधाओ को तोड़ने, प्रौद्योगिकी में संबंधो को बढ़ावा देने और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल और सुलिवन ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में अपने संबंधित उच्चाधिकार प्राप्त प्रतिनिधिमंडलों के साथ पहले आईसीईटी संवाद के लिए मुलाकात की। सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी में हिंद-प्रशांत सुरक्षा कार्यक्रम की वरिष्ठ फेलो और निदेशक लीज़ा कर्टिस ने पीटीआई-भाषा को बताया, भारत और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच पहली आईसीईटी बैठक का आयोजन संबंधो के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर है और यह संकेत देता है कि दोनो पक्ष निकट प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के वास्ते बाधाओ को तोड़ने के लिए तैयार है।

मोदी को बाइडेन ने किया आमंत्रित

जी 20 बैठक से पहले जून में जा सकते हैं यूएस, अमेरिकी संसद में भाषण भी देंगे

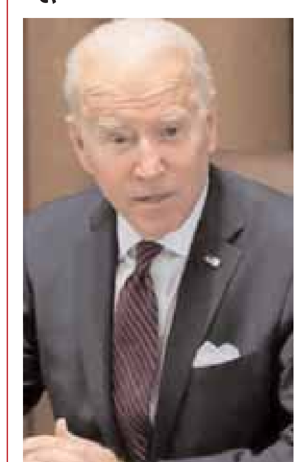

भाषा। **वाशिंगटन**

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस साल गर्मियों में अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक माना जा रहा है कि बाइडन ने मोदी को देश की राजकीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। सूत्रों ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि इस निमंत्रण को सैद्धांतिक रूप में स्वीकार कर लिया गया है और दोनों पक्षों के अधिकारी अब पारस्परिक रूप से यात्रा की संभावित तारीखों पर चर्चा कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि अभी योजना पर चर्चा प्रारंभिक चरण में हैं।

भारत इस वर्ष जी-20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत इस साल जी-20 से संबंधित कई कार्यक्रमों की मेजबानी भी कर रहा है, जिसके तहत सितंबर में एक शिखर सम्मेलन होगा जिसमें अन्य लोगों के साथ बाइडन की हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के अधिकारी जून और जुलाई में उपयुक्त तारीखों की तलाश कर रहे हैं। उस समय न केवल अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट के सत्र चल रहे होंगे, बल्कि तब प्रधानमंत्री मोदी के भी कोई पूर्व निर्धारित घरेलू या अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं हैं। यह राजकीय यात्रा कम से कम कुछ दिनों की होगी, जिसमें अन्य बातों के अलावा अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करना और व्हाइट हाउस में राजकीय रात्रिभोज शामिल होने की संभावना है। जी-20 के अलावा, प्रधानमंत्री मोदी को साल के उत्तरार्ध में कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करना है। साथ ही इस वर्ष के अंत में कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी के लिए प्रचार का जिम्मा भी उनपर होगा। सूत्रों ने हालांकि यह जानकारी नहीं दी कि यह निमंत्रण कब दिया गया और बाइडन की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय को यह व्यक्तिगत निमंत्रण किसने दिया। बाइडन ने पिछले साल दिसंबर में अपने पहले राजकीय रात्रिभोज में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रां की मेजबानी की थी।

राजद्रोह के मामले में पाकिस्तान के पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी को जमानत दी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने राजद्रोह के एक मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी को बुधवार को जमानत दे दी और उनकी रिहाई का आदेश दिया। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी सहयोगी 52 वर्षीय चौधरी को पिछले सप्ताह लाहौर में उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था।पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग के सचिव की शिकायत पर इस्लामाबाद के कोहसर पुलिस थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। निर्वाचन आयोग के सचिव ने चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर आयोग के सदस्यों और उनके परिवारों को धमकी देने का आरोप लगाया था। एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सोमवार को मामले में उनकी हिरासत के लिए पुलिस के अनुरोध को खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायाधीश फैजान गिलानी ने बुधवार को राजद्रोह के मामले में बीस हजार रुपए के मुचलके पर चौधरी को जमानत दे दी। चौधरी पर निर्वाचन आयोग के सदस्यों को सार्वजनिक रूप से धमकाने के लिए राजद्रोह का आरोप लगाया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उनकी गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर उनकी रिहाई की मांग की थी।

रूसी सेना का ध्यान पूर्वी यूक्रेन पर, नए सिरे से हमले की आशंका

कीव। रूस, यूक्रेन के लुहांस्क क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। स्थानीय अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। यूक्रेन इसे आने वाले सप्ताहों में रूस का हमला शुरू होने के एक साल पूरा होने के मौके पर पूर्वी क्षेत्र में हमले की तैयारी के रूप में देख हा है। लुहांस्क के गवर्नर सेरही हैदई ने कहा कि रूसी सेना अपने कब्जे वाले हिस्सों के पास घरों से स्थानीय लोगों को निकाल रही है ताकि वे यूक्रेन के आयुध भंडारों में रूसी सैनिकों की तैनाती के बारे में सूचना नहीं दे सकें। हैदई ने कहा, इस क्षेत्र में रूसी सैनिकों को सक्रियता के साथ भेजा जा रहा है और वे निश्चित रूप से फरवरी में पूर्वी भाग में किसी बड़ी तैयारी के साथ जा रहे हैं। आगामी 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमलों की शुरुआत को एक साल पूरा हो जाएगा।

पोप ने कॉन्गो और दक्षिण सूडान की छह दिवसीय यात्रा शुरू की

किंशासा (कॉन्गो)। पोप फ्रांसिस ने मंगलवार को अफ्रीकी देश कॉन्गो और दक्षिण सुडान की छह दिवसीय यात्रा शुरू की। पोप की इस यात्रा का मकसद इन दो देशों को शांति का संदेश देना है जो गरीबी व संघर्ष से जूझते रहे हैं। पोप के अनुसार ए देशौ उपनिवेशवादी मानसिकतौ का भी सामना कर रहे हैं। सहायता समूह उम्मीद कर रहे हैं कि फ्रांसिस की यात्रा दुनिया के इन दो संघर्षों पर प्रकाश डालेगी और अफ्रीका के सबसे खराब मानवीय संकटों पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करेगी। पोप ने पिछले हफ्ते एसोसिएटिड प्रेस से कहा था, जी हां अफ्रीका में उथल-पुथल है और वह शोषकों के हमलों से जूझ रहा है। उनकी कॉन्गो की यात्रा पिछले साल जुलाई में होनी थी लेकिन उनकी घुटनों की तकलीफ की वजह से इसे टाल दिया गया था। वह कॉन्गो से दक्षिण सुडान जाएंगे।

पश्चिमी आस्ट्रेलिया में ट्रक से गिरा रेडियोधर्मी कैप्सूल खोजा गया

पर्थ। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में अधिकारियों ने बुधवार को उस छोटे खतरनाक रेडियोधर्मी कैप्सूल को तलाश लिया जो पिछले माह इस।,400 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर ढुलाई के दौरान ट्रक से गिर गया था। अधिकारी ने कहा कि उक्त कैप्सूल को ढूंढना भूसे के ढेर से एक सूई खोजने जैसा था। अधिकारियों ने बताया कि मटर के आकार का यह कैप्सूल न्यूमैन के दक्षिण में ग्रेट नॉर्दर्न हाईवे पर मिला। अधिकारियों ने बताया कि इसका पता 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहे एक खोजी वाहन द्वारा लगाया गया जब विशेषज्ञ उपकरण ने कैप्सूल से निकलने वाले विकिरण से इसकी पहचान की। आपातकालीन सेवा मंत्री स्टीफन डॉसन ने कहा, यह एक असाधारण परिणाम है ... उन्होंने वास्तव में भूसे के ढेर में सुई ढूंढ ली है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी एंडी रॉबर्टसन ने कहा कि कैप्सूल से किसी को किसी तरह की क्षति पहुंचने की सूचना नहीं है।

भारतीय अमेरिकी निक्की हेली बन सकती हैं कैंडिडेट

यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन 2024: ट्रम्प से जीतनी होगी बाजी

भाषा। वाशिंगटन

भारतीय मूल की अमेरिकी और रिपब्लिकन पार्टी की नेता निक्की हेली 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने की अपनी योजना की औपचारिक घोषणा 15 फरवरी को कर सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती पेश करने वाली पार्टी की पहली नेता होंगी। हेली (51) दो बार दक्षिण कैरोलाइना की गवर्नर रह चुकी हैं और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत के तौर पर भी सेवाएं दी हैं। अगर वह इस पद के लिए दावेदारी करती हैं तो हेली अपने पूर्व बॉस (ट्रंप) के खिलाफ मुकाबले में उतरने वाली पहली दावेदार होंगी। ट्रंप वर्तमान में अपनी पार्टी की तरफ से 2024 में राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए दावेदारी करने वाले एकमात्र रिपब्लिकन हैं। ट्रंप (76) ने पिछले साल व्हाइट हाउस के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक, हेली इस हफ्ते जल्द से जल्द अपनी योजनाओं का संकेत देने वाला एक वीडियो जारी कर सकती हैं। द पोस्ट एंड कूरियर की खबर के मुताबिक पूर्व गवर्नर के समर्थकों को जल्द ही हेली की 15 फरवरी को होने वाली विशेष घोषणा का उल्लेख किए जाने से संबंधित एक निमंत्रण पत्र मिल सकता है। यह कार्यक्रम चार्ल्सटन विजिटर सेंटर के द शेड में होगा जिसमें उनके सैकड़ों समर्थकों के जुटने की संभावना है। दक्षिण कैरोलाइना स्थित एक दैनिक द चार्ल्सटन ने खबर दी, 31 जनवरी को हेली के करीबियों से इस बात की पुष्टि हुई कि वह इस दौड़ में शामिल हो रही हैं। हेली की पूर्व में कही गई यह बात काफी चर्चित रही थी कि अगर वह (ट्रंप) फिर से चुनाव लड़ेंगे तो वह उन्हें चुनौती नहीं देना चाहेंगी लेकिन हाल के दिनों में उनके रुख में बदलाव आया है क्योंकि उन्होंने कहा कि अमेरिका को एक अलग दिशा की ओर देखने की जरूरत है।

एफबीआई ने बाइडन के घर की तलाशी ली

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति के निजी वकील ने कहा कि एफबीआई ने गोपनीय दस्तावेजों से संबंधित अपनी जांच के तहत बुधवार को जो. बाइडन के रेहोबोथ बीच, डेलवेयर स्थित घर की तलाशी ली। यह तलाशी 20 जनवरी को उनके विलमिंगटन, डेलवेयर आवास की 13 घंटे तक हुई छानबीन के बाद ली गई। पहले की तलाशी में राष्ट्रपति के आवास से कुछ अतिरिक्त गोपनीय दस्तावेज मिले थे। बाइडन के वकील बॉब बौएर ने कहा कि राष्ट्रपति ने जांच के तहत स्वेच्छा से न्याय विभाग को अपने आवासों की तलाशी लेने को कहा है। बाइडन के आवास और कार्यालय से कई गोपनीय दस्तावेज मिले हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यह उस समय के हैं जब बाइडन उपराष्ट्रपति थे।

इमरान खान को आखिरी मौका : इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत ने प्रतिबंधित निधि मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान के वीडियो लिंक के माध्यम से कार्यवाही में शामिल होने के अनुरोध को खारिज कर दिया और उन्हें 15 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आखिरी मौका दिया।

चीन हमले की तैयारी में ताइवान भी हुआ सचेत

सैन्य विमान और युद्धपोत की तैनाती के बीच ताइवान ने अपनी प्रतिरक्षा को सक्रिय किया

एजेंसी। ताइपे

ताइवान ने चीन के 34 सैन्य विमानों और नौ युद्धपोतों की तैनाती के बीच अपने लड़ाकू विमानों को उतारते हुए अपनी नौसेना को सचेत किया और मिसाइल सिस्टम को सक्रिय कर दिया। यह तैनाती ऐसे वक्त हुई है जब चीन ने ताइवान के खिलाफ संभावित नाकाबंदी या हमले की तैयारी बढ़ाई है, जिससे ताइवान के प्रमुख सहयोगी अमेरिका की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। पिछले महीने एक पत्र में अमेरिकी वायु सेना के जनरल माइक मिनिहान ने अधिकारियों को 2025 में ताइवान को लेकर अमेरिका-चीन संघर्ष के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया था। एयर मोबिलिटी कमान के प्रमुख के रूप में, मिनिहान को चीनी सेना की गहरी समझ है और उनकी टिप्पणियां अमेरिका द्वारा तैयारी बढ़ाने के आह्वान के अनुरूप हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 20 चीनी विमानों ने मंगलवार को ताइवान जलडमरूमध्य में सेंट्रल लाइन को पार किया जो लंबे समय से अनौपचारिक बफर जोन रहा है। चीन ताइवान को अपना क्षेत्र बताता है, जबकि ताइवान के अधिकतर लोग चीन की सत्तारुढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में आने का विरोध करते हैं। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि ताइवान के सशस्त्र बलों ने इन गतिविधियों का जवाब देने के लिए स्थिति की निगरानी की। चीन ने लगभग दैनिक आधार पर ताइवान के पास हवाई क्षेत्र में युद्धपोत, बमवर्षक, लड़ाकू विमान भेजे हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की तत्कालीन अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी और यूरोपीय संघ के कई नेताओं के हाल के महीनों में ताइवान के दौरे के बीच दोनों पक्षों ने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। पिछले साल अगस्त में पेलोसी की यात्रा पर आपत्ति जताते हुए चीन ने ताइवान के आसपास युद्धाभ्यास किया था और मिसाइल दागी थी। ताइवान से करीबी संबंध रखने वाले देशों के खिलाफ चीन ने बदले की कार्वाई की चेतावनी दी है।

ब्रिटेन में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर शिक्षकों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की हड़ताल: लंदन, । ब्रिटेन में बुधवार को शिक्षक, विश्वविद्यालय के व्याख्याता, ट्रेन और बस चालक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए। देश में लगभग एक दशक में इस तरह की स्थिति पहली बार उत्पन्न हुई है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के आधिकारिक प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि इस सामूहिक हड़ताल से जनता कोै भारी परेशानीै का सामना करना पड़ेगा। इंग्लैंड और वेल्स में शिक्षकों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया है, जिससे 23,000 स्कूल प्रभावित हुए हैं। इन क्षेत्रों में लगभग 85 प्रतिशत स्कूलों के पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद रहने का अनुमान जताया गया है। शिक्षा मंत्री गिलियन कीगन ने कहा, मैं इस बात से निराश हूं कि कर्मचारी संघों ने इस तरह का निर्णय लिया है।

पेशावर मस्जिद हमले में 17 संदिग्ध गिरफ्तार

पेशावर/इस्लामाबाद (भाषा)

पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने पेशावर में एक उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में स्थित मस्जिद में हुए आत्मघाती विस्फोट के सिलसिले में 17 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने आतंकवादी समूहों के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाने का संकल्प व्यक्त किया और सेना के अधिकारियों को आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का निर्देश दिया। पेशावर में हुए इस हमले में 97 पुलिसकर्मियों समेत 101 लोग मारे गए हैं। सोमवार को दोपहर की नमाज के दौरान आगे की कतार में मौजूद तालिबान के आत्मघाती हमलावर ने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया था। सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान में पिछले कई सालों में सुरक्षाकर्मियों पर हुए इस सबसे भयावह हमले में शामिल होने के संदेह में 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने पीटीआई-भाषा को बताया कि पुलिस लाइन्स इलाके के नजदीकी क्षेत्रों से गिरफ्तारियां की गई हैं और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। इस बीच, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को एक बयान में कहा कि आतंकवाद के खतरे को समाप्त करने के लिए पूरा देश एकजुट है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पुलिस को अग्रिम मोर्चे का बल करार देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें और मजबूत किया जाएगा और आधुनिक हथियारों से लैस किया जाएगा। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) या पाकिस्तानी तालिबान ने आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि उनके कथित कमांडर उमर खालिद खुरासानी की पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान में हुई मौत का बदला लेने के लिए यह हमला किया गया।

यूक्रेनः हालात के साथ महिलाओं के प्रति बदल रहा है दृष्टिकोण

हजारों महिलाएं संभाल रहीं सेना में मोर्चा

एजेंसी। एब्रिस्विथ

(द कन्वरसेशन) क्रीमिया तथा पूर्वी यूक्रेन के क्षेत्रों पर 2014 में रूस द्वारा कब्जा करने की शुरूआत के बाद से यूक्रेन की सेना में हजारों महिलाएं स्वेच्छा से शामिल हुई हैं। पिछले नौ साल से अधिक समय में यूक्रेन की सेना में शामिल होने वाली महिलाओं की संख्या दोगुने से अधिक हो गई है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के पूरी ताकत के साथ हमला किए जाने के बाद यूक्रेन की सेना में शामिल होने के लिए महिलाओं के बीच एक लहर चल पड़ी है। ऐसे तो सोवियत संघ से 1991 में आजाद होने के बाद से ही यूक्रेन के सशस्त्र बल में महिलाएं अपनी सेवा दे रही हैं, लेकिन उनकी महत्वपूर्ण भूमिका 2014 की लड़ाई की के बाद से शुरू हुई। महिलाओं ने 2016 में लड़ाकू भूमिकाओं में काम करना शुरू किया और 2022 में सभी सैन्य भूमिकाओं को महिलाओं के लिए खोल दिया गया। हालांकि, गैर-लड़ाकू भूमिका में शामिल कई महिलाएं, जैसे कि मेडिक्स, भी संघर्षरत और युद्ध के मोर्चे पर डटे अपने पुरुष और महिला सहयोगियों के समान ही खतरों और कठिनाइयों में हैं।यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री हन्ना मलियार के अनुसार, 2022 की गर्मियों तक 50 हजार से अधिक महिलाओं को सेना में विभिन्न भूमिकाओं में लिया गया है, इनमें से करीब 38 हजार महिलाएं वर्दीधारी हैं। उनके अनुसार महिलाएं अब अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं में भी शामिल हैं।

सशस्त्र बलों में शामिल महिलाओं को रूसियों द्वारा युद्धबंदी बनाया जा रहा है। यूक्रेनी मेडिक्स यूलिया पेवेस्का को तीन महीने की कैद हुई थी। पेवेस्का ने बताया, हम लोगों के साथ जो व्यवहार किया गया वह बेहद कठिन और कठोर था। पितृसत्तात्मक सोच बदल रही है- यूक्रेन एक ऐसा देश है जहां, पितृसत्तात्मक परंपरा बेहद मजबूत है, खास तौर से रक्षा क्षेत्र में। लेकिन यूक्रेन की महिला सैनिकों को यूक्रेन का समाज और देश का राजनीतिक नेतृत्व युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर स्वीकार कर रहे हैं। सेना और समाज में महिलाओं की उपस्थिति को पहचान का एक संकेत तब मिला जब 2021 में नेशनल डिफेंडर्स डे का नाम बदल कर डे ऑफ मेन एंड वूमन डिफेंडर्स ऑफ यूक्रेन कर दिया गया।

रक्षा मंत्रालय अपने सोशल मीडिया पोस्ट में महिला सैनिकों की तस्वीर अब नियमित तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन की महिला सैनिक भी अक्सर सुर्खियों में रहती हैं और वह अपने सैन्य अनुभव के बारे में बातचीत करती रहती हैं।

भारत ने न्यूजीलैंड को 168 रन से हराकर जीती शृंखला

शुभमन गिल का टी20 में पहला शतक

भाषा। अहमदाबाद

अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के विरुद्ध शतक लगाने के बाद उत्साहित शुभमन गिल

भारत ने शुभमन गिल के टी20 अंतरराष्ट्रीय में पहले (नाबाद 126 रन) शतक के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत बुधवार को यहां तीसरे और अंतिम मैच में न्यूजीलैंड को 168 रन से हराकर रनों के हिसाब से इस प्रारूप में सबसे बड़ी जीत दर्ज कर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। भारत ने इससे पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत आयरलैंड के खिलाफ (143 रन से) 2018 में डबलिन में हासिल की थी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के दो पूर्णकालिक देशों के बीच रनों के लिहाज से यह सबसे बड़ी जीत है। गिल ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को चारों ओर पीटते हुए अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी।

उन्होंने महज 63 गेंद में 12 चौके और सात छक्के जमाए जिससे भारत ने चार विकेट पर 234 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। गिल का भारतीय बल्लेबाजों में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे बड़ा स्कोर भी है। गिल ने इस मामले में पूर्व कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़ा। कोहली ने पिछले साल अफगानिस्तान के खिलाफ नाबाद 122 रन की पारी खेली थी। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 12.1 ओवर में 66 रन ही बना सकी। उसके लिए डेरिल मिचेल 35 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। केवल एक अन्य बल्लेबाज मिचेल सैंटनर (13 रन) ही दोहरे अंक तक पहुंच सके।

भारत के लिए कप्तान और ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या (16 रन देकर चार विकेट) ने अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन किया। उनके अलावा अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक और शिवम मावी ने दो दो विकेट झटके। गेंदबाजों का क्षेत्ररक्षकों ने भी पूरा साथ दिया और कैच करने के किसी भी मौके को बर्बाद नहीं किया जिसमें सूर्यकुमार यादव ने तीन कैच लपके। न्यूजीलैंड को शुरुआती झटका पहले ही ओवर में लगा जब सलामी बल्लेबाज फिन एलेन भारतीय कप्तान हार्दिक की गेंद पर सूर्यकुमार यादव ने शानदार कैच लपक लिया। अर्शदीप सिंह ने दूसरे ओवर में डेवोन कॉनवे और मार्क चैपमैन को आउट कर न्यूजीलैंड को दो झटके दे दिए जिससे उसका स्कोर तीन विकेट पर पांच रन था। अब टीम की उम्मीदें ग्लेन फिलिप्स (02 रन) पर लगी थीं लेकिन वह भी टीम की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके और तीसरे ओवर में हार्दिक का दूसरा शिकार हुए।

उमरान मलिक ने अपने पहले ही ओवर में माइकल ब्रेसवेल (08) को बोल्ड कर दिया जिससे पांचवें ओवर में 21 रन पर न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। शिवम मावी के पहले ही ओवर में मिचेल सैंटनर (13) और ईश सोढ़ी को चलता किया। फिर हार्दिक ने लॉकी फर्ग्यूसन और ब्लेयर टिकनर को आउट कर अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन किया। उमरान मलिक के ब्रेसवेल को आउट करते ही भारतीय टीम ने रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत दर्ज की। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरूआत इतनी अच्छी नहीं रही और मिचेल सैंटनर ने माइकल ब्रेसवेल को दूसरा ओवर देकर मास्टर स्ट्रोक खेला। इस ऑफ स्पिनर ने भी अपने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन को पगबाधा आउट कर दिया। फॉर्म में चल रहे गिल ने अगले ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन पर दो चौके जड़े। उन्होंने हिट, ड्राइव और पुल शॉट से दर्शकों के लिए मनोरंजन दोगुना कर दिया। गिल ने पांचवें ओवर में ब्लेयर टिकनर पर तीन चौके जड़े जिससे स्कोर एक विकेट पर 44 रन हो गया। युवा राहुल त्रिपाठी (22 गेंद में 44 रन) ने भी तेज लय जारी रखते हुए फर्ग्यूसन पर लगातार गेंदों पर एक चौके और एक छक्का लगाया। त्रिपाठी ने फिर सैंटनर पर शार्ट फाइन लेग पर चौका और सीधे एक छक्का जड़ा। वह आक्रामक दिख रहे थे और ईश सोढ़ी पर एक्स्ट्रा कवर पर अपनी पारी का तीसरा छक्का जड़ा। पर ऐसा ही बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डीप स्क्वायर लेग पर फर्ग्यूसन को कैच दे बैठे। गिल ने सैंटनर की गेंद पर एक रन बनाकर 35 गेंद में अपना पहला टी20 अर्धशतक जड़ा। गिल एक छोर पर डटे थे और सूर्यकुमार यादव (13 गेंद में 24 रन) उनके साथ क्रीज पर थे जिन्होंने भी तेजी से रन जोड़ने की लय बनाए रखी, पर 13वें ओवर में मिड ऑफ पर ब्रेसवेल को कैच देकर आउट हुए।

गिल ने 18वें ओवर की पहली गेंद पर फर्ग्यूसन की गेंद पर मिड ऑफ में चौका जड़कर अपना शतक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने स्वच्छंदता से बल्लेबाजी करते हुए इसी गेंदबाज की अगली गेंद को गगनदाई छक्के के लिए भेज दिया। कप्तान हार्दिक पंड्या (17 गेंद में 30 रन) ने भी रन गति को कम नहीं होने दिया। लेकिन गिल ने शतक के बाद अपनी आक्रामकता तेज कर दी और न्यूजीलैंड का गेंदबाजी आक्रमण लचर दिखाई दिया।

खेलों के लिए सरकार ने 700 करोड़ अधिक दिए

केंद्रीय बजट में 3,397.32 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया

भाषा। नई दिल्ली

इस साल होने वाले एशियाई खेलों और अगले साल के लिए प्रस्तावित पेरिस ओलंपिक की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए खेल मंत्रालय के लिए बुधवार को पेश केन्द्रीय बजट में 3,397.32 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है जो पिछले साल के मुकाबले 723.97 करोड़ रुपए अधिक है। यह राशि पिछले वित्तीय वर्ष (2022-23) के संशोधित बजट से अधिक है, जब मंत्रालय को 2,673.35 करोड़ रुपए मिले थे। पिछले साल हालांकि वास्तविक आवंटन 3,062.60 करोड़ रुपए था। साल 2022-23 के लिए संशोधित आवंटन में कटौती का एक मुख्य कारण चीन में प्रस्तावित एशियाई खेलों का स्थगन हो सकता है। इन खेलों का आयोजन इस साल होगा। मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम, खेलो इंडिया - खेल के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है, इसे पिछले वित्त वर्ष के दौरान 606 करोड़ रुपए के संशोधित आवंटन के मुकाबले 1,045 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

इसमें 439 करोड़ रुपए की वृद्धि कार्यक्रम के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस आयोजन ने पिछले कुछ वर्षों में ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों जैसे प्रमुख वैश्विक आयोजनों के लिए एथलीट तैयार करने की क्षमता दिखाई है। खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय शिविरों के आयोजन, शिविर का बुनियादी ढांचा और उपकरण प्रदान करने, प्रशिक्षकों की नियुक्ति और खेल के बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) के लिए इस बजटीय आवंटन में 36.09 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। पिछले वर्ष के संशोधित व्यय 749.43 करोड़ रुपए के मुकाबले साल 2023-24 के लिए उनका आवंटन 785.52 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) को पिछले वर्ष के संशोधित बजट 280 करोड़ रुपए से 45 करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ आवंटन प्राप्त हुआ है और अब उन्हें 325 करोड़ रुपए मिलेंगे।

विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) से संबद्ध राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीएलटी) को पहले साइ के जरिए कोष मिलता था लेकिन अब ए संस्थाएं अपने रकम को सीधे प्राप्त करेगी। इस साल के बजट में नाडा को 21.73 करोड़ रुपए की धनराशि मुहैया कराने का प्रावधान है, जबकि डोप परीक्षण कराने वाले एनडीटीएल को 19.50 करोड़ रुपए मिलेंगे।

दुनिया भर के देश खेल उत्कृष्टता के लिए प्रयास कर रहे हैं और खिलाड़ियों के खेल विज्ञान और वैज्ञानिक प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में इस साल के बजट में राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र के लिए भी 13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

मध्यक्रम में अय्यर के स्थान के लिए गिल और सूर्यकुमार दावेदार

भाषा। नई दिल्ली

श्रेयस अय्यर के कमर की चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार टेस्ट की श्रृंखला के पहले मैच से बाहर होने के बाद भारतीय टीम प्रबंधन मध्यक्रम में सूर्यकुमार यादव पर शुभमन गिल को तरजीह देते हुए उन्हें खिलाने पर विचार कर सकता है। अय्यर कमर में जकड़न से उबरने में नाकाम रहे हैं और उनके बाहर होने से भारतीय मध्यक्रम में एक स्थान बनेगा। इस स्थान के दावेदार सूर्यकुमार और गिल हैं। सूर्यकुमार ने अपने करियर में मध्यक्रम में ही बल्लेबाजी की है जबकि गिल ने टेस्ट क्रिकेट में अधिकतर राष्ट्रीय टीम के लिए पारी का आगाज किया है। अपने संक्षिप्त टेस्ट करियर में अब तक लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले अय्यर ने पिछले साल दिसंबर में बांग्लादेश के खिलाफ श्रृंखला में 2-0 की जीत के दौरान भी शानदार प्रदर्शन किया था।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, न्यूजीलैंड की टीम जब 2021 के अंत में भारत आई थी तो मध्यक्रम में शुभमन गिल के नाम पर विचार किया गया था क्योंकि लोकेश राहुल को मयंक अग्रवाल के साथ पारी का आगाज करना था। इसके बाद राहुल चोटिल हो गए और गिल ने पारी का आगाज किया। इसके बाद वह चोबारा चोटिल हो गया। लाल गेंद के क्रिकेट में मध्यक्रम के लिए उसके नाम पर विचार हुआ था। कप्तान रोहित शर्मा और उप कप्तान राहुल टीम में सलामी जोड़ी के रूप में पहली पसंद हैं। इनके बाद तीसरे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा और चौथे नंबर पर विराट कोहली का खेलना तय है। पांचवां क्रम काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उम्मीद की जाती है कि इस क्रम पर उतरने वाला बल्लेबाज दूसरी नई गेंद का सामना करेगा। गिल के मामले में टेस्ट क्रिकेट में नियमित रूप से खेलने और लाल गेंद का करियर मध्यक्रम के बल्लेबाज के रूप में शुरू करने के कारण उनका पलड़ा भारी रहेगा। पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ता ने कहा, जब भारत ए की जिम्मेदारी राहुल द्रविड़ के हाथों में थी तो गिल वेस्टइंडीज के ए दौरे पर मध्यक्रम में खेले थे जहां उन्होंने एक दोहरा शतक भी जड़ा था। असल में शुरुआत में वह मध्यक्रम का बल्लेबाज था जिसे सलामी बल्लेबाज में बदला गया। स्पिन की अनुकूल पिचों पर स्पिनरों के खिलाफ सूर्यकुमार का दबदबा महत्वपूर्ण हो सकता है। उन्होंने कहा, अगर नाथन लियोन अपनी ऑफ स्पिन गेंदों को अधिक टर्न कराने में सफल रहते हैं तो सूर्यकुमार अपने फुटवर्क से उनकी लय बिगाड़ सकते हैं लेकिन पैट कमिंस और जोश हेजलवुड के खिलाफ गिल बेहतर विकल्प हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीमित ओवरों की घरेलू श्रृंखला से बाहर रहे अय्यर चोट से पूरी तरह नहीं उबर पाए हैं और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रिहैबिलिटेशन करा रहे हैं।

सूर्यकुमार आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार

दुबई। भारत के आक्रामक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की बुधवार को जारी नवीनतम टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं। रांची में न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में 47 रन की पारी की बदौलत उनके 910 रेटिंग अंक हो गए थे लेकिन श्रृंखला के दूसरे मैच में नाबाद 26 रन की पारी खेलने के बावजूद उनके अंकों की संख्या 908 रह गई। सूर्यकुमार पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजों में सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ रेटिंग अंक के इंग्लैंड के बल्लेबाज डेविड मलान के रिकॉर्ड के भी काफी करीब हैं। मलान ने 2020 में केपटाउन में 915 अंक हासिल किए थे।

सूर्यकुमार टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजों में सर्वाधिक रेटिंग अंक हासिल करने वालों की सर्वकालिक सूची में दूसरे स्थान पर हैं। पिछले साल टी20 विश्व कप में छह मैच में 239 रन जुटाकर सूर्यकुमार टी20 रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचे थे। इसके बाद उन्हें पिछले महीने आईसीसी का साल का सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर भी चुना गया। सूर्यकुमार के अलावा भारत का कोई अन्य बल्लेबाज या गेंदबाज शीर्ष 10 में शामिल नहीं है। ऑलराउंडर की सूची में हार्दिक पंड्या तीसरे स्थान पर हैं। मोहम्मद सिराज एकदिवसीय गेंदबाजों की सूची में शीर्ष पर बने हुए हैं।

सचिन ने विश्वकप विजेता टीम को सम्मानित किया

भाषा। अहमदाबाद

पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार आयोजित हुए अंडर-19 महिला आईसीसी टी20 विश्व कप की विजेता भारतीय क्रिकेट टीम को सम्मानित करते कहा कि इस उपलब्धि से कई लड़कियां खेल को अपनाने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित होंगी।

तेंदुलकर ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के इतर आयोजित इस सम्मान समारोह में कहा, मैं आपको शानदार उपलब्धि पर बधाई देना चाहता हूं। पूरा देश आने वाले वर्षों में (जीत का) जश्न मनाएगा। मास्टर ब्लास्टर ने कहा, मेरे क्रिकेट सपने की शुरुआत भारतीय टीम के 1983 में विश्व कप विजेता बनने से शुरू हुई थी। आपने भी कई नए सपनों को जन्म दिया है। यह शानदार उपलब्धि है। उन्होंने कहा, इस विश्व कप को जीतकर आपने भारत की युवा लड़कियों को देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना दिया है।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक जड़ने वाले इस पूर्व दिग्गज ने कहा, डब्ल्यूपीएल (महिला प्रीमियर लीग) की शुरुआत सबसे बड़ी चीज होने जा रही है। मैं पुरुषों और महिलाओं के लिए समानता में विश्वास करता हूं। खेलों में ही नहीं बल्कि हर जगह दोनों के पास समान अवसर होना चाहिए।

तेंदुलकर ने कहा कि बीसीसीआई देश में महिला क्रिकेट के विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा, बीसीसीआई और उसके अधिकारियों ने महिला क्रिकेट को समृद्ध बनाने में काफी योगदान दिया है। मुझे लगता है कि यह एक संकेत है कि हम वास्तव में अच्छा करेंगे (भविष्य में)। इस संक्षिप्त सम्मान समारोह में बीसीसीआई सचिव जय शाह, अध्यक्ष रोजर बिन्नी, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और कोषाध्यक्ष आशीष शेलार भी शामिल थे। इस मौके पर विश्व चैम्पियन अंडर-19 महिला टीम को पांच करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया जिसकी घोषणा बोर्ड सचिव ने पहले की थी।

नफरत और दुर्व्यवहार के कारण पाकिस्तान टीम को कभी कोचिंग देने के बारे में नहीं सोचा: अकरम

भाषा। कराची

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने कहा है कि देश में कोच और कप्तान की आलोचना, दुर्व्यवहार और नफरत के कारण उन्होंने राष्ट्रीय टीम को कोचिंग देने के बारे में कभी नहीं सोचा। अकरम ने यहां एक साक्षात्कार में कहा, अगर टीम अच्छा नहीं कर रही है तो मैं आलोचना स्वीकार कर सकता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट में हालांकि जिस तरह से कप्तान और कोचों की न केवल आलोचना की जाती है बल्कि सभी के द्वारा गाली-गलौज भी किया जाता है, वह असहनीय है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के क्रिकेट में कप्तान और कोच को दुर्व्यवहार और कभी-कभी जिस नफरत का सामना करना पड़ता है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए तैयार हूं। मुझमें सहनशीलता का वह स्तर नहीं है, खासकर जब सोशल मीडिया के उपयोग की बात आती है। कई ऐसे लोग है जिनका काम सिर्फ नकारात्मक टिप्पणियां करना है। उन्होंने इस मौके पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) से बाबर आजम को कप्तान के पद से नहीं हटाने की मांग की।इस पूर्व कप्तान ने कहा, मुझे लगता है कि यह एक गलती होगी। क्योंकि अगर आप उन्हें किसी भी प्रारूप में कप्तान के रूप में बदलते हैं तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा, इस मामले में हमारे पास विकल्प क्या हैं? अगर हम सब समर्थन करें तो यह सबसे अच्छा विकल्प होगा। वह युवा है और कप्तान के तौर पर वह और बेहतर होगा। मेरी सोच है कि कोई भी जन्मजात कप्तान और नेता नहीं होता, ये चीजें समय और अनुभव के साथ आती हैं।

आंध्र ने बनाए 379 रन, मप्र के चार विकेट पर 144 रन

भाषा। इंदौर

रणजी ट्रॉफी

आंध्र के कप्तान हनुमा विहारी ने बाएं हाथ में चोट के बावजूद इसी से बल्लेबाजी करते हुए आवेश खान की तेज गेंदबाजी का डटकर सामना किया और बुधवार को यहां रणजी ट्राफी क्वार्टरफाइनल मैच के दूसरे दिन 10वें विकेट के लिए 26 रन जोड़कर मध्य प्रदेश के खिलाफ 379 रन बनाने में मदद की। आंध्र ने फिर गत चैम्पियन मध्य प्रदेश के स्टंप तक 144 रन तक चार विकेट झटककर मैच पर नियंत्रण बना लिया था। दो विकेट पर 262 रन के स्कोर से आगे खेलते हुए आंध्र की टीम के लिए चीजें उसके अनुरूप नहीं रहीं और मध्य प्रदेश के गेंदबाजों ने रिकी भुई (149 रन) और करण शिंदे (110 रन) के बीच 251 रन की विशाल साझेदारी के दौरान जूझने के बाद वापसी की। शिंदे ने 254 रन गेंद में अपना शतक पूरा किया जबकि भुई ने घरेलू टीम के गेंदबाजी आक्रमण को हताश करना जारी रखा। मध्यम गति के गेंदबाज अनुभव अग्रवाल (72 रन देकर चार विकेट) ने इस भागीदारी का अंत किया। शिंदे इस गेंदबाज की गेंद पर बल्ला छुआकर विकेटकीपर हिमांशु मंत्री को कैच दे बैठे और इस समय टीम का स्कोर 323 रन था। पांच रन बाद भुई की मैराथन पारी अग्रवाल की गेंद पर सारांश जैन के कैच लेने से समाप्त हुई। मध्य प्रदेश के गेंदबाजों ने फिर लगातार अंतराल पर विकेट झटके और जब आंध्र का स्कोर नौ विकेट पर 353 रन था तब विहारी बल्लेबाजी के लिए उतरे। बाएं हाथ की कलाई चोटिल होने के बाद बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हुए आंध्र के कप्तान ने दो बाउंड्री लगाकर टीम को 379 रन तक पहुंचाया। उन्होंने केवल एक हाथ से बल्लेबाजी की। जैन ने उन्हें 27 रन के निजी स्कोर पर पगबाधा आउट किया। वह मंगलवार को 16 रन के स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट हुए थे जब आवेश खान के बाउंसर से वह चोटिल हो गए। विहारी की इस साहसिक पारी ने जनवरी 2021 में आस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट में उनकी शानदार पारी याद दिला दी जब हैमस्ट्रिंग चोट के बावजूद रविचंद्रन अश्विन के साथ उन्होंने आस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का चार घंटे तक डटकर सामना किया और प्रतिद्वंद्वी टीम को जीत से वंचित कर दिया। इसके बाद मध्य प्रदेश ने सलामी बल्लेबाज मंत्री और यश दूबे के बीच पहले विकेट के लिए 42 रन की साझेदारी से मजबूत शुरूआत की। केवी शशिकांत (37 रन देकर दो विकेट) ने आंध्र को पहला विकेट दूबे के रूप में दिलाया।

साथी सलामी बल्लेबाज मंत्री को पृथ्वी राज (सात रन देकर एक विकेट) ने आउट किया। शुभम शर्मा (51 रन) और फॉर्म में चल रहे रजत पाटीदार (20 रन) ने तीसरे विकेट के लिए 42 रन जोड़े।

पंजाब ने सौराष्ट्र के खिलाफ बनाई बढ़त

भाषा। राजकोट

सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह और नमन धीर की शतकीय पारियों और दोनों के बीच शुरुआती विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी से पंजाब ने रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सौराष्ट्र के खिलाफ दूसरे दिन बुधवार को यहां स्टंप्स तक पांच विकेट पर 327 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। नमन ने 180 गेंद की पारी में नौ चौके और सात छक्के की मदद से 131 रन बनाए जबकि प्रभसिमरन ने 158 गेंद में 126 रन की पारी के दौरान 13 चौके और तीन छक्के जड़े। सौराष्ट्र ने अपनी पहली पारी में 303 रन बनाए थे जिससे पंजाब के पास अब 24 रन की बढ़त है और उसके पांच विकेट बाकी है।

दिन का खेल खत्म होते समय कप्तान मंदीप सिंह 39 और विकेटकीपर अनमोल मल्होत्रा 16 रन बनाकर खेल रहे थे। दिन की शुरुआत बिना किसी नुकसान तीन रन पर करने के बाद प्रभसिमरन और नमन ने पंजाब को शानदार शुरुआत दिलाई और लंच से पहले विरोधी टीम के गेंदबाजों को सफलता से दूर रखा। लंच के बाद हालांकि गेंदबाजों ने सौराष्ट्र की वापसी कराई। सौराष्ट्र के लिए शतक लगाने वाले पार्थ भट ने प्रभसिमरन को आउट कर टीम को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए पुखराज मान (एक) भी जल्दी पवेलियन लौट गए। नमन को इसके बाद कप्तान मंदीप का अच्छा साथ मिला लेकिन उनके आउट होने के बाद पंजाब ने जल्दी जल्दी अनमोलप्रीत सिंह (नौ रन) और नेहा ल वडेरा (चार रन) के विकेट गंवा दिए। सौराष्ट्र के लिए धर्मेंद्रसिंह जडेजा और युवराजसिंह डोडिया ने दो-दो विकेट लिए। पार्थ को एक सफलता मिली।

पश्चिम बंगाल ने पहली पारी की बढ़त हासिल की

भाषा। कोलकाता

कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन और सुदीप घरामी के अर्धशतकों से बंगाल ने बुधवार को यहां रणजी ट्राफी क्वार्टरफाइनल के दूसरे दिन झारखंड के खिलाफ पहली पारी के आधार पर बढ़त हासिल कर ली।

झारखंड को 173 रन पर समेटने के बाद बंगाल ने दूसरे दिन स्टंप तक पांच विकेट पर 238 रन बनाकर पहली पारी में 65 रन की अहम बढ़त हासिल की। सलामी बल्लेबाज काजी जुनैद सैफी (01 रन) नौंवे ओवर में आशीष कुमार की गेंद पर पगबाधा आउट हुए। जिसके बाद अभिमन्यु (77 रन) और घरामी (68 रन) ने बल्ले से दमदार प्रदर्शन किया। अभिमन्यु और घरामी ने दूसरे विकेट के लिए 136 रन जोड़कर घरेलू टीम को पहली पारी की बढ़त हासिल करने के करीब पहुंचा दिया। लेकिन इन दोनों के लगातार आउट होने के बाद टीम ने 60 रन जोड़कर चार विकेट गंवा दिए जिससे टीम का स्कोर पांच विकेट पर 207 रन हो गया। पर फिर अभिषेक पोरेल (25 रन) और शाहबाज अहमद (17 रन) ने पारी को संभालते हुए नाबाद साझेदारी निभा ली है। झारखंड के सुप्रियो चक्रवर्ती ने दो जबकि आशीष, अनुकूल रॉय और शाहबाज नदीम ने एक एक विकेट हासिल किए।

कर्नाटक ने उत्तराखंड पर कसा शिकंजा

बेंगलुरु। हरफनमौला श्रेयस गोपाल की नाबाद 103 रन की पारी के दम पर कर्नाटक ने रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उत्तराखंड के खिलाफ बुधवार को दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पांच विकेट पर 474 रन बनाकर पहली पारी में बड़ी बढ़त कायम कर ली। उत्तराखंड की पहली पारी महज 116 रन पर सिमट गई थी जिससे कर्नाटक के पास अब 358 रन की बड़ी बढ़त है और उसके पांच विकेट बचे हुए है। कर्नाटक की टीम ने दिन की शुरुआत बिना किसी नुकसान के 123 रन से की। कप्तान मयंक अग्रवाल (83)और रविकुमार समर्थ (82) शतक पूरा करने से चूक गए लेकिन दोनों ने पहले विकेट के लिए 159 रन की साझेदारी कर बड़े स्कोर की नींव रखी। इन दोनों के पवेलियन जाने के बाद निकिन जोस (62) और देवदत्त पडिक्कल (69) ने तीसरे विकेट के लिए 118 रन की साझेदारी कर टीम के स्कोर को 300 रन तक पहुंचाया। श्रेयस गोपाल और मनीष पांडे (39) ने इसके बाद टीम के लिए पारी की तीसरी शतकीय साझेदारी की। दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 108 रन जोड़े। श्रेयस गोपाल ने इस दौरान प्रथम श्रेणी क्रिकेट का पांचवां शतक जड़ा और 3000 रन के आंकड़े को पार किया।

उन्होंने 153 गेंद की नाबाद पारी में 13 चौके और एक छक्का लगाया। इस दौरान मयंक मिश्रा ने 31 रन देकर तीन विकेट लिए। उनके अलावा उत्तराखंड का कोई भी गेंदबाज प्रभावी नहीं दिखा। अभय नेगी ने 82 रन देकर दो विकेट चटकाए। स्टंप्स के समय श्रेयस गोपाल के साथ विकेटकीपर बी आर शरत क्रीज पर मौजूद थे। शरत 23 रन पर खेल रहे है।

दोनों ने छठे विकेट के लिए अब तक 59 रन की अटूट साझेदारी कर ली है।